चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

13 अक्टूबर–19 अक्टूबर 2014

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

जया के बाद माया पर छाया

पेज-03

बहुकोणीय मुकाबले में किसे होगा फायदा

पेज-04

मांझी-मंदिर प्रकरण और सुलगते सवाल

पेज-05

साई की महिमा

पेज-12

आईएसआईएस का भारत पर ख़तरा

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

भारत पर स्पष्ट और आसन्न ख़तरा मंडरा रहा है. आईएसआईएस की गहरी साजिश से देश को सावधान रहना होगा. जिस तरह इराक में अल-बगदादी और आईएसआईएस के आतंकी शियाओं का ख़ात्मा कर रहे हैं, वही खेल यह संगठन भारत में भी खेलना चाहता है. वैसे, देश के मुसलमानों ने बगदादी की अपील खारिज कर दी है, लेकिन आशंका यह है कि पैसे लेकर या भाड़े के कुछ लोग उसकी साजिश में शामिल न हो जाएं और एक ऐसी साजिश को अंजाम दें, जिससे देश में हिंसा भड़क उठे. आशंका यह भी जताई जा रही है कि इस मोहर्रम में आईएसआईएस की पूरी कोशिश होगी कि देश में शिया और सुन्नी के बीच हिंसा भड़के. मोहर्रम के दौरान सरकार को सचेत रहना होगा और शिया धर्मगुरुओं की सुरक्षा पर नज़र रखनी होगी, क्योंकि चौथी दुनिया के पास कुछ ऐसी जानकारी है, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे.

मनीष कुमार

मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी, हिंदुस्तान के शिया धर्मगुरुओं में सबसे जाना-पहचाना नाम है. वह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं. वह देश की सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में देश के किसी भी मौलाना से ज़्यादा मुखर हैं. वह कभी बाबा रामदेव के मंच से रामलीला मैदान में भाषण देते हैं, कभी देश में घूम-घूम कर लोगों को एकता का पाठ पढ़ाते हैं, तो कभी अन्ना हजारे के मंच से भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ लड़ते दिखाई पड़ते हैं. टीवी पर होने वाली बहसों में वह शियाओं के सबसे विश्वसनीय प्रवक्ता हैं. वैसे, कहना तो यह चाहिए कि मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी शिया धर्मगुरु तो हैं ही, लेकिन उनके चाहने वालों में सभी धर्मों के लोग हैं. कुछ दिनों पहले वह दिल्ली के लक्ष्मी नगर में थे. वह कार में बैठे थे. आगे ड्राइवर बैठा था. एक साथी सामने की दुकान से कुछ खरीदने गया हुआ था. अचानक से एक व्यक्ति ड्राइवर से खिड़की के शीशे को नीचे करने के लिए कहता है, साथ ही सड़क के उस पार से तीन-चार लोग कार की तरफ़ दौड़ते हुए आ रहे थे. ड्राइवर ने उन्हें देख लिया. ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ा दी. वह वहां से निकल गए. सवाल यह है कि उक्त लोग कौन थे? क्या वे मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी पर हमला करने आए थे? उनकी मंशा क्या थी? इन सवालों के जवाब मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी के साथ घट रही घटनाओं से मिल जाते हैं.

यह कहानी क़रीब छह महीने पहले से शुरू होती है. मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी उन दिनों अमरोहा में चुनाव प्रचार में जुटे थे. वह आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे. उस वक्त कुछ लोग एसएमएस और फोन पर ऑडियो-वीडियो मैसेज के प्रचार-प्रसार के लिए पैकेज बेचने आए. उसी दौरान एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई. सुरक्षा का ख्याल रखते हुए हम उसका असली नाम नहीं बता रहे हैं. इसलिए इस रिपोर्ट में हम उस शख्स को एक काल्पनिक नाम रमेश दे रहे हैं. चुनाव प्रचार के दौरान मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी को अपने फोन पर ई-मेल या मैसेज सही तरीके से नहीं मिल पा रहे थे. रमेश से बातचीत के दौरान उन्हें लगा कि वह फोन का जानकार है, तो उन्होंने अपनी यह समस्या उसे बता दी. रमेश ने कहा कि इसे ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा. इतना कहकर वह चला गया. एक-दो दिन के बाद वह लौटा और उसने मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी से पूछा कि आपका ई-मेल कितनी जगहों पर कन्फीगर किया हुआ है. मतलब यह कि उनका मेल किन-किन फोन और कंप्यूटर पर खुलता है. मौलाना साहब ने कहा कि एक उनके फोन पर, दूसरा उनकी बेटी के फोन पर और शायद दिल्ली के ऑफिस में उनका ई-मेल खोला जाता है. उन्होंने कहा कि यही कोई तीन या चार जगहों पर यह मेल खुलता है. यह सुनकर रमेश ने जवाब दिया कि नहीं, आपका मेल कम से कम सात जगहों पर खोला जाता है. सात जगहों पर लगातार आपके मेल को पढ़ा जा रहा है. मतलब यह कि जो मेल मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी के पास आ रहा है, वह एक ही साथ सात अलग-अलग फोन या कंप्यूटरों पर भी जा रहा है. मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी के होश उड़ गए. अब सवाल यह है कि मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी के मेल के जरिये उनकी जासूसी कौन कर रहा था? उसका क्या मकसद था? वे कौन लोग थे, जिन्हें मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी के ई-मेल की ज़रूरत पड़ गई?

मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी को शायद पता नहीं था कि वह एक ऐसी साजिश के मोहरे बन चुके हैं, जिसके तार आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं. रमेश ने कहा कि वह कुछ ही दिनों में बता देगा कि उनके ई-मेल की जासूसी कौन कर रहा है. एक दिन बाद रमेश ने फोन करके मौलाना साहब को बताया कि उनका ई-मेल एक ऐसे फोन पर खोला जा रहा है, जो विदेश में है. वह व्यक्ति कौन है, कहां है, इसका पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हर घंटे उसकी लोकेशन बदल जाती है. रमेश ने बताया कि यह किसी शातिर व्यक्ति का फोन है, क्योंकि वह एक घंटे पहले अमेरिका में होता है, तो आधे घंटे बाद किसी दूसरे देश में उसके फोन की लोकेशन मिलती है. साधारण तौर पर किसी भी मोबाइल की लोकेशन उसके आईपी से पता चल जाती है. जो भी मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा होता है, उसके नज़दीकी टेलीफोन टावर से उसका पता लगाया जा सकता है. लेकिन, इस फोन की कहानी कुछ और थी. फोन जिसके पास था, वह टेलीफोन की मूलभूत तकनीक को झांसा देने में उस्ताद था. इसलिए हर आधे या एक घंटे में वह अपनी लोकेशन बदल देता था. वह अपनी लोकेशन को पूरी तरह से छिपाने में माहिर है. अब सवाल यह है कि आख़िर वह शख्स कौन है, जिसे अपनी लोकेशन छिपाने की ज़रूरत पड़ रही है. मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी को रमेश ने बताया कि वह पता करने की कोशिश कर रहा है कि आख़िर इस मोबाइल फोन का मालिक कौन है.

रमेश ने जब इस बारे में तहकीकात की, तो पता चला कि यह फोन उस्मान मलिक का है. अब सवाल है कि यह उस्मान मलिक कौन है? एक उस्मान मलिक तो वह है, जिसे आतंकवाद के मामले में ब्रिटेन की अदालत ने तीन साल के लिए जेल भेजा था. ऐसा भी हो सकता है कि यह वह उस्मान मलिक न हो. यह भी हो सकता है कि उस्मान मलिक एक फर्जी नाम हो.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

आईएसआईएस की गतिविधियां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही यह कह दिया हो कि भारत के मुसलमान अलकायदा को सबक सिखाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अलकायदा या आईएसआईएस जैसे संगठनों ने भारत में अपनी गतिविधियां ख़त्म कर दी हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईएसआईएस के भारतीय मूल के दो आतंकी लोगों को संगठन में शामिल करने का काम कर रहे हैं. इसमें जो खुलासे हुए हैं, वे चौंकाने वाले हैं. हैदराबाद निवासी इंजीनियरिंग के चार छात्रों को पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार किया गया, जो देश की सरहद को पार कर आतंकी संगठन में शामिल होने जा रहे थे. जयपुर में भी जो लोग पकड़े गए, वे भी इंजीनियरिंग के छात्र हैं. हाल में ही ख़बर आई है कि अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी गुट अलकायदा ने मणिपुर के 17 लड़कों को दक्षिण एशिया में जिहाद के नाम पर भर्ती किया है. हालांकि, भारत में इस आतंकी गुट की नापाक साजिश को उस वक्त गहरा आघात लगा, जब इनमें से 4 लड़के पाकिस्तानी ट्रेनिंग कैंप से बचकर वापस आ गए. इन लड़कों ने खुफिया एजेंसी को जानकारी दी है कि वहां बचे 13 लड़के भी वापस आना चाहते हैं. इस सूचना के बाद गृह मंत्रालय ने अलकायदा और इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया (आईएसआईएस) के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. ख़बर यह भी आई है कि दक्षिण एशिया में अपने संगठन को मजबूत करने और लड़कों की भर्ती संबंधी जारी की गई सीडी असली है. सूत्रों के मुताबिक, भारत में गजबा-ए-हिंद और बैटल ऑफ खुरसान नामक दो सक्रिय संगठनों का पता चला है, जो उत्तर-पूर्व के राज्यों से लड़कों को भर्ती करने की योजना पर काम कर रहे हैं. ■

आईएसआईएस का भारत पर ख़तरा

पृष्ठ एक का शेष

यह फोन किसी और का हो, जो उस्मान मलिक बनकर बात करता हो या उसने इस नाम से सिम खरीदा हो. जो भी हो, अगर एक व्यक्ति अपने मोबाइल में आईपी जम्पर लगाकर अपना ठिकाना छिपाने की कोशिश कर रहा हो, किसी दूसरे के मेल आईडी की निगरानी कर रहा हो, तो इसका साफ़ मतलब है कि उसका रिश्ता ज़रूर किसी ऐसे गैंग या संगठन से है, जो ग़ैरक़ानूनी काम करता है. आतंकी का नाम सुनते ही मौलाना रिजवी के होश उड़ गए. फिर उन्होंने अपने एक मित्र से बात की और खुफिया एजेंसियों को यह बात बताई. शुरुआती तहकीकात से पता चला कि ई–मेल का यह खेल कोई साधारण खेल नहीं, बल्कि एक पूरी योजना के तहत किया जा रहा है. खुफिया एजेंसी के लोगों ने इस गैंग की गतिविधियों पर अपनी नज़रें गड़ा दीं, तहकीकात की. भारत में इस गैंग में शामिल लोगों की पहचान भी हुई. सूत्र बताते हैं कि राजस्थान के सूरतगढ़ में इस गैंग से जुड़े पांच लोगों की पकड़–धकड़ हुई. वे लोग कौन थे? खुफिया एजेंसी उन्हें कहां लेकर गई? उन्हें क्यों पकड़ा गया? इन सारे सवालों का जवाब देश की खुफिया एजेंसी ही दे सकती है.

लेकिन, सवाल मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी का है. वह एक हाई–प्रोफाइल टारगेट हैं. अगर आईएसआईएस या अल–बगदादी इराक की तरह भारत में भी शिया–सुन्नी के बीच जंग छिड़वाना चाहता है, तो मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी जैसी हस्तियों की हत्या लोगों की भावना भड़काने के लिए काफी है. आतंकवादी संगठनों एवं आतंकवादियों का न कोई धर्म होता है और न उन्हें इंसानियत से मुहब्बत होती है. वे पैसों और सत्ता के लालच में मासूमों, बेगुनाहों का खून बहाने वाले दानव होते हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अल–बगदादी ने यह योजना बना ली है, तो इसे अंजाम देने के लिए उसके पास पैसों की कमी नहीं है. भारत में अल–बगदादी को भले ही किसी मुसलमान का साथ न मिले, किसी सुन्नी का साथ न मिले, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि कोई पैसे लेकर उसके बहकावे में नहीं आएगा? पैसों का लालच तो लालच ही है. उसका किसी धर्म से कोई सरोकार नहीं है. लालच की चपेट में आने वाला व्यक्ति मुस्लिम भी हो सकता है और हिंदू भी उसी लालचवश इस काम को अंजाम दे सकता है.

अबु बक्र अल–बगदादी ने जब खुद को ख़लीफ़ा घोषित किया और इराक को एक इस्लामिक स्टेट बताया, तो उसी सांस में उसने भारत के मुसलमानों से यह अपील की थी कि वे भी उसकी लड़ाई में शामिल हों. बगदादी को शायद हिंदुस्तान की समझ नहीं है, क्योंकि जो लोग हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझते हैं, वे इस बात को भलीभांति जानते हैं कि ऐसी किसी भी अपील का असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर नहीं पड़ने वाला है. हिंदुस्तान के मुसलमान अब तक अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क में शामिल नहीं हुए और वे हिंसा की हमेशा भर्त्सना करते रहे हैं. अल–बगदादी ने जब खुद को ख़लीफ़ा घोषित किया था, तब कुछ मौलवियों ने सही जानकारी के अभाव में उसे समर्थन दे दिया था. देश का माहौल बिगड़ा, कुछ शिया मौलानाओं की तरफ़ से भी बयानबाजी हुई. लेकिन, यह कहना पड़ेगा कि भारत के मुसलमानों ने अल–बगदादी की अपील को न सिर्फ़ नकारा, बल्कि उसकी और उसके समर्थकों की जमकर निंदा की. हालांकि, कुछ युवा भ्रमित होकर इराक जाकर लड़ने की बात करने लगे थे. बस ख़तरा इसी बात से है कि कहीं आईएसआईएस पैसे देकर या बहला–फुसला कर एक–दो लोगों को अपनी साजिश का मोहरा न बना ले. लेकिन, जैसे–जैसे अल–बगदादी और आईएसआईएस के दानवी कृत्यों की ख़बरें आने लगीं, तो जो एक–आध समर्थन था, वह भी चला गया. जिन लोगों ने बयान दिए थे, उनका मखौल उड़ने लगा. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आईएसआईएस या अलकायदा के मंसूबों में कोई कमी आई है.

अबु बक्र अल-बगदादी ने जब खुद को ख़लीफ़ा घोषित किया और इराक को एक इस्लामिक स्टेट बताया, तो उसी सांस में उसने भारत के मुसलमानों से यह अपील की थी कि वे भी उसकी लड़ाई में शामिल हों. बगदादी को शायद हिंदुस्तान की समझ नहीं है, क्योंकि जो लोग हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझते हैं, वे इस बात को भलीभांति जानते हैं कि ऐसी किसी भी अपील का असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर नहीं पड़ने वाला है.

बगदादी और उसके संगठन आईएसआईएस ने जो इस्लामिक राज्य का नक्शा जारी किया, उसमें हिंदुस्तान भी शामिल है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, आईएसआईएस भारत में आतंकियों की टुकड़ी तैयार कर रहा है. इसमें यह बताया गया है कि कुछ भारतीय आतंकी भारत लौटकर यहां आईएसआईएस की गतिविधियों को अंजाम देंगे. दरअसल, भारत दुनिया का दूसरा ऐसा देश है, जहां जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा शिया मुसलमान रहते हैं. आईएसआईएस इराक में शियाओं के ख़िलाफ़ हिंसा कर रहा है. सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को यह सुझाव दिया है कि आईएसआईएस और अलकायदा की मध्य एशिया में चल रही गतिविधियों पर चिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आईएसआईएस साउथ एशिया के लिए एक ख़तरा बनकर उभर रहा है. सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को यह भी जानकारी दी है कि आईएसआईएस और अल–बगदादी ने इराक और सीरिया में लड़ रहे भारतीय आतंकियों को वापस भारत लौटकर भारत में अपनी गतिविधियां जारी रखने की ज़िम्मेदारी सौंपी है. जानकारों की मानें, तो आईएसआईएस अब तक का सबसे अमीर, संगठित और प्रशिक्षित आतंकी संगठन है. उसके पास अकूत पैसा और हथियार हैं. इसलिए आईएसआईएस की क्षमता को कम आंकना भारत की सबसे बड़ी भूल होगी. इसमें कोई शक नहीं है कि आईएसआईएस हरसंभव कोशिश करेगा कि वह भारत में अपनी पैठ जमाए.

शियाओं का सबसे महत्वपूर्ण पर्व मोहर्रम कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है. शियाओं के लिए यह मातम मानने का मौक़ा है. कई जगहों पर वे इकट्ठा होते हैं, धार्मिक जलसों में शामिल होते हैं और फिर ताजिए निकलते हैं. कहने का मतलब, किसी भी आतंकी संगठन के लिए यह सबसे सुविधाजनक मौक़ा है. इस दौरान फेंकी गई जरा–सी चिंगारी को जंगल की आग की शक्ल लेने में जरा भी देर नहीं लगेगी. इसलिए सरकार को चाहिए कि वह सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को इस ख़तरे से आगाह रखे. यह इसलिए भी ज़रूरी है कि मोहर्रम के दौरान ही सही ढंग से पता चलेगा कि आईएसआईएस भारत को लेकर जो कुछ कहता है, उसमें कितना दम है. दम है भी या नहीं. या फिर वह सिर्फ़ सीडी और वीडियो के जरिये अपनी दुकान चलाने के लिए महज हवाई किले बनाता रहता है. यह भी पता चल जाएगा कि उसकी आवाज़ को कोई सुनने वाला भारत में है भी या नहीं. ■

manishbph244@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 06 अंक 32
दिल्ली, 13 अक्टूबर–19 अक्टूबर 2014
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना–800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

मध्यरात्रि में स्थानांतरण

नरेंद्र मोदी सरकारी विभागों में सफाई के काम में जुटे हुए हैं. केंद्र सरकार ने अचानक उत्तर प्रदेश, बिहार एवं तमिलनाडु के अतिरिक्त और संयुक्त सचिव स्तर के 50 अधिकारियों का अचानक स्थानांतरण कर दिया. यह क़दम रातोंरात इस तरह उठाया गया कि कई नौकरशाह तो इससे बिल्कुल अनजान थे. हालांकि, सरकार ने इसे नियमित तौर पर होने वाली गतिविधि बताया है. पर्यवेक्षकों का कहना है कि सरकार ने यह क़दम नौकरशाही को यूपीए के साये से दूर करने के लिए उठाया है. यह इस वजह से भी आश्चर्य चकित करने वाला क़दम है, क्योंकि नौकरशाही पर नज़र रखने वाले बहुत–से लोग मान रहे थे कि विभिन्न महकमों में मामूली हेरफेर होगी. उन्हें भी 50 अधिकारियों के एकमुश्त स्थानांतरण की उम्मीद नहीं थी. इस सूची में आईएस चंदेल, राकेश कुमार सिंह, यूएस कुमावत, एम अरिज़ अहमद, प्रवीण प्रकाश एवं अन्य जाने–माने नौकरशाहों के नाम शामिल हैं. यह सही है, तो मोदी सरकार जाहिर तौर पर सुशासन के लिए समर्पित है. बाबुओं को भी इस बात की भनक नहीं है कि अगला अधिकारी कहां से आ रहा है! ■

अखिलेश काम पर

हाल में संपन्न उपचुनाव में लोगों की आशाओं से उलट आठ सीटों पर जीत हासिल करके समाजवादी पार्टी उत्साह से सराबोर है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रशासन की धूमिल छवि सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया है. और, इस दिशा में मुख्यमंत्री की नज़र खासकर उन नौकरशाहों पर है, जिनके पास सरकार के बड़े प्रोजेक्ट्स की ज़िम्मेदारी है. लखनऊ के इमामबाड़ा कॉम्पलेक्स के सौंदर्यीकरण की महत्वाकांक्षी योजना में देरी करने की वजह से हाल में अखिलेश यादव ने दो नौकरशाहों संजीव शरण एवं सदाकांत का स्थानांतरण कर दिया. सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने तीन अन्य नौकरशाहों से उनसे संबंधित विभागों में होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों की जानकारी न देने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है. संजीव शरण मुख्य सचिव–बुनियादी ढांचा और औद्योगिक विकास विभाग के पद पर तैनात थे. उन्हें नीदरलैंड के व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल के दौरे के दो दिनों बाद ही पद से हटा दिया गया और देवीपाटन के आयुक्त पद पर भेज दिया गया, जो प्रदेश का सबसे पिछड़ा मंडल है. इसी तरह सदाकांत, जो आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत थे, उन्हें बस्ती मंडल का आयुक्त बना दिया गया. इन नौकरशाहों के उत्तराधिकारियों के नाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं. बस्ती और देवीपाटन मंडल के आयुक्तों, एसके श्रीवस्तव एवं आरपी अरोरा के नाम अगले आदेश तक प्रतीक्षा सूची में डाल दिए गए हैं. ■

अधिक सुरक्षित नहीं

नौकरशाहों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार का मुक़दमा चलाने से बचाने वाले प्रावधानों से धीरे–धीरे परत हट रही है. मद्रास हाईकोर्ट ने हाल में एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जांच एजेंसियों को भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे आईएएस अधिकारियों के ख़िलाफ़ जांच और कार्रवाई करने के लिए उनके गृह राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है. भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अधिकारियों के ऊपर इस रूलिंग का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. अदालत ने 1982 बैच एवं मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी के सुरेश की याचिका खारिज कर दी, जो वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम के जोनल मैनेजर के रूप में चेन्नई में पदस्थ हैं और उन पर आय से ज़्यादा संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. उक्त नौकरशाह ने इस संबंध में तर्क देते हुए कहा कि सीबीआई, जिसने उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज किया है, उसे जांच करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से अनुमति लेनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दी गई जांच की अनुमति नियम विरुद्ध है. लेकिन, अदालत ने इन दलीलों को दरकिनार करते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी. ■

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

रवींद्र गृह मंत्रालय से जुड़े

1981 बैच एवं हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी रवींद्र कुमार जैन को गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में सचिव (अतिरिक्त सचिव के समकक्ष) नियुक्त किया गया है. वह 1980 बैच एवं आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी सत्य नारायण मोहंती का स्थान लेंगे, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव नियुक्त किए गए हैं.

कृष्णा सहायक आयुक्त बने

2012 बैच एवं एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी अरावा गोपी कृष्णा को अंडमान (डीपीटी) के अंतर्गत डिगलीपुर का सहायक आयुक्त बनाया गया है.

पाठक संयुक्त सचिव होंगे

1990 बैच एवं बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी केशव कुमार पाठक कश्मीर के संयुक्त सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे. वह वर्तमान में गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वतंत्रता सेनानी प्रकोष्ठ के संयुक्त सचिव हैं.

सुरेंद्र मध्य प्रदेश के नए डीजीपी

1980 बैच एवं मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र सिंह को पुलिस महानिदेशक–मध्य प्रदेश नियुक्त किया गया है.

अभय बीपीआर एंड डी जाएंगे

1986 बैच एवं ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी अभय भारत सरकार से जल्द ही जुड़ सकते हैं. वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत महानिरीक्षक के रूप में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में कार्यभार संभाल सकते हैं. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सीबीआई की जांच–पड़ताल में मायावती और उनके कुनबे की कई सौ करोड़ से अधिक की चल–अचल संपत्तियों का पता चला था. ताज कॉरिडोर को लेकर मायावती के ख़िलाफ़ 18 जुलाई, 2003 को विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ था. सीबीआई को जांच पड़ताल में मिले सबूतों के आधार पर 5 अक्टूबर, 2003 को आरसी नंबर 19–ए के तहत आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभियोग दर्ज किया गया था. राजनीतिक सौदेबाजी और दबाव के चलते तब सीबीआई ऐसा कुछ खास नहीं जुटा पाई. सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी 17 करोड़ रुपये पर सवाल उठाया, जिनका पता नहीं चला कि वे कहां चले गए.

आय से अधिक संपत्ति का प्रेत जया के बाद माया पर छाया

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की आय से अधिक संपत्ति उनके लिए विपत्ति का कारण बनी और उन्हें जेल जाना पड़ा. जयललिता के ख़िलाफ़ अदालत के इस रुख से अब मायावती की जान आफत में है. मायावती की अकूत संपत्ति भी अदालत की निगाह में है, इसीलिए सीबीआई की टालमटोल के बावजूद मामला टलता नहीं दिख रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर ही रखा है. दूसरी तरफ़ मुलायम सिंह भी सीधे नहीं, तो घुमा-फिराकर इसकी परिधि में आ रहे हैं. जयललिता के आय से अधिक संपत्ति मामले में अदालत का फ़ैसला न केवल मायावती, बल्कि देश भर के सियासतदानों को हतप्रभ और सतर्क करने वाला है.

प्रभात रंजन दीन

जयललिता के ख़िलाफ़ अदालत का फ़ैसला आने के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति के शीर्ष गलियारे में गंभीरता छाई हुई है. दूसरी तरफ़ आम लोगों में इस मसले पर चर्चा तेज हो गई है. सबको मालूम ही है कि मायावती के आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच में सीबीआई ने किस तरह कोताही की और मामला राजनीतिक दबाव और क़ानूनी उपेक्षा के कारण ठोस शक्ल नहीं ले सका. लेकिन, पिछले दिनों से यह फिर से सुगबुगाने लगा. अब जयललिता प्रकरण में फ़ैसला आ जाने के बाद इसका तेज होना सुनिश्चित है. जयललिता मसले पर फ़ैसला आने से कुछ दिनों पहले ही मायावती और सीबीआई, दोनों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की तरफ़ से नोटिस जारी हो चुका था. सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर बसपा प्रमुख मायावती और सीबीआई को नोटिस जारी कर रखा है. याचिका में मायावती के आय से अधिक संपत्ति मामले में नए सिरे से एफआईआर दर्ज करने और इसकी जांच कराने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तकनीकी आधार पर अदालत की ओर से एफआईआर रद्द किए जाने के बाद सीबीआई को अदालत से उपयुक्त सलाह लेनी चाहिए थी. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कमलेश वर्मा की याचिका पर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी कर रखा है. पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और सीबीआई सहित सभी पक्षकारों को चार हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दे रखा है.

सुप्रीम कोर्ट ने मायावती की तरफ़ से बहस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एवं बसपा नेता सतीश चंद्र मिश्र की उन दलीलों को दरकिनार कर दिया, जिनमें कहा गया था कि यह राजनीति से प्रेरित है. पीठ ने परोक्ष रूप से अपने 2012 के फ़ैसले का हवाला दिया, जिसमें तकनीकी आधार पर मायावती के ख़िलाफ़ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से जुड़ा मामला खारिज कर दिया गया था. उस फ़ैसले में सीबीआई के समक्ष मायावती के ख़िलाफ़ ताजा मामला दर्ज करने का विकल्प खुला रखा गया था, लेकिन सीबीआई ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि अदालत का काम हरेक बिंदु पर आदेश जारी करना नहीं है. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2012 के फ़ैसले में मायावती के ख़िलाफ़ नौ साल पुराने आय से अधिक संपत्ति मामले को इस आधार पर खारिज किया था कि सीबीआई ने 2003 के उसके आदेश को बिना ठीक ढंग से समझे ही आगे बढ़ा दिया और आय से अधिक संपत्ति की जांच को ताज कॉरिडोर प्रकरण से जुड़ा रखा, जो महज 17 करोड़ रुपये की अनियमितता से जुड़ा है. सीबीआई ने आय से अधिक संपत्ति मामले की व्यापकता को संकुचित करते हुए अदालत की आड़ लेकर इसे ताज कॉरिडोर प्रकरण की जांच में शामिल कर दिया. जबकि दोनों मामले अलग-अलग हैं. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था.

मई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2012 के फ़ैसले की समीक्षा करने की याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए स्पष्ट किया था कि उसके पिछले फ़ैसले में आय से अधिक संपत्ति मामले में मायावती के ख़िलाफ़ आगे की कार्रवाई करने का अधिकार सीबीआई से वापस थोड़े ही ले लिया गया था! इसके बावजूद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के इस रुख पर कोई ध्यान नहीं दिया. स्पष्ट है कि सीबीआई मायावती के आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच करने से टालमटोल कर रही थी. अब उसे इस टालमटोल का जवाब देना है. टालमटोल की पराकाष्ठा तो इसी से समझी जा सकती है कि सीबीआई के अनुसंधानकर्ता क्या रिपोर्ट फाइल करने वाले हैं, मायावती को यह भी पता रहता था. इस पर सीबीआई के तत्कालीन निदेशक विजय शंकर ने गहरी आपत्ति भी जताई थी. सनद रहे, मायावती के आय से अधिक संपत्ति मामले में ही सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि सीबीआई बसपा अध्यक्ष मायावती के ख़िलाफ़ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है. याद रहे कि सीबीआई ने मायावती की आय से अधिक संपत्ति की जांच में ढेर सारे सबूत हासिल किए थे, लेकिन बाद में हुए घालमेल के कारण असली मामले से ध्यान हट गया. सुप्रीम कोर्ट ने ताज कॉरिडोर प्रकरण से डीए (आय से अधिक संपत्ति) मामला जोड़े जाने की सीबीआई की कार्रवाई खारिज की थी, लेकिन सीबीआई को असली मामले की जांच से मना नहीं किया था! फिर भी सीबीआई चादर तानकर सो गई. अब उन सबूतों पर भी बात होगी, जो सीबीआई ने इकट्ठा किए थे. धीरे-धीरे परतें खुल रही हैं. कभी कोई बसपा नेता फंस रहा है, तो कभी कोई नौकरशाह. लेकिन किन नेताओं, कर्मचारियों, नौकरों एवं विश्वासपात्रों के नाम पर मायावती की बेनामी संपत्तियां हैं, अभी इसका खुलासा होना बाकी है. मायावती द्वारा रिश्तेदारों के नाम पर बनाई गई अनाप-शनाप संपत्तियों के सबूत सीबीआई के पास हैं.

सीबीआई की जांच-पड़ताल में मायावती और उनके कुनबे की कई सौ करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्तियों का पता चला था. ताज कॉरिडोर को लेकर मायावती के ख़िलाफ़ 18 जुलाई, 2003 को विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ था. सीबीआई को जांच पड़ताल में मिले सबूतों के आधार पर 5 अक्टूबर, 2003 को आरसी नंबर 19-ए के तहत आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभियोग दर्ज किया गया था. राजनीतिक सौदेबाजी और दबाव के चलते तब सीबीआई ऐसा कुछ खास नहीं जुटा पाई. सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी 17 करोड़ रुपये पर सवाल उठाया, जिनका पता नहीं चला कि वे कहां चले गए.

बहरहाल, सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख से स्पष्ट है कि मायावती की आय से अधिक संपत्ति का मामला अलग है और ताज कॉरिडोर घोटाला मामला अलग. दोनों अलग-अलग विषय हैं और दोनों की अलग-अलग जांच हो सकती है. विधि विशेषज्ञों का भी कहना है कि ताज कॉरिडोर मामले से डीए मामला जोड़ दिए जाने को खारिज किया गया था. इससे आय से अधिक संपत्ति की जांच की संभावनाओं को ही ख़त्म नहीं माना जा सकता.

सूत्र कहते हैं कि सीबीआई की फाइल में कई शहरों में मायावती के नामी-बेनामी बंगले, हीरे-जवाहरात के आभूषण और कई फार्म हाऊसों का जिक्र है. दिल्ली स्थित मायावती के दो बैंक खातों से मिले 2.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा की धनराशि के ब्यौरे के साथ ही इन खातों से निकाले गए रुपये ठिकाने लगाने का विवरण भी सीबीआई की फाइलों में दर्ज है. सबूत मिटाने की भी कोशिशें खूब हुईं. फाइलों से छेड़छाड़ करने की केंद्रीय फॉरेंसिक जांच प्रयोगशाला और विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा भी पुष्टि की जा चुकी है. अब जब फिर से (निष्पक्षता से) जांच होगी, तो सीबीआई अपनी ही फाइल फिर से खोलेगी. तब बसपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मायावती के खास क़ानूनी सलाहकार सतीश चंद्र मिश्र और उनकी बहन आभा अग्निहोत्री के देहरादून स्थित उन भूखंडों का भी जिक्र आएगा, जिन्हें बढ़ी हुई क़ीमतों पर बसपा कर्मचारी महेश टमटा को बेचा दिखाया गया. महेश टमटा जैसे कई कर्मचारी हैं, जिनके नाम ऐसी संपत्तियां दर्ज हैं. ऐसा ही नैनीताल या अन्य स्थानों में भी हुआ. देहरादून में कई अचल संपत्तियां मायावती के भाई एवं भाभियों के नाम हैं. मसूरी के विधायक रहे राजेंद्र शाह के देहरादून के नेहरू नगर स्थित विशाल भवन की खरीदारी मायावती के भाई के नाम हुई थी. यह संपत्ति आज करोड़ों रुपये की है. ऐसे अनगिनत मामले सीबीआई की पकड़ में हैं. सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि आयकर विभाग की आंख में धूल झोंकने के इरादे से मायावती ने अपने भाई-भतीजों, मां-बाप और रिश्तेदारों के नाम बैंक खातों में बड़ा धन जमा किया. उनके नाम से भवन-भूखंड भी खरीदे. मायावती के चपरासियों एवं रसोइयों तक के नाम भारी बैंक बैलेंस एवं भूखंडों की जानकारी सीबीआई के पास है. मायावती ने अपने गांव बादलपुर में जो आलीशान महल बनवाया, उसकी खूबसूरती के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 35 एकड़ ज़मीन पर लगभग 140 करोड़ रुपये की लागत से दो पार्क बनाए थे.

मायावती सारा धन बसपा और बसपा फाउंडेशन का बताती हैं, लेकिन यह नहीं बतातीं कि फिर उस धन को दूसरों के बैंक खातों में क्यों जमा कराया गया? मायावती को बिजनौर के लोगों ने रावली रोड पर एक शानदार कोठी खरीद कर दी थी. उस कोठी को भी बेच डाला गया और उसकी रकम का पता नहीं चला. याद रहे कि मायावती ने बिजनौर में बिरादरी के लोगों के छप्परों के नीचे बैठकर अपनी राजनीति शुरू की थी. तब फूल सिंह कबाड़ वाले और उनके कुछ सहयोगी अपनी साइकिल के पीछे बैठाकर मायावती को गांव-गांव ले जाते थे. फूल सिंह कबाड़ वाले तो ज़िंदा नहीं हैं, लेकिन यह सच्चाई तो अब भी ज़िंदा है. ■

सीबीआई के हाथ लगे बैंक खाते

धारक का नाम	बैंक	खाता संख्या	जमा धनराशि
मायावती	यूनियन बैंक, मोतीबाग, नई दिल्ली	9195	2,27,94,533 रुपये
मायावती	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली	01190526277	23,45,539 रुपये
राजकुमार (भाई)	यूनियन बैंक, नोएडा	----	32,00,000 रुपये
राजकुमार (भाई)	विजया बैंक, बुलंदशहर	----	16,05,649 रुपये
राजकुमार (भाई)	कैनरा बैंक, करोल बाग, दिल्ली	----	86,940 रुपये
आनंद कुमार (भाई)	यूनियन बैंक, नोएडा	59578	19,06,904 रुपये
आनंद कुमार (भाई)	यूनियन बैंक, नोएडा	1484	38,92,020 रुपये
विचित्र लता (भाभी)	यूनियन बैंक, नोएडा	59880	4,54,201 रुपये
विचित्र लता (भाभी)	यूनियन बैंक, नोएडा	1455	7,09,331 रुपये
रचना (भाभी)	यूनियन बैंक, नोएडा	1187	3,88,893 रुपये
रचना (भाभी)	यूनियन बैंक, नोएडा	584	5,02,506 रुपये
निर्मला रानी (भाभी)	यूनियन बैंक, नोएडा	1604	21,07,584 रुपये
निर्मला रानी (भाभी)	विजया बैंक, बुलंदशहर	12391	10,24,214 रुपये
सुभाष कुमार (भाई)	यूनियन बैंक, नोएडा	59591	13,77,800 रुपये
प्रभु दयाल (पिता)			
भाई राजकुमार और भाभी निर्मला रानी, रामरती (मां)	--- केनरा बैंक, दिल्ली ---	59617 एफडी ---	20,54,000 रुपये 70,44,000 रुपये 36,00,000 रुपये

अचल संपत्तियों का विवरण

नाम	स्थान	संपत्ति	क़ीमत
प्रभु दयाल (पिता)	सिकंदरपुर, अलीगढ़	भूमि	2,48,000 रुपये
----	बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर	-----	5,92,000 रुपये
राजकुमार (भाई)	इंद्रपुरी, नई दिल्ली	दुकान	1,83,000 रुपये
राजकुमार (भाई)	एफ-88, पश्चिमी दिल्ली	भवन	15,67,000 रुपये
राजकुमार (भाई)	शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली	----	5,65,000 रुपये
राजकुमार (भाई)	पटेल नगर, नई दिल्ली	----	17,00,000 रुपये
तेज सिंह (भाई)	मौजपुर, खुर्जा	भूमि	10,00,000 रुपये
निर्मला रानी (भाभी) पत्नी राजकुमार	गयासपुर, बुलंदशहर	भूमि	13,25,000 रुपये
सिद्धार्थ कुमार (भाई)	सेक्टर-55, नोएडा	भवन	12,50,000 रुपये
सिद्धार्थ कुमार (भाई)	सेक्टर-55, नोएडा	भवन	5,53,000 रुपये
आनंद कुमार (भाई)	सेक्टर-44, नोएडा	भवन	81,00,000 रुपये
आनंद कुमार (भाई)	सेक्टर-44, नोएडा	भवन	16,00,000 रुपये
आनंद कुमार (भाई)	ग्यासपुर, बुलंदशहर	बाग	33,50,000 रुपये
राजवीर सिंह (भाई)	फरीदपुर, बिजनौर	भूमि	27,40,000 रुपये
विचित्र लता (भाभी)	ग्यासपुर, बुलंदशहर	भूमि	3,52,000 रुपये
मायावती	ग्यासपुर, बुलंदशहर	फार्म हाउस	9,00,000 रुपये

मुलायम तक पहुंच सकती है आंच

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच का प्रकरण तो समाप्त हो गया है, लेकिन जांच के दायरे में उनकी पत्नी साधना गुप्ता एवं उनके छोटे बेटे प्रतीक यादव तो हैं ही. लिहाजा, यह जांच कभी न कभी मुलायम तक आंच पहुंचा सकती है. याद करते चलें कि मुलायम सिंह के ख़िलाफ़ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच बंद करने के बाद सीबीआई ने आयकर विभाग से कहा था कि वह साधना गुप्ता द्वारा अपने बेटे प्रतीक यादव के नाम पर अर्जित कथित बेनामी संपत्तियों की जांच करे. सीबीआई ने आयकर विभाग को लिखे पत्र में करोड़ों रुपये मूल्य की चार संपत्तियां लखनऊ में होने का जिक्र किया था. सीबीआई ने 2007 की अपनी रिपोर्ट में इन संपत्तियों को मुलायम सिंह की संपत्ति में शामिल कर लिया था, लेकिन बाद में हटा दिया. सीबीआई ने मुलायम के ख़िलाफ़ आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति से जुड़ा पुराना मामला साक्ष्य के अभाव में बंद कर दिया था. इसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की आय, संपत्ति और व्यय को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग किया जाना चाहिए. सीबीआई ने कहा, जांच के दौरान दस्तावेजों, गवाहों के बयानों और संदिग्धों के बयान की सावधानीपूर्वक जांच में मुलायम सिंह एवं उनके परिवार के सदस्यों के ख़िलाफ़ संयुक्त रूप से या निजी तौर पर आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति रखने के आरोप के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं सामने आए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

राज्य में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पिछले दस सालों से विराजमान है. ज़बरदस्त सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही हुड्डा सरकार के ख़िलाफ़ आमजन के गुस्से का मुख्य कारण कई घोटालों का खुलासा होना, सरकार में शामिल मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप और लचर क़ानून व्यवस्था आदि है. इन सबका परिणाम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस देख चुकी है. दूसरी तरफ़ लोकसभा चुनाव के समय से कांग्रेस नेताओं द्वारा पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह अब भी जारी है. साथ ही चुनाव से ठीक पहले पार्टी की अंदरूनी कलह भी सबके सामने है. जहां एक तरफ़ चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे नेता पार्टी छोड़कर चले गए.

महाराष्ट्र

बहुकोणीय मुकाबले में किसे होगा फ़ायदा

शशि शेखर

19 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आ जाएगा. 15 अक्टूबर को राज्य की 288 सीटों पर मतदाना होना है. इन सीटों के लिए छह हज़ार उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं. जहां तक गठबंधन का सवाल है, तो एक तरफ़ भाजपा और शिवसेना ने अपना 25 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया, वहीं दूसरी तरफ़ कांग्रेस और एनसीपी ने भी अपना 15 साल पुराना गठबंधन समाप्त कर लिया. कांग्रेस और सपा में भी गठबंधन की पहले ख़बर आई, लेकिन बाद में वह भी टूट गया. हां, भाजपा का गठबंधन ज़रूर आरपीआई से हुआ है. कांग्रेस ने सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं. कांग्रेस पिछले 15 सालों के बाद पहली बार अकेले चुनाव मैदान में उतरी है. पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 174 और एनसीपी ने 114 सीटों पर चुनाव लड़ा था.

हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम क़रीब सभी दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं. लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला बड़ा चुनाव है. बदले राजनीतिक हालात में कांग्रेस, भाजपा, एनसीपी और शिवसेना के सामने खुद को साबित करने की एक बड़ी चुनौती है. वैसे भाजपा और शिवसेना का गठबंधन टूटना दोनों दलों के लिए नुक़सानदायक साबित हो सकता है. इन दोनों ही दलों का वोट आधार क़रीब-क़रीब एक है. अब जब दोनों एक-दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, तो हो सकता है कि इसका फ़ायदा किसी और को मिल जाए. वैसे, पश्चिमी महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस की स्थिति अच्छी रही है, लेकिन अब ये दोनों भी अलग-अलग हैं. जाहिर है, इससे इस क्षेत्र में दोनों को नुक़सान उठाना पड़ सकता है.

शुरुआत से ही शिवसेना राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 171 पर चुनाव लड़ती थी, जबकि बाकी सीटें भाजपा के खाते में जाती थीं. लोकसभा चुनाव में भाजपा को ज़्यादा सीटें मिलती थीं और शिवसेना को कम. एनडीए को पिछले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में जबरदस्त सफलता मिली. इस जीत का सेहरा मोदी लहर के हिस्से में गया था. ग़ौरतलब है कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है, जहां तक़रीबन सभी राजनीतिक दलों का संगठनात्मक ढांचा मज़बूत है. 2009 की तुलना में भाजपा के मतों में 9.13 और शिवसेना के मतों में 3.60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी. इस सबसे भाजपा का उत्साहित होना स्वाभाविक है. ऐसी स्थिति में भाजपा के लिए सीटों के मसले पर शिवसेना से अलग होना आसान हो गया. वैसे, भाजपा के लिए फिलहाल एक नुक़सान यही है कि उसका एक मजबूत नेता गोपीनाथ मुंडे अब उसके साथ नहीं है.

गठबंधन टूटने के बाद कौन सबसे अधिक फ़ायदे में रहेगा, सवाल यही है. पिछले कुछ सालों में जिस तरह से कांग्रेस-एनसीपी सरकार में घोटाले हुए हैं, उसे देखते हुए मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन को नुक़सान उठाना पड़ेगा. कांग्रेस के अलावा, सिंचाई घोटाले में मुख्य रूप से एनसीपी शामिल थी. आम जनता में एनसीपी नेताओं के रवैये को लेकर भी असंतोष है. एनसीपी सिंचाई घोटाला, हाईवे टोल-टैक्स, ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती को लेकर जनता के निशाने पर है.

बहरहाल, गठबंधन टूटने के बाद कौन सबसे अधिक फ़ायदे में रहेगा, सवाल यही है. पिछले कुछ सालों में जिस तरह से कांग्रेस-एनसीपी सरकार में घोटाले हुए हैं, उसे देखते हुए मौजूदा सत्ताधारी गठबंधन को नुक़सान उठाना पड़ेगा. कांग्रेस के अलावा, सिंचाई घोटाले में मुख्य रूप से एनसीपी शामिल थी. आम जनता में एनसीपी नेताओं के रवैये को लेकर भी असंतोष है. एनसीपी सिंचाई घोटाला, हाईवे टोल-टैक्स, ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती को लेकर जनता के निशाने पर है. उधर एनसीपी के बड़े नेता सूर्यकांत पाटिल, पूर्व मंत्री बबनराव पचपुते, पूर्व एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष अजित घोरपड़े पार्टी से निकल चुके हैं. इतना ही नहीं, उप-मुख्यमंत्री अजित पवार के व्यवहार से भी एनसीपी में असंतोष है.

बहरहाल, भाजपा के लिए अच्छी बात यह है कि विदर्भ क्षेत्र में उसकी अच्छी पैठ है. पृथक विदर्भ का भाजपा शुरू से समर्थन करती आ रही है. विदर्भ के भाजपा नेताओं को लगता है कि महाराष्ट्र का विभाजन करके विदर्भ को अलग राज्य बनाने से पार्टी को फ़ायदा होगा और चूंकि मोदी लहर भी है, तो इस वजह से इस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जा सकती हैं. ग़ौरतलब है कि शिवसेना पृथक विदर्भ का विरोध करती है. नतीजतन, भाजपा को भी लगा कि शिवसेना के साथ रहते हुए वह अपने अलग विदर्भ के एजेंडे को पूरा नहीं कर पाएगी.

वैसे, चुनाव पूर्व से अधिक चुनाव बाद बनने वाले समीकरण दिलचस्प होंगे. इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसी की सरकार बनने की संभावना सबसे अधिक होगी. ऐसे में अभी भाजपा फ़ायदे में आती दिख रही है. चुनाव बाद, चाहे वह शिवसेना हो, एनसीपी हो या फिर मनसे, इनमें से कोई भी भाजपा को सरकार बनाने के लिए समर्थन दे सकता है. यह भी हो सकता है कि शिवसेना और भाजपा ने जिस गठबंधन को तोड़ दिया, उसे वे चुनाव के बाद फिर से बना लें. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

हरियाणा

किसके हाथ लगेगी बाजी

शफीक आलम

हरियाणा विधानसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने और नाम वापसी की प्रक्रिया समाप्त हो गई है. राज्य की 90 सीटों के लिए रिकॉर्ड 109 महिलाओं समेत कुल 1350 उम्मीदवार मैदान में हैं. भारतीय राष्ट्रीय लोकदल, कांग्रेस, भाजपा एवं हरियाणा जनहित कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के साथ-साथ इनका खेल बिगाड़ने के लिए कांग्रेस से अलग हुए विनोद शर्मा की जनचेतना पार्टी और विवादों के घेरे में रहे पूर्व मंत्री गोपाल कांडा की हरियाणा लोकहित पार्टी भी मैदान में हैं. जहां लोकसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद भाजपा का खेमा उत्साहित दिख रहा है, वहीं राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अपनी खोई हुई साख बचाने की हर मुमकिन कोशिश में लगी है.

दूसरी तरफ़ इंडियन नेशनल लोकदल (आईएनएलडी) ने अपने संस्थापक चौधरी देवीलाल के जन्मदिन के अवसर पर जींद में एक विशाल रैली के रूप में शक्ति प्रदर्शन करके राज्य की सत्ता पर अपनी मज़बूत दावेदारी पेश की है.

अगर पिछले तीन विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखा जाए, तो राज्य में भाजपा का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. उसे 2000 में छह, 2005 में दो और 2009 में चार सीटें मिली थीं. 2000 में आईएनएलडी की सरकार बनी थी, जबकि 2005 एवं 2009 में कांग्रेस सत्ता पर काबिज़ हुई थी. जहां तक वोट प्रतिशत का सवाल है, तो भाजपा को इनमें से किसी भी चुनाव में 10 प्रतिशत से अधिक वोट नहीं मिले. लेकिन, हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की 10 सीटों में से सात पर क़ब्ज़ा कर लिया, जबकि कांग्रेस को एक और आईएनएलडी को दो सीटों के साथ संतोष करना पड़ा. भाजपा का वोट प्रतिशत 35 था, वहीं कांग्रेस को 22 और आईएनएलडी को 23 प्रतिशत वोट मिले.

इन नतीजों के आधार पर और राज्य में 10 सालों से सत्तारूढ़ एवं घोटालों-घपलों का आरोप झेल रही कांग्रेस को देखते हुए भाजपा को लग रहा है कि 19 अक्टूबर को नतीजे आने के बाद वह राज्य में पहली बार अकेले ही सरकार बना सकती है. हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ भाजपा का गठबंधन टूटने के पीछे यही विश्वास था. लेकिन क्या भाजपा के लिए सत्ता का रास्ता आसान होगा? जहां तक लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी का सवाल है, तो देश के चुनाव विश्लेषक मानते हैं कि जहां लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय एवं बड़े मुद्दों पर लड़े जाते हैं, वहीं विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं. इसलिए लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी विधानसभा में कामयाबी की ज़मानत नहीं दे सकती. इस तथ्य के कई उदाहरण मौजूद हैं. हाल में संपन्न उपचुनाव में भाजपा को कई प्रतिकूल परिणामों का सामना करना पड़ा. हालांकि उपचुनाव के परिणाम गंभीरता से नहीं लिए जाते. बहरहाल, राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी भाजपा को संगठन के अंदर ही विद्रोह के सुर सुनाई देने लगे हैं. लोकसभा चुनाव में भाजपा की कामयाबी के बाद दूसरी पार्टियों के बहुत सारे नेता भी उसमें शामिल हो गए थे, जो विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज़ हैं. हिसार से पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके जयवीर गोदारा ने इस बार टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाते हुए इसकी सीबीआई से जांच कराने की मांग कर डाली. ज़ाहिर है, ऐसे विद्रोही स्वर भाजपा को चुनाव में नुक़सान पहुंचा सकते हैं. उधर चुनाव प्रक्रिया के शुरुआती दिनों में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कई जनसभाएं की, लेकिन उनमें उतनी भीड़ नहीं जुटी, जितनी लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी. ऐसे में भाजपा की सारी उम्मीदें स्टार प्रचारक एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई हैं. भाजपा आम तौर पर चुनाव से पहले ही अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा कर देती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ. हालांकि मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में इंद्रजीत सिंह एवं कैप्टन अभिमन्यु के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से पार्टी ने कोई घोषणा नहीं की है. इसका नुक़सान भी पार्टी को हो सकता है.

राज्य में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पिछले दस सालों से विराजमान है. ज़बरदस्त सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही हुड्डा सरकार के ख़िलाफ़ आमजन के गुस्से का मुख्य कारण कई घोटालों का खुलासा होना, सरकार में शामिल मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप और लचर क़ानून व्यवस्था आदि है. इन सबका परिणाम लोकसभा चुनाव में कांग्रेस देख चुकी है. दूसरी तरफ़ लोकसभा चुनाव के समय से कांग्रेस नेताओं द्वारा पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वह अब भी जारी है. साथ ही चुनाव से ठीक पहले पार्टी की अंदरूनी कलह भी सबके सामने है. जहां एक तरफ़ चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे नेता पार्टी छोड़कर चले गए, वहीं विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर और मुख्यमंत्री हुड्डा के बीच चली खींचातानी भी अख़बारों की सुर्ख़ियां बनी. ज़ाहिर है, इसका नकारात्मक असर पार्टी के प्रदर्शन पर पड़ेगा. कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में भी पूर्ण बहुमत के साथ चुनकर नहीं आई थी. उसे राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 40 सीटें मिली थीं, जबकि आईएनएलडी के 31 उम्मीदवार चुनाव जीते थे. आईएनएलडी ने 25 सितंबर को जींद में एक विशाल रैली करके न सिर्फ़ विधानसभा चुनाव में अपनी ज़बरदस्त उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि इस रैली में जनता परिवार को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की घोषणा और मंच पर अकाली दल (बादल) के नेता प्रकाश सिंह बादल की मौजूदगी का लाभ भी पार्टी को मिलेगा. यह अलग बात है कि आईएनएलडी को छोड़कर जनता परिवार के किसी घटक की राज्य में कोई खास मौजूदगी नहीं है, लेकिन आईएनएलडी के पक्ष में इसका एक सकारात्मक संदेश ज़रूर जाएगा. पिछले चुनावों के नतीजे साबित करते हैं कि राज्य के कई क्षेत्रों में आईएनएलडी की पकड़ बहुत मज़बूत है.

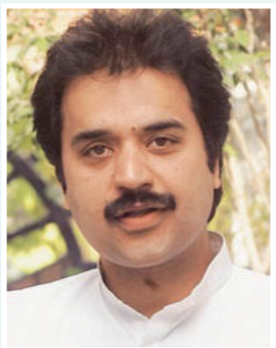

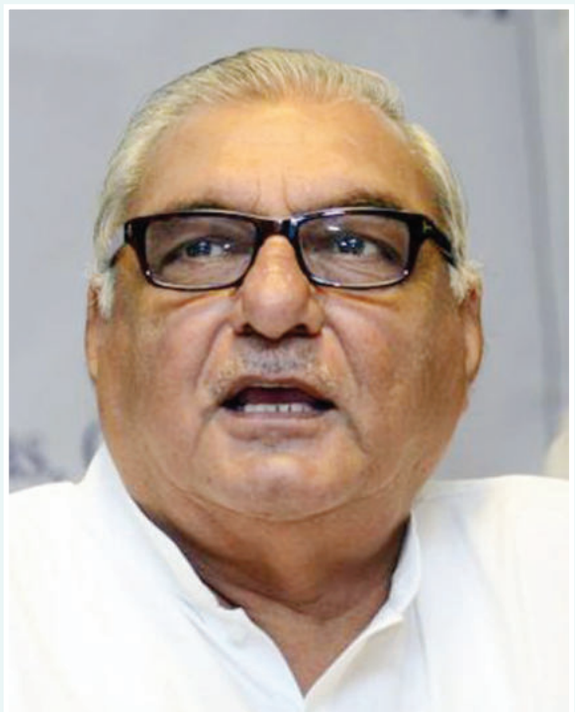

अगर 2000 के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नज़र डालें, तो पता चलता है कि तब आईएनएलडी को 47 सीटें मिली थीं, जबकि कांग्रेस को 21. कांग्रेस को 31 और आईएनएलडी को 30 प्रतिशत वोट मिले थे. एक प्रतिशत अधिक वोट हासिल करने के बावजूद कांग्रेस को कम सीटें मिली थीं, जिसका कारण यह था कि कांग्रेस की मौजूदगी पूरे राज्य में थी. लिहाज़ा, इसमें कोई शक नहीं कि राज्य में बहुकोणीय मुकाबला होगा.

ऐसी स्थिति में आईएनएलडी सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रहेगी. जहां तक पार्टी के अंदरूनी अनुशासन का सवाल है, तो आईएनएलडी सत्ता के अन्य दो दावेदारों यानी कांग्रेस और भाजपा से कहीं अधिक व्यवस्थित पार्टी नज़र आ रही है. लिहाज़ा, इन सारे तथ्यों का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि आईएनएलडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी. दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो फिलहाल आईएनएलडी ही ऐसी पार्टी है, जो अकेले सरकार बनाने की स्थिति में दिख रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार

मांझी-मंदिर प्रकरण और सुलगते सवाल

सुकांत नागार्जुन

जीतनराम मांझी जदयू के भीतर खुद को दल के अघोषित सुप्रीमो नीतीश कुमार के समानांतर खड़ा करने की जी–तोड़ कोशिश में हैं? वह राज्य की राजनीति, विशेष तौर पर दलित राजनीति में नए आयाम जोड़ना चाहते हैं? पटना के राजनीतिक गलियारे में ये सवाल आम हो गए हैं. मंदिर प्रकरण ने इन सवालों को नया और तीखा बना दिया है. मुख्यमंत्री ने बीते अगस्त माह में विधानसभा उप–चुनाव के दौरान हुई एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वह मधुबनी के एक गांव में स्थित मंदिर में गए थे, जिसे उनके वापस आने के बाद धोया गया था. उन्हें यह बात उनके मंत्री रामलखन राम रमण ने बताई. उन्होंने कहा कि उनके साथ अब भी भेदभाव होता है. लोग काम के लिए आने पर मेरे पैर छूते हैं, लेकिन जब मैं मंदिर जाता हूं, तो मेरे वापस लौटने के बाद उसे धोते हैं.

पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव ने इस रहस्योद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी. मांझी की इस बात को जदयू के मंत्री नीतीश मिश्र एवं विधान पार्षद विनोद सिंह ने गलत बताया है. मांझी सरकार में खान एवं भूतत्व मंत्री रामलखन राम रमण ने भी मुख्यमंत्री को ऐसी किसी घटना की जानकारी देने से इंकार किया है, लेकिन मांझी को अपने किसी मंत्री या विधान पार्षद पर भरोसा नहीं है. लिहाजा उन्होंने इस प्रकरण की प्रशासनिक जांच के आदेश दिए हैं. दरभंगा के आयुक्त एवं पुलिस महानिरीक्षक मामले की जांच करके रिपोर्ट देंगे और तब आगे की कार्रवाई होगी.

मांझी चार दशकों से अधिक समय से सक्रिय राजनीति में हैं और तीन दशकों से अधिक समय से मंत्री. कांग्रेस की सरकारों में हिस्सेदारी निभाने और लालू-राबड़ी की कप्तानी झेलने के बाद वह नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे. इतनी लंबी यात्रा के बाद नीतीश कुमार की कृपा से (बतौर उनकी कठपुतली) उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिला. मांझी जानते और सार्वजनिक रूप से कहते भी हैं कि वह अगले कुछ महीने ही मुख्यमंत्री हैं.

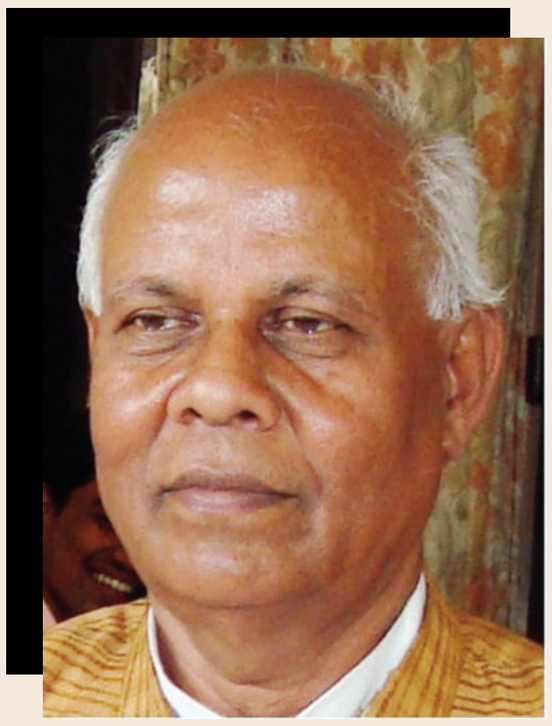

मधुबनी ज़िले के ठाढ़ी गांव में परमेश्वरी स्थान नामक यह मंदिर किसी देवता का नहीं, बल्कि ग्राम देवी का है और मिट्टी का पिंडा है. चूंकि इसे धोया नहीं जाता है, इसीलिए सुबह–शाम इसकी सफाई ही होती है. राजनगर उपचुनाव में प्रचार अभियान के दौरान नीतीश मिश्र एवं विनोद सिंह के साथ मांझी यहां पहुंचे थे, पूजा–अर्चना की थी. उनके साथ रामलखन राम रमण या कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं था. रमण ने खुद ऐसी कोई जानकारी मुख्यमंत्री को देने से इंकार किया और कहा, पूर्व सांसद एवं जदयू नेता देवेंद्र प्रसाद यादव ने ही इस वाकये के बारे में मुख्यमंत्री को बताया था. उस समय मैं भी वहां मौजूद था. यानी मुख्यमंत्री को इस घटना की जानकारी सुनी–सुनाई बातों के आधार पर दी गई, वह चाहे रमण ने दी हो या यादव ने. यदि मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा करें, तो वह लोगों को यह नहीं बताते कि रमण ने उन्हें इसकी जानकारी कब दी. वह यह भी नहीं बताते कि उन्हें जब इस वाकये के बारे में बताया गया, तो उन्होंने इसे जनसभा में बताने की बजाय इसकी जांच कराना मुनासिब क्यों नहीं समझा? क्या वह सियासी हंगामा पैदा करने लायक माहौल की प्रतीक्षा कर रहे थे?

जाहिर है, मुख्यमंत्री की चुनावी यात्रा के दौरान प्रशासन ने अपनी ओर से खास व्यवस्था की होगी. लिहाजा उस गांव में भी वैसी व्यवस्था हुई होगी. मंदिर से सात किलोमीटर की दूरी पर थाना और प्रखंड कार्यालय है. पंचायत में मुखिया है, सरपंच है, चौकीदार है. किसी ने कोई जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी को क्यों नहीं दी, कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? लगभग दो महीने तक पुलिस और ज़िला प्रशासन खामोश क्यों रहा? रमण और यादव को यदि इसकी पक्की जानकारी थी, तो उन्होंने मधुबनी के ज़िला प्रशासन को इसकी सूचना क्यों नहीं दी? यदि उन्होंने मुख्यमंत्री को गलत जानकारी दी है, तो उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी? यदि मंदिर धोने की घटना सही है, तो मुख्यमंत्री को झूठा साबित करने वाले मंत्री एवं जदयू विधान पार्षद के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जा रही है? मामले की जांच कराने की घोषणा जदयू ने भी की है. वह अपनी टीम भेजेगा, लेकिन कब टीम भेजी जाएगी और उसमें कौन लोग शामिल होंगे, यह घोषणा अभी नहीं की गई है. राज्य में महादलित आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ ऐसा अमानवीय–आपराधिक भेदभाव हो रहा है और सभी खामोश हैं. मामले की जांच भी स्वयं मुख्यमंत्री के आदेश पर हो रही है.

उम्मीद है कि इस संवेदनशील मामले की जांच तत्परता और पूरी गंभीरता से जल्द पूरी कर ली जाएगी. यह सामान्य बात नहीं है. आज़ादी के 67 सालों बाद भी देश में ऐसा होता है, यह किसी भी सभ्य समाज की कल्पना से बाहर है. लिहाजा किसी की यह अपेक्षा सहज है कि इस प्रकरण में (यदि यह सही साबित होता है) सभी दोषियों को कठोर दंड मिले. दंड उन्हें भी मिले, (अधिकारियों एवं जन–प्रतिनिधियों) जिन्होंने इस प्रकरण को दबाकर रखा और समाज में ग़ैर संवैधानिक व्यवस्था के पोषक लोगों की मदद की. सवाल यह भी है कि यदि मामला गलत साबित होता है, तो क्या होगा? समाज में जातीय उन्माद की हवा चलाने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या राजनीतिक दल ऐसे तत्वों को दल के भीतर पद और चुनाव में उम्मीदवारी देकर सम्मानित करने से बाज आएंगे?

दरअसल, ऐसे नाजुक मामलों में कान से अधिक चेतना और दिल से नहीं, दिमाग से काम लेने की ज़रूरत होती है. सिर्फ सत्ता–शीर्ष पर मौजूद नौकरशाह नहीं, राजनेताओं से भी यही अपेक्षा रहती है. मांझी को भी इस प्रकरण पर किसी आमसभा में राय रखने या प्रतिक्रिया व्यक्त करने के पहले आधिकारिक तौर पर पक्की जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए थी. उनके पास पूरी सरकार है, सारी सूचनाएं मिनटों में उन तक पहुंच सकती हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. आख़िर क्यों?

मांझी चार दशकों से अधिक समय से सक्रिय राजनीति में हैं और तीन दशकों से अधिक समय से मंत्री. कांग्रेस की सरकारों में हिस्सेदारी निभाने और लालू–राबड़ी की कप्तानी झेलने के बाद वह नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे. इतनी लंबी यात्रा के बाद नीतीश कुमार की कृपा से (बतौर उनकी कठपुतली) उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिला. मांझी जानते और सार्वजनिक रूप से कहते भी हैं कि वह अगले कुछ महीने ही मुख्यमंत्री हैं. पटना के राजनीतिक हलकों में उन्हें गया का और गया में महकार (मुख्यमंत्री का पैतृक गांव) का मुख्यमंत्री कहा जाता है. लेकिन, वह बिहार के दलित नेता के तौर पर अपनी पहचान के लिए काफी परेशान हैं.

वह केवल दलितों–महादलितों को नहीं, बल्कि उन तमाम छोटी, उपेक्षित, वंचित एवं अति पिछड़ी जातियों को भी समेटना चाहते हैं, जिनके हिस्से का विकास कुछ खास सामाजिक समूह लूट ले जाते हैं. मांझी खुद को उनके हित–संरक्षक के तौर पर पेश कर रहे हैं. मंदिर प्रकरण की वास्तविकता जो भी हो, लेकिन उसका राजनीतिक संदेश मांझी ने दे दिया कि दलित सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा किसी दूसरे के बूते की बात नहीं है.

मांझी के इस नए अवतार से जदयू और नीतीश कुमार को जो भी लाभ मिले, फिलहाल इससे उनकी कट्टर विरोधी भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ा काम अनायास बगैर कुछ किए बन गया. भाजपा से दूर होते कुछ खास सामाजिक समूह के मतदाता एक बार फिर उसके प्रति नरम हो सकते हैं. राम विलास पासवान एवं भाजपा के प्रवक्ता योगेंद्र पासवान की प्रतिक्रियाएं कुछ यही संकेत देती हैं. शायद यही कारण है कि जदयू के कई पुराने नेता मांझी के राजनीतिक बात–व्यवहार को दल के लिए परेशानी का सबब मान रहे हैं और मंदिर प्रकरण के बाद तो वे सब उबाल पर हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

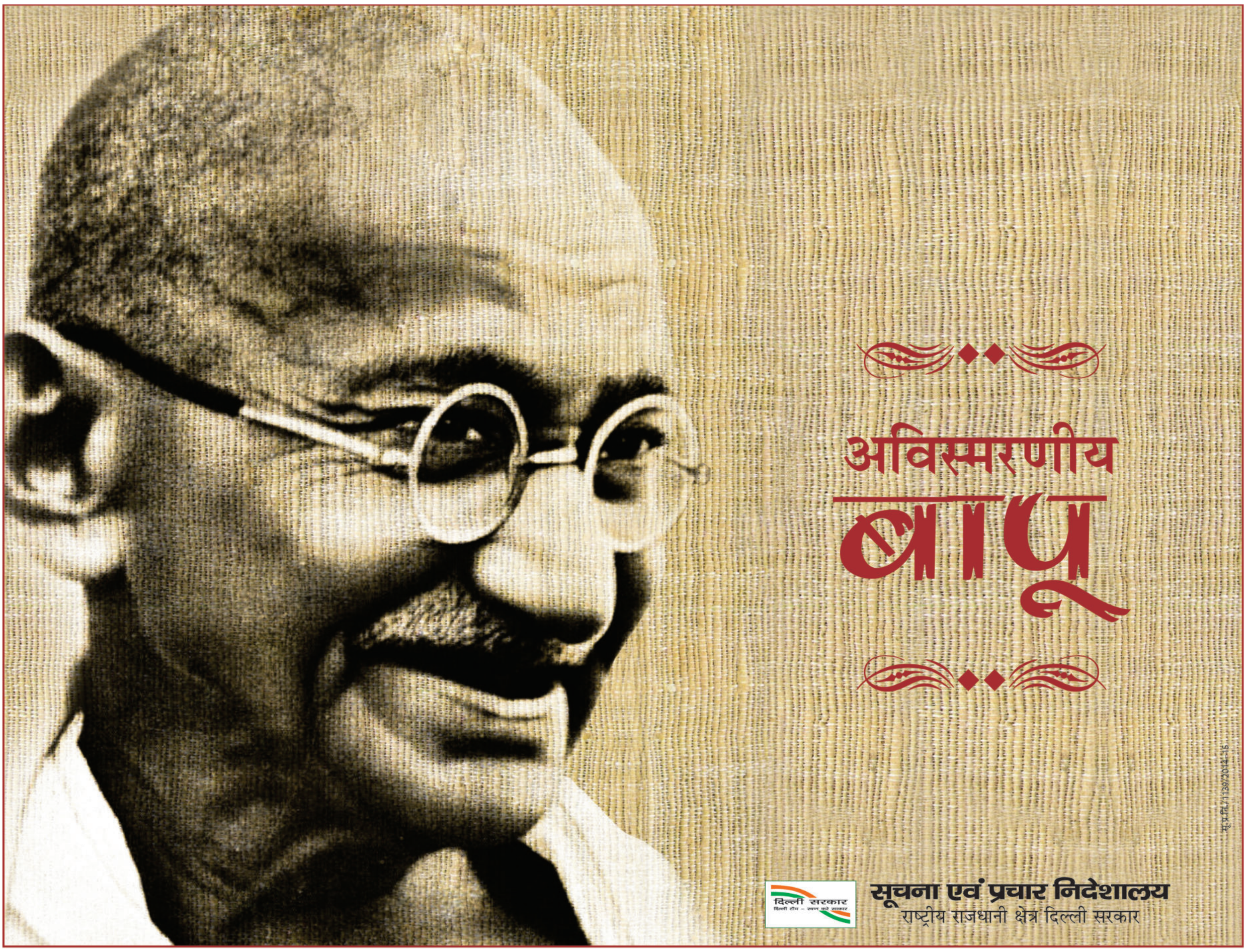

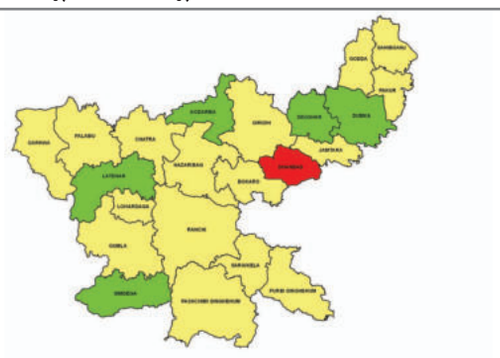

राज्य में राजनीतिक उतार–चढ़ाव के चलते विकास कार्य बाधित हैं. हेमंत ने कहा कि उनकी सरकार का एक वर्ष पिछले 13 वर्षों पर भारी है. सरकार ने शहीदों के आश्रितों को खोजकर उन्हें नौकरी दी. अगर दोबारा झामुमो की सरकार बनती है, तो राज्य के आंदोलनकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा. हेमंत पिछले दिनों बोकारो दौरे पर थे, जहां उन्होंने सेक्टर पांच में आयोजित विकास मेला में 64 योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया.

...सुंदर सपना टूट गया

चौथी दुनिया ब्यूरो

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले सारे गठबंधन टूट गए. एक और छोटा गठबंधन टूटा, जिसकी तरफ़ उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञ बहुत उम्मीद और आशंकाओं, दोनों के प्रिज्म से देख रहे थे. उत्तर प्रदेश के नेताओं को इससे मतलब नहीं था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस–एन–सीपी का गठबंधन बना रहता है कि नहीं अथवा भाजपा–शिव–सेना का गठबंधन बना रहता है या टूट जाता है. बल्कि उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होता है, तो उत्तर प्रदेश में 2017 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के ख़िलाफ़ वृहत्तर गठबंधन की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. महाराष्ट्र में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ और अगले ही दिन टूट भी गया. इसमें कांग्रेस का अड़ियलपन कारण बना.

पहले कांग्रेस–सपा गठबंधन का ऐलान हुआ, लेकिन अगले ही दिन समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने सार्वजनिक तौर पर जानकारी दी कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठबंधन टूट गया है और अब उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी. आजमी ने बताया कि कांग्रेस सपा को उचित संख्या में सीट देने के लिए तैयार नहीं थी, जिसके चलते सपा को गठबंधन से अलग होना पड़ा. कांग्रेस का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की तरह है. आजमी ने कहा कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस को बिना मांगे समर्थन दिया. सपा धर्मनिरपेक्ष मतों का विभाजन रोकने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस उचित सीटें देने के लिए तैयार नहीं हुई.

वहीं कांग्रेस ने भी अपनी तीसरी एवं अंतिम सूची में 26 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित करके समाजवादी पार्टी से एक दिन पुराना गठबंधन तोड़ने की मुनादी कर दी. अबू आसिम आजमी ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि 77 लोगों ने समाजवादी पार्टी से टिकट की मांग की थी. कांग्रेस ने अपना फ़ैसला पहले सुना दिया होता, तो सपा उसके अनुरूप पहले ही फ़ैसला कर लेती. आजमी ने कहा कि सपा की प्राथमिकता भाजपा–शिवसेना को रोकने की थी. कांग्रेस से आठ सीटों के लिए बात हुई थी, जबकि कांग्रेस ने महज तीन सीटों को लेकर मामला फंसा दिया, जबकि इस सिलसिले में उनकी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मानिक राव ठाकरे के साथ निर्णायक वार्ता हो चुकी थी. आजमी को वार्ता करने और आवश्यक निर्णय लेने के लिए सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. राम गोपाल यादव ने अधिकृत किया था. महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश ने उत्तर प्रदेश को लेकर कई संभावनाएं दिखाई थीं. पहली बार कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने से समाजवादी पार्टी के लिए महाराष्ट्र नए समीकरणों की नायाब प्रयोगशाला साबित होता और उत्तर प्रदेश में यह और विस्तार ले सकता था, लेकिन कांग्रेस के कारण ऐसा नहीं हो सका. गठबंधन की कोशिश के पीछे भाजपा के ख़िलाफ़ तमाम राजनीतिक दलों को व्यापक रूप से एकजुट करने की मंशा थी, लेकिन महज तीन सीटों के स्वार्थ ने कांग्रेस को इस गठबंधन से वंचित कर दिया. आंकड़े बताते हैं कि इस गठबंधन से फ़ायदा होता और वोटों का बिखराव बचता.

ग़ौरतलब है कि सपा ने 2009 में भिवंडी, मानखुर्द (शिवाजी नगर) एवं नवापुर सीटें जीती थीं. इससे पहले 2004 में भिवंडी में शिवसेना महज इसलिए जीत गई थी, क्योंकि कांग्रेस को 25 हज़ार वोट मिले और सपा को 82 हज़ार. वोटों के बिखराव से दोनों दलों का नुक़सान हुआ था. अगर साथ चुनाव लड़ते, तो फ़ायदा कांग्रेस और सपा दोनों को होता. महाराष्ट्र प्रयोग के पीछे बिहार प्रयोग की प्रेरणा काम कर रही थी.

बिहार में भाजपा विरोधी वोटों का बिखराव रोकने का प्रयोग उपचुनाव में सफल हुआ. लालू एवं नीतीश ने मिलकर भाजपा को पीछे धकेल दिया. राजद अध्यक्ष लालू यादव ने मुलायम सिंह को भी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा महा–गठबंधन करने की सलाह दी थी. महाराष्ट्र में गठबंधन कायम करने की पहल के पीछे यही प्रेरणा थी, जिसका फ़ायदा चुनाव में दिखता और उत्तर प्रदेश का रास्ता खुलता, लेकिन कांग्रेस ने सारी रूपरेखा पर पानी फेर दिया.

महाराष्ट्र चुनाव में प्रचार के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का कार्यक्रम बन रहा था. यह भी कोशिश थी कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की साझा सभाएं आयोजित हों. दोनों साथ प्रचार करते, तो उसका राजनीतिक संदेश जाता. इस आधार पर उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों के लिए गठबंधन का स्वरूप तय होता, लेकिन महज तीन सीटों की खातिर मैडम ने गठबंधन की स्वीकृति नहीं दी. उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ रहे यूपीए–1 और यूपीए–2 का साथ हमेशा देती रही. सपा ने लोकसभा चुनाव में रायबरेली एवं अमेठी में उम्मीदवार न उतार कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का रास्ता आसान बनाकर यह संदेश दिया था कि भविष्य में व्यापक मित्रता कायम हो सकती है. हालांकि कांग्रेस ने भी मैनपुरी में मुलायम सिंह और कन्नौज में उनकी बहू डिंपल यादव के ख़िलाफ़ उम्मीदवार नहीं उतारे थे. इन्हीं तमाम बातों को आधार बनाकर व्यापक मित्रता की पहल हो रही थी, लेकिन महाराष्ट्र में झटका देकर कांग्रेस ने अपना रुख साफ़ कर दिया. सपा 2012 में मिले व्यापक जनादेश की कुर्बानी दे नहीं सकती और कांग्रेस उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में खुद को स्वाहा कर लेने का निर्णय नहीं कर सकती, भले ही वह एक भी सीट न जीत पाए.

महाराष्ट्र का झटका कुछ वैसा है, जैसा कांग्रेस ने 2009 में फिरोजाबाद सीट पर राजबब्बर द्वारा डिंपल को हराकर दिया था. कुछ कांग्रेसी नेताओं को आज तक इस बात की कसक है कि 1989–90 में मुलायम सिंह सरकार को समर्थन देने का फ़ैसला कांग्रेस को काफी महंगा पड़ा. उन्हें लगता है कि कांग्रेस के समर्थन का फायदा उठाकर मुलायम सिंह अल्पसंख्यकों के दिमाग में यह बात बैठाने में सफल रहे कि भाजपा का विरोध वही कर सकते हैं. ऐसा करके उन्होंने कांग्रेस को वह नुक़सान पहुंचाया, जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो सकी.

बहरहाल, मौजूदा राजनीतिक स्थिति और समझ तो यही है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के ख़िलाफ़ मोर्चा लेने में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से काफी आगे खड़ी है तथा लोकसभा चुनाव में हार के बावजूद खुद को राष्ट्रीय राजनीति में समीकरण बनाने–बिगाड़ने की भूमिका में लाने का प्रयास कर रही है. उपचुनाव में मिली जीत ने भी सपा में आत्मविश्वास भरने का काम किया है. सपा के एक नेता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समझौते की संभावना अब तभी बन सकती है, जब कांग्रेस 90 फ़ीसद से अधिक सीटें सपा को देने के लिए तैयार हो जाए. लेकिन, कांग्रेस ऐसा करने से रही और गठबंधन होने से रहा. ■

feedback@chauthiduniya.com

झारखंड

महा-गठबंधन बनाने की तैयारी

मंगलानंद

कुछ माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर संथाल परगना में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. झामुमो की ओर से जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वयं कमान संभाल रहे हैं, वहीं झाविमो प्रमुख बाबू लाल मरांडी भी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं. संथाल का ताबड़तोड़ दौरा करने के बाद हेमंत सोरेन पूरी तरह से आश्वस्त हो चुके हैं. अब भाजपा ने भी अपनी पूरी ताकत संथाल में झोंक दी है. झारखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद निशिकांत दूबे संथाल में अपनी गोटियां सजा रहे हैं. दूसरी ओर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत एवं सरयू राय सरीखे नेता भी संथाल में घूम–घूमकर जनता और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं. भाजपा अपना सांगठनिक ढांचा दुरुस्त करने में जुटी हुई है. बूथ स्तर पर दमदार उपस्थिति के लिए जगह–जगह कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं.

प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को उम्मीद है कि संथाल में इस बार झामुमो को हराया जा सकता है. भाजपा को यहां की सभी 18 सीटों पर जीत हासिल करने की उम्मीद है, लेकिन उसकी इस उम्मीद पर झाविमो पानी फेर सकता है. यदि झाविमो यूपीए खेमे में गया, तो यूपीए संथाल परगना में मजबूत हो जाएगा. संथाल परगना में इस समय 13 विधायक झामुमो, कांग्रेस एवं राजद के हैं, जबकि दो विधायक झाविमो के. संथाल परगना में झाविमो प्रमुख ने भी कड़ी मेहनत की है. संथाल की कई सीटों पर पार्टी की अच्छी पकड़ है. ऐसे में यदि झामुमो एवं झाविमो जैसे झारखंड नामधारी दल एक साथ मैदान में आए, तो संथाल परगना में चुनावी पासा पलट सकता है, लेकिन अभी तक महा–गठबंधन को लेकर संशय बरकरार है.

यूपीए खेमे के किसी नेता ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं.

प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को उम्मीद है कि संथाल में इस बार झामुमो को हराया जा सकता है. भाजपा को यहां की सभी 18 सीटों पर जीत हासिल करने की उम्मीद है, लेकिन उसकी इस उम्मीद पर झाविमो पानी फेर सकता है. यदि झाविमो यूपीए खेमे में गया, तो यूपीए संथाल परगना में मजबूत हो जाएगा.

झाविमो प्रमुख भी अपनी शर्तों पर ही महा–गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन झामुमो एवं झाविमो एक साथ आएंगे, इसमें संदेह है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में गठबंधन का ऐलान समय आने पर किया जाएगा. बकौल हेमंत, उनकी कई राजनीतिक दलों से बातचीत हो रही है. राज्य में राजनीतिक उतार–चढ़ाव के चलते विकास कार्य बाधित हैं. हेमंत ने कहा कि उनकी सरकार का एक वर्ष पिछले 13 वर्षों पर भारी है. सरकार ने शहीदों के आश्रितों को खोजकर उन्हें नौकरी दी. अगर दोबारा झामुमो की सरकार बनती है, तो राज्य के आंदोलनकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा. हेमंत पिछले दिनों बोकारो दौरे पर थे, जहां उन्होंने सेक्टर पांच में आयोजित विकास मेला में 64 योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया. उन्होंने बताया कि विभिन्न कंपनियों की लौह अयस्क खदान की लीज के नवीनीकरण की प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा पुलिस में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है. ■

पाकिस्तान

राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट की मार

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ अब भी कह रहे हैं कि सत्ता में परिवर्तन की संभावनाएं हैं. दूसरी ओर इमरान ख़ान नवाज़ शरीफ़ के इस्तीफ़े से कम किसी भी शर्त पर अपना विरोध ख़त्म करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं. हालांकि उन्हें दोबारा बातचीत की पेशकश की जा रही है. संघीय मंत्री अहसन इक़बाल पाकिस्तानी अवामी तहरीक और तहरीक-ए-इंसाफ़ से धरना-प्रदर्शन ख़त्म करने की अपील कर रहे हैं. उन्होंने अभी हाल में मीडिया से बात करते हुए कहा, देश धरनों को सहन नहीं कर सकता.

वसीम अहमद

पाकिस्तान इस समय गंभीर राजनीतिक हालात से गुज़र रहा है. इमरान ख़ान एवं धर्मगुरु ताहिरुल क़ादरी के विरोध प्रदर्शन से उत्पन्न उथल-पुथल का सिलसिला अभी रुका भी नहीं कि तीन पाकिस्तानियों को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किए जाने से दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहंसाई शुरू हो गई है. इन समस्याओं को नवाज़ शरीफ़ किस तरह हल करेंगे, इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता. ज़ाहिर है, प्रधानमंत्री ऐसे संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ सामान्य नहीं है. एक ओर इमरान ख़ान एवं ताहिरुल क़ादिरी का विरोध प्रदर्शन निरंतर जारी रहने के कारण देश राजनीतिक संकट का शिकार है और सरकार लड़खड़ा रही है.

पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ अब भी कह रहे हैं कि सत्ता में परिवर्तन की संभावनाएं हैं. दूसरी ओर इमरान ख़ान नवाज़ शरीफ़ के इस्तीफ़े से कम किसी भी शर्त पर अपना विरोध ख़त्म करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं. हालांकि उन्हें दोबारा बातचीत की पेशकश की जा रही है. संघीय मंत्री अहसन इक़बाल पाकिस्तानी अवामी तहरीक और तहरीक-ए-इंसाफ़ से धरना-प्रदर्शन ख़त्म करने की अपील कर रहे हैं. उन्होंने अभी हाल में मीडिया से बात करते हुए कहा, देश धरनों को सहन नहीं कर सकता. इमरान ख़ान हर दिन आरोप-प्रत्यारोप करके पगड़ी उछाल रहे हैं, वह जनता को भ्रमित कर रहे हैं और नौजवानों में ज़हर भर रहे हैं. तहरीक-ए-इंसाफ़ का रवैया असंवैधानिक और बिखराव पर आधारित है. दोनों पार्टियों को चाहिए कि वे धरना-प्रदर्शन ख़त्म करके बातचीत के जरिये समाधान खोजें. स्वयं नवाज़ शरीफ़ ने भी दोनों पार्टियों से धरना ख़त्म करके बातचीत द्वारा समस्या का हल तलाशने की पेशकश की है. लेकिन, इमरान ख़ान सत्ता परिवर्तन के सिवाय किसी और बात पर राज़ी नहीं हैं.

राजनीतिक परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि एक ओर नवाज़ शरीफ़ हैं, वहीं दूसरी ओर विरोध प्रदर्शन कर रही इन पार्टियों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग (क़ायदे आजम), मजलिस वहदत मुस्लमीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आदि भी नज़र आ रही हैं और वे सब किसी भी तरह अपनी मांगों से पीछे हटने के मूड में नहीं हैं. ज़ाहिर है, यह स्थिति नवाज़ शरीफ़ के लिए समस्याएं खड़ी कर रही है और देश की अर्थव्यवस्था को नुक़सान हो रहा है. क़ौमी असेंबली में विपक्षी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने भी सरकार को निशाना बनाते हुए कहा है कि वह अपनी दिशा दुरुस्त करे. दूसरी ओर कुछ दल तमाम पक्षों के बीच मामलों को बातचीत के ज़रिये हल कराने के लिए सक्रिय हैं, जिनमें जमीअत-ए-इस्लामी, मुत्तेहदा कौमी मूवमेंट आदि शामिल हैं.

अब इस सबसे एक बात तो साफ़ हो जाती है कि लगभग एक साल पहले सत्तारूढ़ हुई मुस्लिम लीग (एन) के लिए दिन-प्रतिदिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और उसे अपनी सत्ता संभालना मुश्किल होता जा रहा है. इस सबके बीच मूल रूप से एक सवाल जन्म लेता है कि अगर अन्य दल सरकार गिराने में सफल हो जाते हैं, तो फिर क्या होगा? क्या आने वाली सरकार जनता की आशाओं पर खरी उतरेगी? इस बात की क्या गारंटी है कि उसे बाकी दलों की ओर से इस प्रकार के विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा? ऐसे तमाम सवाल हर पाकिस्तानी के दिमाग में कौंध रहे हैं. इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक बात तय है कि अगर सरकार विरोधी आंदोलन के नतीजे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) सत्ता से बाहर होती है, तो फिर नई बनने वाली सरकार को भी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा. वजह, अगर आज विरोधी दल सरकार के विरुद्ध संगठित हो सकते हैं, तो कोई शक नहीं कि कल नई सरकार को इन्हीं परिस्थितियों से गुज़रना पड़ जाए और नतीजे में देश इससे भी ख़तरनाक संकट का शिकार होता चला जाए.

अगर ऐसा होता है, तो फिर यह याद रखना चाहिए कि ऐसे किसी भी संकट के परिणाम में देश के किसी राजनीतिज्ञ का कुछ नहीं बिगड़ेगा. नुक़सान होगा, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ग़रीब जनता का, जिसे शायद दो जून की रोटी भी मयस्सर नहीं है. पाकिस्तान में ग़रीबी का आलम यह है कि 18 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 33 प्रतिशत आबादी यानी 5 करोड़ 87 लाख लोग ग़रीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं. एक ग़ैर सरकारी संगठन थिंक टैंक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट जारी की है कि पाकिस्तान की एक तिहाई आबादी भयानक भुखमरी का शिकार है. इसका साफ़ मतलब है कि पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ी समस्या ग़रीबी है, लेकिन सरकार ग़रीबी के ख़िलाफ़ लड़ने की बजाय राजनीतिक उथल-पुथल से जूझ रही है. पाकिस्तान की हालत देखते हुए बेहतर यही है कि एक निर्वाचित सरकार गिराने की बजाय सभी दल, समूह मिल-बैठकर समस्या का हल तलाश करें. एक क़दम सत्तारूढ़ पार्टी को बढ़ाना चाहिए, तो दूसरा क़दम सरकार के विरोध में खड़े दलों एवं नेताओं को. उन्हें अपनी मांगों में संशोधन करके इस संकट से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए.

आर्थिक संकट के अलावा पाकिस्तान की दूसरी बड़ी समस्या आतंकवाद है. पिछले दिनों भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के साथ एक मुलाक़ात के दौरान पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद पर चिंता व्यक्त की थी. अमेरिका को यह सबूत भी मिल गया है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को संरक्षण मिल रहा है. अमेरिका ने पाकिस्तान के उग्रवादी संगठन हरकतुल मुजाहिदीन के संस्थापक एवं जिहादी प्रतिनिधि अफ़ज़ल रहमान ख़लील, लश्कर-ए-तैयबा के मोहम्मद नईम शेख़ और उम्र नईम शेख़ पाकिस्तानी को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों की सूची में शामिल कर लिया है. ज़ाहिर है, इन संगठनों से जुड़े लोग नवाज़ शरीफ़ पर अमेरिकी निर्णय के ख़िलाफ़ दबाव बनाएंगे. यह स्थिति नवाज़ शरीफ़ के लिए एक नई चुनौती है. लांग मार्च पर जिहादी संगठनों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी, लेकिन अब अगर नवाज़ शरीफ़ इस फ़ैसले पर कोई अंतिम निर्णय करेंगे, तो इन संगठनों का झुकाव प्रदर्शनकारियों की ओर हो सकता है. चूंकि पाकिस्तान में इनका नेटवर्क बहुत मज़बूत है, इसलिए यह स्थिति नवाज़ सरकार के ख़िलाफ़ जा सकती है. पाकिस्तान एक के बाद एक, नए-नए संकटों से घिरता जा रहा है, जिससे निबटने के लिए सरकार को बेहद समझदारी भरे क़दम उठाने होंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

जम्मू और कश्मीर

बाढ़ सरकार की अक्षमता उजागर कर गई

हारुन ऋषि

कश्मीर घाटी में भयानक बाढ़ के एक महीने बाद भी उसकी विनाशलीला दिखाई पड़ रही है. श्रीनगर का केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र लाल चौक खंडहर जैसा दिखाई पड़ रहा है. हर तरफ टूटी-फूटी इमारतें, सड़कें देखने को मिल रही हैं. जहां तक निगाह जाती है बस कूड़ा-करकट और सड़ांध फैली दिखाई पड़ती है. इस तरह की तबाही श्रीनगर के तकरीबन पचहत्तर फिसदी हिस्से में देखने को मिल रही है. शहर और देहात के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित सैकड़ों राहत शिविरों में हजारों बाढ़ प्रभावित लोग आज भी रह रहे हैं. जम्मू और कश्मीर सरकार ने बाढ़ से हुए नुक्सान का आकलन करते हुए कहा है कि तकरीबन एक लाख करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई है. इस विनाशकारी बाढ़ की ज़द में आकर लगभग तीन लाख इमारतें ढह गई हैं, जिनमें ढाई लाख रिहाइशी मकान भी शामिल हैं. फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि आम कश्मीरियों को इस नुकसान की भरपाई करने में दशकों लग जाएंगे.

सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि सरकार ने न तो बाढ़ से पहले अपनी जिम्मेदारियां निभाई और न बाद में अपनी जिम्मेदारियों को निभाती दिख रही है. इस बात में कोई संदेह नहीं है कि अगर सरकार ने समय रहते उचित कदम उठाए होते तो शायद श्रीनगर के अधिकांश क्षेत्रों खासतौर पर व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लालचौक को इस तबाही से बचाया जा सकता था. सच्चाई तो यह है कि राज्य में इस विनाशकारी बाढ़ की तबाहियों ने जहां उमर अब्दुल्लाह के नेतृत्व वाली सरकार की अयोग्यता को पूरी तरह बेनाकाब कर दिया है. वहीं इस प्राकृतिक आपदा ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य और विशेष रूप से और एक खास तरह की सोच में असाधारण बदलाव पैदा कर दिया है. कुछ एक अलगाववादी नेताओं को छोड़कर बाक़ी का नेतृत्व(लीडरशिप) इस बाढ़ में अपनी भूमिका निभाने में नाकाम साबित हुई. कश्मीरी नौजवानों और कई जगहों पर सेना के जवानों ने अपनी जान पर खेल कर हजारों बाढ़ प्रभावित लोगों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. अब जाकर श्रीनगर और दूसरे प्रभावित क्षेत्रों में सिसकती ज़िन्दगियां बहाल होने की कोशिश कर रही हैं. सरकार की नाक़ामी आमजनों के लिए बहस का मुद्दा बनी हुई है.

दक्षिणी कश्मीर 7 सितम्बर को बाढ़ की चपेट में आ गया था. बाढ़ ने यहां जिस कदर तबाही मचाई थी उसे देखकर यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता था कि बाढ़ का यह पानी श्रीनगर और घाटी के दुसरे क्षत्रों मेंभी पहुंचेगा और बड़े पैमाने पर तबाही मचाएगा. बावजूद इसके सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही. मुख्यमंत्री या सरकार का कोई पदाधिकारी इस बात का साफ-साफ जवाब नहीं दे पाता है कि सरकार ने समय रहते जनता को बाढ़ से पहले इसकी खबर देने में नाकाम क्यों हो गई? बाढ़ के पानी को दक्षिणी कश्मीर से श्रीनगर पहुंचने के दो दिन पहले सरकार ने बचाव की पहल क्यों शुरू नहीं की. लोग हैरान हैं कि बाढ़ की चपेट में आने वाले क्षेत्रों से लोगों को निकलने के लिए नौकाओं को तैयार क्यों नहीं रखा गया था? आपात सेवाओं को हरकत में क्यों नहीं लाया गया? साथ ही इन विभागों से जुड़े अफसरों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर हाज़िर रहने का आदेश क्यों नहीं दिया गया. झेलम नदी में पानी का स्तर बढ़ते ही पुलिसकर्मी ड्यूटी छोड़कर कैसे और कहां भाग गए? शहर के अस्पतालों से मरीजों को सुरक्षित स्थानों पर क्यों नहीं ले जाया गया? जम्मू के एकमात्र बच्चों के अस्पताल में वेंटिलेटर पर मौजूद नवजात बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर क्यों नहीं निकाला गया? दक्षिणी कश्मीर में बाढ़ आ जाने के बाद ज्यादातर मंत्रियों और अफसरों को अपने-अपने परिवार के साथ जम्मू क्यों भाग जाने दिया गया? झेलम के बांध को वहां से क्यों नहीं तोड़ा गया जहां बाढ़ आने से पहले ही बांध तोड़ने की रवायत रही है? बाढ़ के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह को हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्रों में रोटियां, बिस्किट, केले और पानी की बोतलें फेंकतें हुए देखा गया. आलोचकों का यह सवाल सही है कि क्या एक यह एक मुख्यमंत्री का काम है? जो काम एक पुलिसकर्मी कर सकता था उस काम को करने में मुख्यमंत्री ने अपना समय क्यों बर्बाद किया? उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों को बचाने के लिए दूसरी राज्यों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं की? सच्चाई तो यह है कि सरकार ने बाढ़ से पहले और उसके बाद भी अपनी नाकामी के भरपूर सबूत दिए. हद तो यह है कि बाढ़ से हुई तबाही के एक महीना बीत जाने के बाद भी सरकार अभी तक यह बताने में नाक़ाम साबित हुई है कि घाटी में झेलम नदी में सामान्य रूप से बहने वाले 25 हजार क्यूसेक पानी की बजाय एक लाख 20 हजार क्यूसेक पानी कहां से आ गया? सरकार की उस समय की दयनीय स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक महीना बीत जाने के बाद भी यह ज्यादातर क्षेत्रों में पीने का साफ पानी और बिजली सप्लाई को बहाल करने में नाकाम साबित रही है. आज एक महीना बाद भी घाटी में कैंसर की दवाईयां उपलब्ध नहीं हैं. उमर अब्दुल्लाह के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 6 साल के कार्यकाल में कई ऐसी बातें हुईं जो सरकार को कमजोर और असफल साबित करने के लिए काफी हैं, लेकिन बाढ़ इस सरकार की अक्षमता को सतह पर ले आई. इस भयानक बाढ़ में इंसानी जिंदगियों को बचाने में अगर किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो वह कश्मीर का नौजवान और भारतीय सेना थी. आम कश्मीरी नौजवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर कई प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों को बचाया और उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया. कश्मीरी नौजवान पूरे जोश और मानवीयता के साथ बचाव कार्य जारी रखा. ठीक उसी तरह से फौज ने भी कुछ इलाकों में समय पर बचाव कार्य शुरू कर हज़ारों लोगों की जिंदगी बचाई. हालांकि फौज पर बचाव कार्य के दौरान आम कश्मीरियों के बजाय अपने जवानों और दूसरे राज्यों के मजदूरों और सैलानियों को प्राथमिकता देने के आरोप लगाए जा रहे हैं, बावजूद इसके इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता कि सेना की त्वरित कार्यवाही की वजह से हजारों लोगों की जान बाढ़ में बह जाने से बच गई.

सात सितंबर को श्रीनगर में बाढ़ का पानी घुसने के साथ ही यहां तैनात फौज की 15 वीं कोर के उच्चाधिकारियों की एक मीटिंग हुई. इसके बाद फौज को फौरन बचावकार्य शुरू करने का आदेश दिया गया. फौज ने नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स(राष्ट्रीय आपदा मोचन बल) की सहायता से दूसरे राज्यों के सैड़कों लोगों को दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ पहुंचा दिया. श्रीनगर के हमहमा वायुसेना स्टेशन में हजारों बाढ़ प्रभावितों को पनाह दी गई. कुल मिलाकर सेना ने इस भयानक बाढ़ में आवाम के लिए एक बेहतरीन काम किया. कई अलगववादी नेता भी शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आवाम की मदद करते और लोगों को बचाते दिखे, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि अलगावादी नेताओं में से कई सहायता सामग्री बांटते हुए फोटो खिंचवाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते थे. इस तरह की तस्वीरें सोशल नेटवर्किंग साइट पर अपलोड की जा रहीं थी और स्थानीय अखबारों में छपने के लिए भेजी जा रहीं थीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को मानने के लिए भी सहमत नहीं है कि गांधी जी अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से सर्वश्रेष्ठ थे. इस संदर्भ में, यह नोट करने वाली बात है कि कम से कम प्रधानमंत्री यह मानते हैं कि गांधी की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान शुरू किया. लालकिले से भी उन्होंने गांधी जी का नाम लिया. ऐसे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करेगा, पता नहीं.

आगे बढ़ने के लिए विरोधाभास ख़त्म करने होंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और अब वहां से वापस आ चुके हैं. वह संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करने वहां गए थे. यह अमेरिकी दौरा अमेरिका के साथ द्विपक्षीय वार्ता के लिए नहीं था. दुर्भाग्य से, पूरे भारतीय मीडिया ने इसे ऐसे दिखाया, जिससे इस यात्रा से बहुत अधिक उम्मीदें पैदा हो गईं. द्विपक्षीय संबंध इस तरह से नहीं बनते. वेशक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी अमेरिका ने वीजा देने से इंकार कर दिया था और एक समय यह है, जब उसी अमेरिका ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. न सिर्फ़ भारतीय समुदाय, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी उन्हें डिनर पर आमंत्रित किया. यह सब अच्छा था. हालांकि, जब काम की बात आती है, तो भारतीय प्रधानमंत्री ने काफी अच्छी तरह से भारत के मुद्दों और उसकी चिंताओं को सामने रखा, लेकिन अमेरिका की प्रतिक्रिया वैसी नहीं रही, जैसी भारतीय मीडिया ने दिखाने की कोशिश की. इसके अलावा, हमें पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की समस्या के लिए अमेरिका पर बहुत ज़्यादा निर्भर होने के ख़तरे को लेकर भी सावधान रहना चाहिए. हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी.

भारत 26/11 जैसे हमले के दोषियों को सजा दिलाने के लिए अमेरिका की ओर देखता है, तो यह गलत है. देश में हमारे पास मजबूत सेना, अर्द्धसैनिक बल और सुरक्षा बल हैं. मुंबई में जिस तरीके से ताज और ओबेराय होटल पर हमला किया गया, उससे थोड़ी-सी सतर्कता से आसानी से निपटा जा सकता था. हमारे सुरक्षा बल इसके लिए पर्याप्त थे. इस हमले के दोषियों को भारत लाने और उन्हें सजा देने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालना अच्छी बात है, लेकिन इस सबके लिए अमेरिका पर निर्भरता ठीक नहीं है. ऐसा करके हम अपनी संप्रभुता और गरिमा से ही समझौता करेंगे. आर्थिक मोर्चे की बात करें, तो पैसा उसी दिशा में जाता है, जहां लाभ होता है. मैडिसन स्क्वायर में बड़ी संख्या में अमेरिकी भारतीय लोग इकट्ठा थे. उनमें से कोई भी भारत में निवेश इसलिए नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास स्पष्ट बहुमत के साथ एक सरकार है. निवेश तभी होगा, जब विदेशी निवेशकों को यह लाभदायक लगेगा. ऐसी लाभदायक स्थिति पैदा करने पर ही भारत में कोई भी निवेश करना चाहेगा. हमें इस पर भी विचार करना होगा कि हमें कहां तक विदेशी निवेश की ज़रूरत है, कितने निवेश की ज़रूरत है, वगैरह-वगैरह.

हम उम्मीद करते हैं कि भारत-अमेरिकी संबंध दोनों पक्षों के लिए और अधिक उपयोगी बने. हम ऐसी कामना करते हैं. लेकिन, इससे अधिक अगर हम यह सोचते हैं कि इस एक यात्रा से सभी समस्याओं का हल निकल आएगा, तो यह एक बड़ी गलती होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं. खुशी की बात यह है कि नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को वह स्थान देना चाहते हैं, जिसके गांधी जी हक़दार हैं. नरेंद्र मोदी अक्सर स्वामी विवेकानंद एवं महात्मा गांधी का उल्लेख करते रहते हैं. लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कभी किसी मंच पर गांधी को जगह नहीं दी. यह एक विडंबना है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रुख गांधी को लेकर इतना भर है कि गांधी जी भी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गांधी जी को फादर ऑफ नेशन नहीं मानता.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस बात को मानने के लिए भी सहमत नहीं है कि गांधी जी अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से सर्वश्रेष्ठ थे. इस संदर्भ में, यह नोट करने वाली बात है कि कम से कम प्रधानमंत्री यह मानते हैं कि गांधी की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता अभियान शुरू किया. लालकिले से भी उन्होंने गांधी जी का नाम लिया. ऐसे में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या करेगा, पता नहीं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति पूजा के ख़िलाफ़ है और इसी वजह से वह गांधी के भी ख़िलाफ़ है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इंदिरा गांधी का विरोध भी इसीलिए करता था, क्योंकि कांग्रेस एवं कांग्रेसियों ने इंदिरा गांधी को सर्वोच्च नेता बना दिया था और व्यक्ति पूजा शुरू हो गई थी. लेकिन, विडंबना यह है कि आज भाजपा कैडर नरेंद्र मोदी की जितनी पूजा कर रहा है, उतनी पूजा तो कांग्रेस ने भी कभी इंदिरा गांधी की नहीं की. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीनी माल का बहिष्कार करना चाहता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीमा मुद्दे पर बहुत स्पष्ट होना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ़, नरेंद्र मोदी चीन से दोस्ती चाहते हैं. इन सभी विरोधाभासों को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा. हमें आगे जाना है, क्योंकि हमारे पास एक स्पष्ट बहुमत है. यह भी साफ़ है कि करने के लिए बहुत काम भी हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

साख बनाना और बचाना संपादक का बुनियादी दायित्व

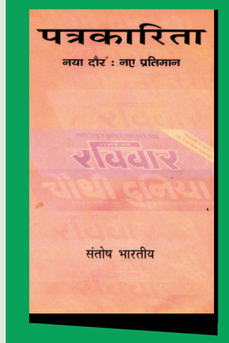

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

अच्छे और ऊर्जावान संपादक को स्वयं में भी स्पष्ट होना पड़ता है. उसे अपनी महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट रूप से पहचाननी चाहिए. क्या वह सचमुच बड़ा या अच्छा संपादक बनना चाहता है या उसके अवचेतन मन में कुछ और चल रहा है. यदि वह अपने मन का विश्लेषण नहीं करता, तो वह हमेशा भ्रमित रहेगा. एक तरह के वे लोग होते हैं, जो समाज और राजनीति को केवल प्रभावित करना चाहते हैं. ऐसे लोग हमेशा पत्रकारिता से जुड़े रहते हैं. कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो पत्रकारिता का सहारा लेकर राजनीति में हिस्सा लेने की आकांक्षा पाले रहते हैं, ऐसे लोग पत्रकारिता में अपनी इच्छाएं मिलाने लगते हैं. तीसरे ऐसे लोग होते हैं, जिनका लक्ष्य ही राज्यसभा होता है. ऐसे लोग ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि वे लोग समाचारों को एक विशेष विचारधारा के चश्मे से देखने लगते हैं तथा उस विचारधारा का कैसे प्रचार हो, इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं. ये चाहे लेख लिखें, चाहे समाचार को एंगल दें या फिर चैनल पर ख़बरें पढ़ें या किसी का साक्षात्कार लें, यह सब एक विशेष उद्देश्य के लिए ही होता है. जब ये राज्यसभा में पहुंचते हैं, तभी ये बिल्कुल असली रूप में होते हैं और तब पता चलता है कि इनकी सारी पत्रकारिता एक दल विशेष की विचारधारा का प्रोपेगंडा भर थी.

ऐसे लोगों की प्राथमिकता पत्रकारिता नहीं होती. अच्छे संपादक की प्राथमिकता पत्रकारिता ही होनी चाहिए, क्योंकि सच का चेहरा बदलने की कोशिश करना पत्रकारिता के पेशे के साथ विश्वासघात करना है. सच के पक्ष में खड़े रहने का अधिकार किसी भी संपादक को है, चाहे वह किसी ज़िले से निकलने वाला अख़बार हो या राजधानी से निकलने वाला अख़बार हो. सच के कई पक्ष नहीं होते, सच का केवल एक पक्ष होता है और वह खुद सच है. सच के पक्ष में खड़ी पत्रकारिता ही संपादक की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए.

संपादक के ऊपर निर्भर करता है कि वह अपने अख़बार, पत्रिका या चैनल की कितनी साख बनाता है. साख बनाने की क्षमता उसकी परीक्षा है. यदि उसकी टीम द्वारा लाई गई रिपोर्ट का खंडन अक्सर छपता है, तो साख बन ही नहीं सकती. संपादक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी क्षेत्र के बारे में गलत रिपोर्ट जाती है, तो भले ही दूसरे क्षेत्र के लोग न जानें, पर उस क्षेत्र के लोग तो सच्चाई जानते हैं, जहां के बारे में गलत रिपोर्ट छपी है. उस क्षेत्र में तो साख पर सवालिया निशान लग ही जाता है. इसीलिए साख बनाना और बनी साख की रक्षा करना संपादक का बुनियादी दायित्व है. रिपोर्ट की साख इससे नहीं बनती, जब वह तुम भी सही, तुम भी सही के सिद्धांत पर लिखी गई हो. अक्सर ज़िम्मेदारी और मेहनत से बचने के लिए संवाददाता ऐसी रिपोर्ट लिखता है, जिसमें दोनों पक्षों की बात होती है तथा संपादक उसे ही पसंद करता है. ऐसी रिपोर्ट पाठकों को कुछ नहीं बता सकती, बस केवल बुनियादी जानकारी ही दे पाती है. साख तब बनती है, जब रिपोर्ट किसी निष्कर्ष पर पहुंची हो और वह निष्कर्ष संवाददाता का हो. इसके लिए संपादक को ही आगे बढ़ना पड़ता है और निर्देश देने पड़ते हैं.

संपादक को इस बात के लिए भी सावधानी बरतनी चाहिए कि जितने शब्दों में बात साफ़ हो सकती है, उससे ज़्यादा शब्द रिपोर्ट में न हों. यह संतुलन कम संपादक साध पाते हैं, क्योंकि आजकल एक नया रुझान देखने में आ रहा है कि उपलब्ध स्थान के आधार पर रिपोर्ट का लेखन और संपादन हो रहा है. होना यह चाहिए कि विषय-वस्तु के आधार पर स्थान का निर्धारण हो. संपादक यदि संवाददाता को स्पष्ट कर दे कि उसे स्पष्ट, लेकिन बढ़ी-चढ़ी नहीं, रिपोर्ट चाहिए, तो संवाददाता उसका ध्यान रखेगा. पर आजकल संवाददाता का संपादक से कम डेस्क से ज़्यादा संवाद होता है, इसलिए वह डेस्क की सुविधानुसार रिपोर्ट का आकार तय करता है. इसकी जगह डेस्क को रिपोर्ट के अनुसार स्थान का आकार तय करना चाहिए.

संपादक और मैनेजर का फर्क स्वयं संपादक नाम की संस्था के लिए आवश्यक है. संपादक मैनेजर के रूप में तब्दील हो जाए, इसके लिए संपादक को ही सचेत रहना होगा. संपादक अपनी टीम की केवल सुख-सुविधा का ध्यान रखे, तो मैनेजर के रूप में बदलते ज़्यादा देर नहीं लगेगी, पर यदि वह अपनी टीम का नेतृत्व करे, तभी वह संपादक के नाते इज्जत पा सकेगा. दरअसल, आज बाज़ार के युग में अच्छी पैकेजिंग वाले संपादक ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो कि अपने संगठन को संपादकीय नेतृत्व कम बाज़ार को समझने वाले व्यक्ति के रूप में ज़्यादा पेश कर रहे हैं. इसीलिए चाहे चैनल हों या अख़बार या पत्रिकाएं, कइयों को जब संपादकीय विषय-वस्तु में प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, तब परेशानी आ जाती है. बाज़ार को समझना एक चीज है और बाज़ार का ही संपादक बनाना बिल्कुल दूसरी. संपादक का काम अलग है और मैनेजर का अलग. यह अलग रहे, तभी पत्रकारिता अपने मूल रूप में लोगों की सेवा कर सकती है. ■

संपादक को इस बात के लिए भी सावधानी बरतनी चाहिए कि जितने शब्दों में बात साफ़ हो सकती है, उससे ज़्यादा शब्द रिपोर्ट में न हों. यह संतुलन कम संपादक साध पाते हैं, क्योंकि आजकल एक नया रुझान देखने में आ रहा है कि उपलब्ध स्थान के आधार पर रिपोर्ट का लेखन और संपादन हो रहा है. होना यह चाहिए कि विषय-वस्तु के आधार पर स्थान का निर्धारण हो. संपादक यदि संवाददाता को स्पष्ट कर दे कि उसे स्पष्ट, लेकिन बढ़ी-चढ़ी नहीं, रिपोर्ट चाहिए, तो संवाददाता उसका ध्यान रखेगा.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

30 नहीं, 70 फ़ीसद आबादी का विकास हो

अमेरिका में नरेंद्र मोदी के भाषणों की काफी तारीफ़ हो रही है. मैं भी उन तारीफ़ करने वालों में शामिल हूं. नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में भारतीयों के सम्मान में इजाफा किया है और इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका दौरा पिछले कई प्रधानमंत्रियों के दौरे से सफल रहा है. नरेंद्र मोदी में अमेरिका में बसे भारतीयों ने एक ऐसे राष्ट्रनेता की छवि देखी है, जिसका कद ओबामा के बराबर है. नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में अमेरिका में बसे भारतीयों का कद बढ़ाया है और इसमें कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका से सफल होकर लौटे हैं.

लेकिन, जिस एक बात ने मुझे थोड़ा चिंतित किया है, वह देश और देश में रहने वाले लोगों के भविष्य के रास्ते की कल्पना को लेकर है. नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में बिल्कुल वैसा भाषण दिया, जैसा अमेरिका में रहने वाले लोग सुनना चाहते थे. नरेंद्र मोदी ने वहां अपने विकास की जिस अवधारणा का वर्णन किया, वह उच्च-मध्यम वर्ग की अवधारणा है. विकास के जिस मॉडल की बात उन्होंने अमेरिका में की, वह उच्च-मध्यम वर्ग के विकास का मॉडल है. साथ ही नरेंद्र मोदी ने मध्यम वर्ग में यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की कि अगर मध्यम वर्ग के लोग चाहें, तो उनके बच्चे भी अमेरिका जा सकते हैं. अमेरिका ही क्यों, सारी दुनिया में जा सकते हैं, क्योंकि सारी दुनिया में वर्क फोर्स की कमी है. नरेंद्र मोदी ने 2019 का ज़िक्र कई जगह किया, इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी 2019 तक इस उच्च-मध्यम वर्ग के विकास की बात करना चाहते हैं, उच्च-मध्यम वर्ग को हिंदुस्तान में कंज्यूमर सेक्टर में अवसर देने की बात करना चाहते हैं और मध्यम वर्ग को यह आशा देना चाहते हैं कि वह चाहे, तो उच्च-मध्यम वर्ग की तरफ़ बढ़ सकता है. इसका बहुत साफ़ अर्थ निकलता है कि नरेंद्र मोदी के दिमाग में हिंदुस्तान के विकास का नक्शा 30 प्रतिशत के विकास का नक्शा है.

मैं चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझने वाले लोग मेरी इस धारणा को ग़लत साबित करें. मैं ग़लत साबित होना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह देश तनाव के उस मुकाम तक पहुंच जाए, जहां से परस्पर एक-दूसरे के प्रति तलवारें खिंच जाती हैं. हिंदुस्तान के 70 प्रतिशत से ज़्यादा लोगों के पास शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, पानी नहीं है और सबसे बड़ी चीज रोटी नहीं है. अगर है, तो तिल-तिल कर मरने के अवसर हैं. मेरे जैसा शख्स नरेंद्र मोदी के मुंह से यह सुनना चाहता है कि अगले पांच साल में हिंदुस्तान में सौ प्रतिशत शिक्षा की व्यवस्था होगी. हम दुनिया में अगर शिक्षक भेजने की बात करते हैं, तो वे शिक्षक उच्च-मध्यम वर्ग के शिक्षक होंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में उच्च शिक्षा की संभावना सिर्फ़ उच्च-मध्यम वर्ग के पास है, मध्यम वर्ग भी वहां पर मुश्किल से पहुंच पा रहा है.

मैं इस बात के लिए लालायित हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कहें कि हिंदुस्तान के गांवों और शहरों में शिक्षा की ऐसी व्यवस्था होगी, जिस शिक्षा को प्राप्त कर लोग दुनिया का मुक़ाबला करने की स्थिति में पहुंच जाएं. देश के सत्तर प्रतिशत लोगों के पास न तो स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंचने की क्षमता है और न स्वास्थ्य सुविधाएं उन तक पहुंच पाती हैं. दवाइयां कहीं से मिल भी जाएं, तो कौन दवाई किस बीमारी में देनी है, यह बताने वाला 70 प्रतिशत लोगों के पास कोई नहीं है. तीसरी सबसे बड़ी बात, जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी का ध्यान दिलाने की आवश्यकता है और मेरे जैसा शख्स प्रधानमंत्री से यह सुनना चाहता है कि हिंदुस्तान के गांवों में कम से कम ऐसे उद्योग लग जाएंगे, जिनका रिश्ता वहां पैदा होने वाले कच्चे माल से होगा. पर दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मिले इस अवसर को गंवा दिया. नरेंद्र मोदी को अमेरिका में हिंदुस्तान की 70 प्रतिशत आबादी के लिए, जो विकास की धारा से बाहर हैं, जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं उद्योग की ज़रूरत है, जो कि बेरोज़गारी का जवाब हैं और खासकर, हिंदुस्तान के गांवों में महामारी की तरह फैली हुई बेकारी का हल ढूंढने का ऐलान करने का अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने उस अवसर को उच्च-मध्यम वर्ग के लिए संभावित अवसरों की घोषणाओं में बदल दिया.

मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बताने की ज़रूरत है कि यदि इन सत्तर प्रतिशत लोगों के पास विकास की गंगा तो दूर, नाला भी नहीं पहुंचा और ये सत्तर प्रतिशत लोग शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोज़गार की संभावनाओं से दूर रहे, तो 30 प्रतिशत लोग जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणाएं की हैं, वे भी आसानी के साथ इन अवसरों का उपयोग नहीं कर पाएंगे. अगर वे इन अवसरों का उपयोग करना चाहेंगे, तो उन्हें सेना की सहायता लेनी पड़ेगी. जिस एक बात को हम बार-बार दोहराते हैं कि अभी भी हिंदुस्तान के एक तिहाई से ज़्यादा ज़िले विकास से दूर हैं और इतने दूर हैं कि वहां पर भारत सरकार का शासन चलता ही नहीं है. और, यह असंतोष क़ानून व्यवस्था की समस्या नहीं है, यह असंतोष विकास की समस्या है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारे देश के लिए विकास का नक्शा कब पेश करेंगे, इसकी प्रतीक्षा मेरे जैसे शख्स को है. इसलिए जब नरेंद्र मोदी अमेरिका में भाषण देते हैं, तो वहां भारतीयों का सिर गर्व से उठ जाता है. लेकिन किन भारतीयों का सिर गर्व से उठ जाता है? उच्च-मध्यम वर्ग के भारतीयों का, जो अमेरिका जा सकते हैं, जो अमेरिका में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और जो अमेरिका में जाकर व्यापार कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी की घोषणाएं उनके लिए हैं. लेकिन, जो अपने गांव से शहर नहीं जा सकता, जिसने टेलीविजन के अलावा देश की राजधानी को नहीं देखा और जिसने अच्छी रेलगाड़ी में यात्रा नहीं की, उसके लिए ये सारी घोषणाएं बेमानी हैं. क्योंकि न वह पढ़ पाता है, न लिख पाता है, न समझ पाता है और न ज़िंदा रहने के लिए बीमारी से लड़ पाता है.

ये सवाल आज उठाना नक्कारखाने में तूती की आवाज़ सरीखा हो सकता है, पर पत्रकारिता चापलूसी नहीं है, पत्रकारिता पीआर जर्नलिज्म नहीं है. पत्रकारिता सही समस्या की तरफ़ ध्यान दिलाने का नाम है. आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं और इस बात की आशा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी एक भाषण तो ऐसा दें, जो देश के सत्तर प्रतिशत से ज़्यादा लोगों के मन में आशा का संचार कर सके. इस सत्तर प्रतिशत लोगों में देश के दबे-कुचले, वंचित, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े यानी हर वर्ग के लोग शामिल हैं. इनमें वे भी शामिल हैं, जिन्हें बड़ी जाति का कहा जाता है.

ये सवाल आज उठाना नक्कारखाने में तूती की आवाज़ सरीखा हो सकता है, पर पत्रकारिता चापलूसी नहीं है, पत्रकारिता पीआर जर्नलिज्म नहीं है. पत्रकारिता सही समस्या की तरफ़ ध्यान दिलाने का नाम है. आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं और इस बात की आशा करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी एक भाषण तो ऐसा दें, जो देश के सत्तर प्रतिशत से ज़्यादा लोगों के मन में आशा का संचार कर सके. इन सत्तर प्रतिशत लोगों में देश के दबे-कुचले, वंचित, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े यानी हर वर्ग के लोग शामिल हैं. इनमें वे भी शामिल हैं, जिन्हें बड़ी जाति का कहा जाता है. हमारे देश के आर्थिक विकास की सड़क पर हर एक को चलने का मौक़ा मिले, इसे सुनिश्चित सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार कर सकती है. अभी जो भी चल रहा है, वह बाज़ार के ऊपर निर्भर होकर चल रहा है. बाज़ार लोगों को रोटी नहीं देना चाहता, बाज़ार रोटी कमाना चाहता है. बाज़ार लोगों को शिक्षित नहीं करना चाहता, बाज़ार शिक्षा को और बड़ा व्यवसाय बनाना चाहता है. बाज़ार लोगों को ज़िंदा नहीं रखना चाहता, बल्कि ज़िंदा लोगों को अपने लिए गुलाम बनाना चाहता है. इस तथ्य को अगर मनमोहन सिंह ने नहीं समझा, तो क्या नरेंद्र मोदी भी इस तथ्य को नहीं समझेंगे? नरेंद्र मोदी अगर सारे देश को बाज़ार के हवाले करने का फ़ैसला करेंगे, तो उन्हें इस बात के लिए भी तैयार होना चाहिए कि देश में अव्यवस्था, शोषण, भ्रष्टाचार, बेरोज़गारी, महंगाई, भूख और मौत के सवालों को लेकर अगर नौजवानों के आंदोलन हुए, तो उनका सामना वह कैसे करेंगे? क्या ऐसे आंदोलनों का सामना गोलियों से होगा या फिर लोगों की पीड़ाओं का समाधान करने से होगा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बात और अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि यदि वह समस्याओं से भागने वाली पूर्ववर्ती सरकारों का अनुसरण करेंगे, तो वह देश के वैसे ही प्रधानमंत्री साबित होंगे, जैसे राजीव गांधी 404 सांसदों के विशाल बहुमत से बने प्रधानमंत्री अपने आख़िरी दिनों में साबित हुए. मैं दोनों की तुलना नहीं कर रहा हूं. मेरा मानना है कि आज नरेंद्र मोदी के पास बहुत कुछ करने का अवसर है, लेकिन अगर वह निहित स्वार्थों, कॉरपोरेट और बाज़ार के रखवाले बन जाएंगे, तो उनके लिए इतिहास में अपनी जगह बनाना मुश्किल होगा. लेकिन, मैं आशा करता हूं कि नरेंद्र मोदी देश को बाज़ार के हवाले नहीं करेंगे और देश की सत्तर प्रतिशत जनता को विकास की धारा में शामिल करने के लिए जी-जान लगा देंगे. हालांकि, अमेरिका में दिया गया उनका भाषण 30 प्रतिशत को बहुत उत्साहित करने वाला है, लेकिन 70 प्रतिशत को बहुत निराशा देने वाला है. ■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

हमने यूजीसी को ब्रिटिश ढांचे से उठाया है, लेकिन सिर्फ़ शब्दों में, आत्मा से नहीं. यूनिवर्सिटी को इस बात की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वे शिक्षकों को रख सकें और अपने हिसाब से शोध करा सकें. यह गुणवत्ता को बढ़ाता है. इंग्लैंड में शिक्षा को लेकर समय-समय पर सुधार होते रहे हैं. भारत में अच्छे लड़के अगर शोध करना चाहते हैं, तो विदेश का रास्ता अख्तियार करते हैं, जहां वे अच्छा और ईमानदार प्रयास कर सकें, जहां उन्हें अपने विभाग प्रमुख की चापलूसी नहीं करनी पड़ती. वे अपने अच्छे काम के प्रति समर्पित होते हैं, न कि अपने वरिष्ठों को अच्छे उपहार देने में दिमाग़ लगाते हैं.

विश्वस्तरीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला और निम्नस्तरीय विश्वविद्यालय होने के बीच ज़रूर कुछ गड़बड़ी हो रही है. क्या इसका कारण यह है कि इन शोध संस्थानों को अपने मन का काम करने की खुली छूट है, क्या स्वायत्त होना काबिलियत की मुख्य वजह है और क्या यूजीसी ने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को ब्यूरोक्रेटिक बना दिया है, जहां काबिलियत के आधार पर कोई पदोन्नति नहीं दी जाती है.

मंगल मिशन की कामयाबी

मंगल मिशन की जबरदस्त सफलता के लिए आज़ादी के बाद के भारत के युवा नेतृत्व को धन्यवाद दिया जाना चाहिए. गांधी मशीनों व आधुनिकता से जुड़ी किसी भी चीज के विरोधी थे, लेकिन जवाहर लाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता आधुनिकवाद, विज्ञान और तकनीक के पक्षधर थे. वे पश्चिमी तकनीक को लेकर हेयदृष्टि नहीं रखते थे और न परंपरावादियों की उन बातों से इत्तेफाक रखते थे, जिसमें कहा जाता था कि प्राचीन भारत के पास वे सभी आधुनिक तकनीक और विज्ञान आदि पहले से मौजूद थे. असल मुद्दा यह नहीं है कि हमारे पास पुष्पक विमान मौजूद था, बल्कि यह है कि ऐसे सौ विमान बनाने की फैक्ट्रियां कहां मौजूद थीं.

बोस और नेहरू चाहते थे कि आज़ादी के बाद भारत का जितना जल्दी हो सके, औद्योगीकरण हो जाए. भारत के भविष्य के लिए वर्ष 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना भी की गई थी. उस समय हमें किसी भी फिल्म को देखने के पहले न्यूज रील देखनी ही पड़ती थी. नेहरू भारत को वैज्ञानिक एवं तार्किक रूप से विकसित करना चाहते थे. पंडित जी अपनी ही शैली में मॉडर्न इंडिया की स्पिरिट के बारे में बताते थे. वह रिसर्च संस्थाओं की स्थापना की बात करते थे, जबकि बहुत-से लोग उस समय कहा करते थे कि हमारे जैसे देश के लिए यह एक विलासिता की चीज होगी. नेहरू ने ही होमी भाभा, विक्रम साराभाई एवं अन्य दूसरे वैज्ञानिकों को दुनिया के साथ प्रतियोगिता करने के लिए उत्साहित किया. भारत ने उस समय अपने सैटेलाइट सेट करने शुरू कर दिए, जब देश में रेलगाड़ियां कभी-कभार ही समय पर आया करती थीं. उनकी भावनाएं सही थीं. प्रोग्रेस नॉन लिनियर होती है. अगर आपको दूसरे को पीछे छोड़ना है, तो तेजी से आगे बढ़ना होगा. अच्छे शोध संस्थान खड़े करने के लिए लंबा समय लगता है और ऐसे लोग चाहिए होते हैं, जो अपने काम को प्यार करते हों. वे अपनी पूरी मेरिट और क्षमता के साथ काम करें. ऐसे लोग वास्तविक कर्मयोगी होते हैं. कोई भी उनकी खुशी देख सकता था, जब मंगल मिशन कामयाब हुआ. यह काम होने तक और उसके बाद भी उन्होंने डींगे नहीं मारीं. उनकी सोने की बड़ी-बड़ी प्रतिमाएं भी नहीं लगेंगी. इस तरह का कठिन और बेहतरीन काम पूरा करने का आनंद शब्दों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है. जो इस तरह के कार्य करते हैं, सिर्फ़ वे ही जानते हैं कि आख़िर इन्हें पूरा करने के बाद कैसा आनंद आता है.

लेकिन दुःखद रूप से भारत की एक भी यूनिवर्सिटी शीर्ष 200 में नहीं है. यह ऐसी संस्कृति है, जो मेरिट की बजाय उम्र को तरजीह देती है, सामान्य समझ वालों को अच्छे पदों पर बने रहने देती है. यूजीसी के ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशन आते रहते हैं. और भी ऐसी कई संस्थाएं हैं, जिन्हें काबिलियत से कोई मतलब नहीं है. वे केवल नियमों की खानापूर्ति भर कर रही हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्नातक डिग्री को चार वर्षीय बनाने का मामला सारी कहानी कह देता है. दरअसल, शिक्षा में किसी भी तरह के प्रयोग की आज्ञा नहीं है. अगर आपका तर्क मीडिया के अनुरूप नहीं होगा, तो मामले में तुरंत राजनीतिक हस्तक्षेप होता है और किसी भी नए प्रयोग को दबा दिया जाता है.

हमने यूजीसी को ब्रिटिश ढांचे से उठाया है, लेकिन सिर्फ़ शब्दों में, आत्मा से नहीं. यूनिवर्सिटी को इस बात की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कि वे शिक्षकों को रख सकें और अपने हिसाब से शोध करा सकें. यह गुणवत्ता को बढ़ाता है. इंग्लैंड में शिक्षा को लेकर समय-समय पर सुधार होते रहे हैं. भारत में अच्छे लड़के अगर शोध करना चाहते हैं, तो विदेश का रास्ता अख्तियार करते हैं, जहां वे अच्छा और ईमानदार प्रयास कर सकें, जहां उन्हें अपने विभाग प्रमुख की चापलूसी नहीं करनी पड़ती. वे अपने अच्छे काम के प्रति समर्पित होते हैं, न कि अपने वरिष्ठों को अच्छे उपहार देने में दिमाग़ लगाते हैं.

विश्वस्तरीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला और निम्नस्तरीय विश्वविद्यालय होने के बीच ज़रूर कुछ गड़बड़ी हो रही है. क्या इसका कारण यह है कि इन शोध संस्थानों को अपने मन का काम करने की खुली छूट है, क्या स्वायत्त होना काबिलियत की मुख्य वजह है और क्या यूजीसी ने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को ब्यूरोक्रेटिक बना दिया है, जहां काबिलियत के आधार पर कोई पदोन्नति नहीं दी जाती है. जब आपके पास एमबीए के अच्छे छात्र हैं, युवा उद्यमी मौजूद हैं, तो उच्च शिक्षा व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं किया जा सकता? ■

feedback@chauthiduniya.com

स्वयं सहायता समूह से संवरते परिवार

चौथी दुनिया ब्यूरो

राजस्थान के शेख़ावाटी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह का आग़ाज़ मोरारका फाउंडेशन ने वर्ष 1993 में किया था. पहले स्वयं सहायता समूह का गठन नवलगढ़ के निकट घोड़ीवारा खुर्द में हुआ था. समूहों के गठन के लिए क्षेत्र के ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का सर्वेक्षण मोरारका फाउंडेशन ने नवलगढ़ क्षेत्र के विभिन्न गांवों में किया. सर्वेक्षण की मदद से गांव की निर्धन महिलाओं की समस्याओं के बारे काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई. प्रारंभ में दस गांवों में 50 स्वयं सहायता ग्रुप गठित किए गए. वर्ष 2000 में मोरारका फाइंडेशन ने नाबार्ड(नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट) की सहायता से 100 स्वयं सहायता समूहों का 35 गांवों में गठन किया. इसके बाद वर्ष 2003 में केयर आर्गनाइज़ेशन के साथ काम करते हुए 200 समूहों का गठन किया गया. समूह की महिलाओं को वर्मी कंपोस्ट बनाने, जूतियां बनाने, सिलाई कढ़ाई, दरी बनाना, गालीचा बनाना, बूंदी बांधना, लाख की चूड़ियां बनाने , अचार, पापड़ व मगोड़ी बनाने, कपड़े के बैग और पायदान आदि बनाने का प्रशिक्षण दिया गया. इससे इन महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आया. वर्ष 2004 में 50 समूहों का गठन किया गया और यूनिसेफ़ की सहायता से इंवान समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को छोटे–छोटे कामों का प्रशिक्षण दिया गया.

समूह की महिलाओं के बच्चों के लिए स्कूल खोलकर उन्हें शिक्षा से जोड़ा गया. समूह की महिलाओं को बैंकों से क़र्ज़ दिलवाया गया. इन समूहों से जुड़ी हुई गांव की महिलाओं को उनके गावों में प्रशिक्षण दिया गया. जिन गावों में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया उसमें घोड़ीवाड़ा, मुकुंदगढ़, जांटवाली, मोहब्बत श्री, सेंसवास, चूड़ी, अजीतगढ़, पंजी का बास, मीठा वास, कसीरो, नवां, हमीरवास, जीतास, तीतरा, सांगांसी, मांडासी, गमीघाल, ओराड़ी, फतहश्री, हमीरवास, दोड़ीयो की ठानी, बाय, बैरोली, नौलड़ी, चीलासी, बलवंतपुरा. झांझड़, गोठड़ा, मोहनवाड़ी, झांझड़ियों की ढाणी, चीनगढ़, प्रसारामपुरा आदि शामिल हैं. 2010 में 65 गांवों में स्वयं सहायता समूहों का काम अमल में आया है. इसके तहत 117 समूह बनाए गए.

अब तक कुल 517 स्वयं सहायता समूह बनाये जा चुके हैं, जिनमे 100 समूह दो चार महीने चलने के बाद समूह के सदस्यों की आपसी समस्याओं की वजह से बंद हो गए और 115 समूह 6 महीने चलकर बंद हुए. इनमें से 100 ग्रुप केयर के द्वारा से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाये जा रहे हैं और इससे जुड़ी महिलाएं समृद्धि की ओर क़दम बढ़ा रही हैं. वर्तमान समय में फाउंडेशन के पास 181 समूह हैं. जिनमें 2800 महिलाओं के परिवार लाभप्रद हो रहे हैं. समूह को बैंक से आज तक कुल क़र्ज के रूप में एक करोड़ 99 लाख रुपये दिए गए हैं. समूह का कुल आपसी अंतरिम लोन पांच करोड़ 41 लाख 50 हज़ार रुपये है. इस लोन को महिलाएं छोटी–छोटी किस्तों में चुका रही हैं.

समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है. इनकी शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि हुई है. साथ ही महिलाएं छोटी-छोटी बचत करने लगी हैं. इन्हें साहूकारों के क़र्ज़ से निजात मिली है. समूह से जुड़ने से आपसी मेल–मिलाप बढ़ा है और महिलाओं ने खुद का कारोबार शुरू करके अपना नाम रोशन किया है. मोरारका फाउंडेशन का लक्ष्य है कि इन समूहों को 100 गांवों और 15 हज़ार परिवारों तक पहुंचाया जाए ताकि अधिक से अधिक परिवारों को स्वयं सहायता समूह का लाभ मिल सके.

समूह से जुड़ने के बाद महिलाओं की आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है. इनकी शिक्षा और ज्ञान में वृद्धि हुई है. साथ ही महिलाएं छोटी–छोटी बचत करने लगी हैं. इन्हें साहूकारों के क़र्ज़ से निजात मिली है. समूह से जुड़ने से आपसी मेल–मिलाप बढ़ा है और महिलाओं ने खुद का कारोबार शुरू करके अपना नाम रोशन किया है. मोरारका फाउंडेशन का लक्ष्य है कि इन समूहों को 100 गांवों और 15 हज़ार परिवारों तक पहुंचाया जाए ताकि अधिक से अधिक परिवारों को स्वयं सहायता समूह का लाभ मिल सके. इन समूहों से जुड़ी महिलाएं इसका ख़ूब फ़ायदा उठा रही हैं और इस समूह से जुड़ने के बाद उनका घर भी खुशहाली से चल रहा है. मुकुंदगढ़ में की एक महिला पूनम देवी स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं उन्होंने बताया कि उन्हें अपने बच्चों का स्कूल में दाख़िला करवाने के लिए के लिए 5 हज़ार रुपये की आवश्यकता थी. अगर वह यह क़र्ज़ किसी साहूकार से लेने जातीं तो न तो उन्हें समय पर पूरा पैसा नहीं मिलता. यदि मिल भी जाता तो इसका सूद चुकाते–चुकाते सालों गुज़र जाते और मूल की रक़म जस की तस रह जाती लेकिन इस समूह के माध्यम से मुझे बैंक से तुरंत ज़रूरी पैसा मिल गया और इसका ब्याज भी बहुत कम था जिसे चुकता करना हमारे लिए मुश्किल नहीं था. लिहाज़ा, हमने थोड़ा–थोड़ा करके पूरा क़र्ज़ चुका दिया.

इसी गांव की एक दूसरी महिला रामा देवी कहती हैं कि उनके पति बीमार रहते हैं. वह काम नहीं कर पाते थे, इस वजह से घर की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी. मुझे मोरारका फाउंडेशन की मदद से चलाए जा रहे समूह के बारे में पता चला. मैं उसकी सदस्य बन गई. फिर हमें वहां से पांच हज़ार का क़र्ज़ कम ब्याज़ पर बैंक से दिलाई गई. मैंने इस पैसे से एक किराने की दुकान खोल ली. अब इससे इतनी आमदनी हो जाती है कि बैंक का क़र्ज़ भी चुका रही हूं और घर का ख़र्च भी ठीक तरह से चल रहा है.

इसी प्रकार बलबंतपुरा में एक महिला संतोष हैं. उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी. उनका तीन वर्षीय बेटा बीमार रहता था, इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही थी. इनकी इस स्थिति को देखते हुए साल 2009 में सलासर स्वयं सहायता समूह की बैठक में उन्हें बुलाया गया और वहां उपस्थित मोरारका फाइंडेशन की विनोद देवी ने उन्हें स्वयं सहायता समूह के महत्व के बारे समझाया. बात उनकी समझ में आई और वह समूह की सदस्य बन गईं. समूह का सदस्य बनने के बाद उन्हें बैंक से 35 हज़ार रुपये का क़र्ज़ दिलाया गया. इस कर्ज़ से उन्होंने एक गाय ख़रीदी और शेष राशि से बेटे का उपचार कराया और कुछ पैसों और खल और चूरी बनाने का काम शुरू किया. गाय प्रतिदिन 15 से 17 लीटर दूध देती थी. इस दूध में 13 से 14 लीटर दूध डेरी को बेच देतीं और इससे प्राप्त होने वाले पैसों से बैंक का कर्ज़ चुकातीं और कुछ बचाकर अपना घरेलू ख़र्च चलातीं. इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उनके बच्चे का ईलाज भी सही तरीक़े से हुआ, लिहाज़ा वह भी स्वस्थ हुआ. अब इनकी जिन्दगी में समृद्धि आ गई है और वह किसी के कर्ज़ के दबाव में नहीं हैं. पहला कर्ज़ अदा करने के बाद उन्होंने अक्टूबर 2011 में बैंक से दोबारा लोन लिया, जिससे उन्होंने एक और गाय ख़रीद ली. इस दौरान इन्होंने दूध बेचने का काम जारी रखा और बैंक के दूसरे कर्ज़ को भी चुका दिया. वह कहती हैं कि यदि मोरारका फाउंडेशन मेरे जीवन में न होता तो मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रहता और मैं परेशानी में जिंदगी गुजार रही होती.

एक और अन्य महिला सरोजा जो मुकुंदगढ़ की निवासी हैं. उन्होंने 2012 में ज्योति स्वयं सहायता समूह का गठन किया. मोरारका फाउंडेशन की ओर से महिलाओं को इस समूह में शामिल होने की प्रेरणा दी गई. नतीजातन 13 महिलाएं इसकी सदस्य बनीं. इन सदस्यों में एक सरोज भी थीं. समूह ने सरोज को बैंक से 15000 रुपये का कर्ज़ दिलाया. इस पैसे से सरोज ने सब्ज़ी का ठेला लगाकर अपने पति को दिया और 5 हज़ार रुपये से अपने लिए सिलाई मशीन ख़रीदी और घर पर सिलाई का काम शुरू किया. उनका कहना है कि मैं और मेरे पति बेरोज़गार थे लेकिन समूह से जुड़ने के बाद हम दोनों को रोज़गार मिल गया. अब दोनों की कमाई से दिन अच्छे गुज़र रहे हैं. सरोज का कहना है कि मोरारका फाउंडेशन ने हमें दूसरों की गुलामी से निजात दिलाई.

इसी प्रकार मुकुंदगढ़ की ही कमला देवी ने गणेश स्वयं सहायता समूह की मदद से बैंक से वर्ष 2009 में 40 हज़ार का कर्ज़ लिया. जिसमें से 15 हज़ार रुपये में एक गधा गाड़ी बनवाकर अपने बेटे को दी और 20 हज़ार रुपये से कबाड़ का काम शुरू किया और अब इनके जीवन में समृद्धि आ गई है. इनका कहना है कि यही क़र्ज़ अगर वह किसी साहूकार से लेतीं तो इसका मूल और सूद एक साथ चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता. इसी प्रकार अन्य बहुत सी महिलाएं हैं, जिन्होंने स्वयं सहायता समूह की मदद से बैंक कर्ज़ लेकर छोटे–छोटे काम करके अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाकर खुशहाल जीवन जी रही हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

ब्रेन कैंसर

सही समय पर सही इलाज से बचाव संभव है

मस्तिष्क (ब्रेन) और रीढ़ की हड्डी (स्पाइन) से संबंधित कैंसर के मामलों में बीते कुछ सालों में काफी इजाफा हुआ है. अक्सर ऐसा देखा गया है कि शरीर के दूसरे अंगों में होने वाले कैंसर जैसे फेफड़ों और स्तन के कैंसर भी ब्रेन और स्पाइन को सेकंडरी कैंसर के रूप में प्रभावित करते हैं. ब्रेन कैंसर की प्रारंभिक अवस्था को ग्लाइयोमा कहते हैं. ब्रेन कैंसर के सभी मामलों में लगभग 80 प्रतिशत मामले ग्लाइयोमा से ही संबंधित होते हैं. सामान्य रूप से ऐसा देखा गया है कि प्राइमरी स्टेज का ब्रेन कैंसर बच्चों के सिर के पिछले भाग में और वयस्कों के सिर के आगे के भाग में ज्यादा होता है. ब्रेन कैंसर होने के कई कारण हैं. ब्रेन कैंसर आमतौर पर किसी गंभीर बीमारी के कारण होता है तो कई बार आपकी लापरवाही से ब्रेन सेल्स नष्ट होने लगता है. ब्रेन कैंसर होने का अर्थ है कि आपके दिमाग में ट्यूमर लगातार बढ़ रहा है. ब्रेन में अनियंत्रित कोशिकाएं ब्रेन सेल्स के आसपास तेजी से फैलती है जो कि कैंसर का रूप धारण करती रहती हैं, जिसे शल्य चिकित्सा द्वारा हटाना भी मुश्किल होता है.

ब्रेन कैंसर की अवस्थाएं

स्टेज 1

ब्रेन कैंसर की वह सामान्य स्थिति होती है जिसकी रोकथाम आसानी से की जा सकती है. इस स्थिति में कोशिकाओं का विकास बहुत धीरे –धीरे होता है. ट्यूमर दिमाग से शरीर के दूसरे हिस्से में नहीं फैलता है. इस स्टेज को आसानी से सर्जरी के जरिए स्कल को खोलकर ट्यूमर को हटाया जा सकता है.

स्टेज 2

ब्रेन कैंसर की इस स्थिति में घातक ब्रेन सेल्स शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगते हैं. अगर इसका निदान नहीं किया गया तो ट्यूमर बढ़ने लगता है और घातक साबित हो सकता है. कीमोथेरेपी के जरिए इस अवस्था का इलाज संभव है.

स्टेज 3

ब्रेन कैंसर की इस स्थिति में ट्यूमर परिपक्व होकर आक्रामक हो जाता है. घातक कैंसर सेल्स तेजी से फैलकर शरीर के अन्य हिस्सों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं. दिमाग को शरीर के अन्य संकेतों को पहचानने में दिक्कत होने लगती है. आदमी को शरीर का संतुलन बनाने में दिक्कत होने लगती है. बुखार और उल्टी लगातार होने लगती है. रेडिएशन थेरेपी के जरिए इस स्टेज का इलाज कुछ हद तक संभव है.

स्टेज 4

यह ब्रेन कैंसर की आखिरी अवस्था होती है. इसमें ट्यूमर पूर्णतया विकसित होकर शरीर को पूरी तरह से क्षति पहुचाने लगता है. घातक उतकों की पहचान मेडिकल जांच के द्वारा भी मुश्किल से हो पाती है. कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और लेजर थेरेपी द्वारा इस स्टेज पर इलाज के लिए सुझाव दिया जा सकता है.

ब्रेन टयूमर के लक्षण

अभी तक ब्रेन ट्यूमर के कारणों का सही–सही पता नहीं चल पाया है. पर चिकित्सकों के अनुसार नीचे बताए गए लक्षणों में से अगर कोई भी लक्षण आपको दिखाई दे, तो तुरंत किसी न्यूरो सर्जन से संपर्क करें. कभी–कभी मिरगी के दौरे के सामान दौरा पड़ता हो या बेहोशी आती हो, सिर में असहनीय दर्द होता हो, हाथ–पैरों में ऐंठन हो, ज्यादा कमजोरी का एहसास हो, सुबह के समय सिर में अक्सर दर्द होता हो या दृष्टि का अचानक कम होना या कलर ब्लांइडनेस. ब्रेन कैंसर के लक्षण दो बातों पर निर्भर करते हैं कि इसका आकार कितना बड़ा है और यह ब्रेन के किस भाग में स्थित है. फिर भी इस कैंसर के कुछ लक्षण ये हैं, सिरदर्द और जी मिचलाना, बेहोशी छा जाना या फिर कोमा में चले जाना, बच्चों व वयस्कों के सामान्य व्यवहार में परिवर्तन, याददाश्त में कमजोरी आना व मिरगी के दौरे पड़ना.

निदान

कैट स्कैन और एमआरआई समय पर कराने से रोग सामने आने लगा है. पहले यह जांच और परीक्षण बड़े–बड़े शहरों और उनमें भी मुख्य अस्पतालों तक सीमित थे. आज उनका क्षेत्र व्यापक हो गया है.

नवीनतम उपचार

सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी द्वारा ब्रेन कैंसर का प्राथमिक उपचार किया जाता है. सेकंडरी ब्रेन कैंसर में रेडियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है. इसके अंतर्गत सर्वाधिक नवीनतम इलाज गामा नाइफ और साइबर नाइफ नामक मशीनों के द्वारा दिमाग व स्पाइन के कैंसर प्रभावित भागों पर विकिरण के जरिये किया जाता है. वैसे प्राइमरी कैंसर के मामलों का इलाज भी गामा नाइफ और साइबर नाइफ द्वारा किया जाता है.

स्पाइन कैंसर: कैंसर से प्रभावित अन्य अंगों का प्रतिकूल असर जब स्पाइन पर पड़ता है, तो इस स्थिति से उत्पन्न हुए रोग को सेकंडरी स्पाइन कैंसर कहते है. ऐसे कैंसर के मामले कुछ ज्यादा ही सामने आते हैं. स्पाइन कैंसर के सर्वाधिक सामने आने वाले लक्षणों में स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन नर्व का प्रभावित होना है. इस कैसर के कुछ अन्य लक्षण इस प्रकार हैं, हाथ–पैरों में कमजोरी महसूस करना, सुन्नपन और मल–मूत्र की क्रिया में तकलीफ महसूस करना, रीढ़ की हड्डी में कमजोरी के कारण गर्दन, कमर या पीठ में असहनीय दर्द होना.

उपचार

स्पाइन कैंसर का इलाज मिनिमल इनवेसिव डिकम्प्रेशिव सर्जरी से किया जाता है. इसके साथ ही स्पाइन को मजबूत करने के लिए स्क्रू व रॉड आदि का प्रयोग (इंस्ट्रूमेंटेशन) भी इलाज की एक विधि है. उपचार की प्रक्रिया में रेडियोथेरेपी व कीमोथेरेपी का भी प्रयोग किया जाता है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

एक विशेष व्यवस्था के तहत हांगकांग के चीफ़ एक्ज़ीक्यूटिव (मुख्य कार्यकारी) का चुनाव किया जाता है. इस व्यवस्था में 1200 व्यवसायी या अन्य प्रभावशाली लोगों का एक निर्वाचन मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो मुख्य कार्याकारी का चुनाव करते हैं. हांगकांग की पहचान एक वैश्विक महानगर और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र होने के साथ–साथ एक उच्च विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की है.

हांगकांग में लोकतंत्र की चिंगारी

चौथी दुनिया ब्यूरो

हांगकांग, वर्तमान में आधिकारिक तौर पर पीपुल्स रिपब्लिक चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है. एक व्यापारिक बंदरगाह के रूप में आबाद होने के बाद हांगकांग 1842 में ब्रिटेन का विशेष उपनिवेश बन गया था. वर्ष 1983 में इसे एक ब्रिटिश डिपेंन्डेंट क्षेत्र के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था. वर्ष 1997 में ब्रिटेन ने चीन के हाथ हांगकांग की संप्रभुता हस्तांतरित कर दी थी. इसके बाद चीन ने इसे एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र का दर्जा दिया. वर्तमान में हांगकांग में स्थानीय लोगों के पास प्रत्यक्ष तौर पर सरकार चुनने का अधिकार नहीं है लेकिन उनके पास अभिव्यक्ति और विरोध का अधिकार है. फिलहाल एक विशेष व्यवस्था के तहत हांगकांग के चीफ़ एक्ज़ीक्यूटिव (मुख्य कार्यकारी) का चुनाव किया जाता है. इस व्यवस्था में 1200 व्यवसायी या अन्य प्रभावशाली लोगों का एक निर्वाचन मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो मुख्य कार्याकारी का चुनाव करते हैं. हांगकांग की पहचान एक वैश्विक महानगर और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र होने के साथ–साथ एक उच्च विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की है. चीन की एक देश दो नीति के अंतर्गत हांगकांग को बुनियादी क़ानून के अनुसार अधिकांश क्षेत्रों में उच्च स्तर की स्वायत्तता प्राप्त है. केवल विदेशी मामलों और रक्षा की जिम्मेदारी चीन की सरकार की है. हांगकांग की अपनी मुद्रा, कानून प्रणाली, राजनीतिक व्यवस्था, अप्रवास पर नियंत्रण, सड़क नियम हैं. यहां के लोगों की जीवन शैली चीन की जीवनशैली से अलग है. गहरे प्राकृतिक बंदरगाह के लिए प्रख्यात हांगकांग की पहचान एक ऐसे महानगरीय केंद्र की है जहां के भोजन, फिल्मों, संगीत और परंपराओं में पूर्व और पश्चिम का मिलन होता है. हांगकांग की आबादी 70 लाख है. यहां रहने वाले 95 प्रतिशत लोग हान समुदाय के और 5 प्रतिशत लोग अन्य समुदायों के हैं. 1,054 वर्ग किमी क्षेत्रफल में फैला हांगकांग दुनिया के सबसे धनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है.

क्यों हो रहा है विरोध प्रदर्शन ?

हांगकांग का नया नेता चुनने के लिए साल 2017 में होने वाले चुनाव में उम्मीदवारी के लिए चीन ने नियम निर्धारित किए हैं. ये नियम अगस्त,2014 में चीन की संसद की स्थाई समिति ने पारित किए हैं उनके तहत उम्मीदवारों को नामांकन समिति में बहुमत से समर्थन हासिल करना होगा. सिर्फ़ दो या तीन उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं. इसका मतलब नए नियमों के मुताबिक चीन के अनुमोदन के बाद ही कोई उम्मीदवार हांगकांग के चीफ़ एक्ज़ीक्यूटिव का चुनाव लड़ सकता है. इसमें किसी अन्य को अपनी दावेदारी पेश करने की इजाज़त नहीं होगी. चुनाव के बाद भी निर्वाचित चीफ एग्जीक्यूटिव को पदस्थ करने के लिए चीन की संसद का औपचारिक तौर पर अनुमोदन जरुरी होगा. लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता इसके विरोध में हैं. उनका कहना है कि 1997 में हांगकांग को चीन को सौंपने से वर्षों पहले चीनी नेताओं ने हांगकांग के लोगों से एक व्यक्ति–एक वोट का वादा किया था. लेकिन हांगकांग में ऐसा नहीं है और न ही ऐसा हो रहा है. हांगकांग में लोग सार्वभौमिक मताधिकार चाहते हैं. इसका मतलब यह कि मतदाताओं को तमाम राजनीतिक विचारधाराओं के उम्मीदवारों में से अपना नेता चुनने का अधिकार हो. लेकिन चीन हांगकांग के लोगों को उसके द्वारा चुने गए लोगों में से किसी एक को चुनने को कह रहा है. अब हांगकांग के लोग आरोप लगा रहे हैं कि चीन हांगकांग में सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने के अपने वादे से पीछे हट रहा है. इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा है कि चीन ने समझौते की भावना का उल्लंघन किया है. इसी वजह से लोगों ने आंदोलन की राह पकड़ी है और चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. लोग अंतरराष्ट्रीय मानकों और मापदंडों के आधार पर अपना नेता चुनना चाहते हैं लेकिन चीन ऐसा नहीं करने देना चाहता है. चीन हांगकांग में सीमित लोकतंत्र देना चाहता है, जबकि छात्र पूर्ण लोकतंत्र की मांग पर अड़े हुए हैं. चीन की सोशल नेटवर्किंग साइट वीबो पर ऑक्यूपाई सेंट्रल शब्द को ब्लॉक कर दिया गया है. हांगकांग में आंदोलन इसी नाम से चल रहा है. इस आंदोलन में छात्रों ने काली शर्ट और पीला रिबन बांधा हुआ है जो इनका विरोध प्रतीक है. साथ ही छाता जो कि लोगों की रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज है, वे इसके आधार पर आंदोलन को अंबरेला आंदोलन कह रहे हैं. छात्र रात में मोबाइल में लगी फ्लैश लाइट का उपयोग मशाल की तरह विरोध करने में भी कर रहे हैं.

हांगकांग फेडेरेशन ऑफ स्टूडेंट्स और स्कोलरिज्म ने सरकारी मुख्यालयके सामने 22 सितंबर को प्रदर्शन करना शुरू किया. 26 सितंबर की शाम को हजारों लोकतंत्र समर्थक सुरक्षा बैरियर को तोड़ते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट कांप्लेक्स में घुस गए थे जहां जुलाई से आम लोगों के प्रवेश करने पर पाबंदी लगी हुई है. इसके बाद सुरक्षा अधिकारियों ने कॉम्पेलक्स के प्रांगण में प्रदर्शनकारियों को घेर लिया और उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी. और अगले दिन उन्हें वहां से बल पूर्वक हटा दिया. छात्र नेता जोशुआ वांग को अस्थाई रूप से हिरासत में रखा गया. आंदोलनकारियों ने इसके बाद असहयोग आंदोलन की शुरुआत की घोषणा कर दी.

1997 के बाद से लेकर अबतक पहली बार इतने बड़े पैमाने पर हांगकांग में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतें, बढ़ती असमानता, लोकतंत्र की कमी और चीनी प्रशासन में शीर्ष स्तर पर हुए कई राजनीतिक विवादों के कारण हांगकांगवासियों में लगातार असंतोष बढ़ता गया. लोकतंत्र समर्थक चीफ एग्जीक्यूटिव लियुंग चुन यिंग के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं. युंग ने 2017 में होने वाले चुनावों का उल्लेख करते हुए कहा है कि मैं त्यागपत्र नहीं दूंगा क्योंकि मुझे चुनाव के लिए काम करना है. अधिकारियों ने लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है कि जितनी जल्दी हो सके, वे वहां से चले जाएं. गौरतलब हो कि, प्रदर्शनकारियों ने बड़े पैमाने पर धरना देकर दक्षिणी चीनी शहर के मध्य क्षेत्रों को बंद कर दिया है. प्रदर्शनकारी शहर की विधानसभा के बाहर भी धरने पर बैठे हुए हैं. आंदोलनकारी अपना प्रदर्शन जारी रखते हुए सरकार से बातचीत के लिए तैयार हो गए थे. लेकिन 3 अक्टूबर को हांगकांग फेडरेशन ऑफ़ स्टूडेंट्स ने सरकार से बातचीत बंद करने की. घोषणा की वजह से लोकतंत्र समर्थक और विरोधियों के बीच हिंसात्मक झड़प हुई. फेडरेशन ऑफ़ स्टूडेंट्स पुलिस पर आरोप लगा रहा है कि उसने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के ऊपर हुए हमले को रोकने की कोशिश नहीं की.

क्या हांगकांग त्यानमान स्क्वायर बनेगा?

अब सवाल यह उठता है किया क्या हांगकांग की छाता क्रांति (अम्ब्रेला रेवोलुशन) का अंजाम 1989 के त्यानमान स्क्वायर (जिसे 4 जून की घटना के नाम से भी जाना जाता है) के जैसा होगा? वर्ष 1989 में चीन की राजधानी बीजिंग में लोकतंत्र के समर्थन में चल रहे छात्र आंदोलन का अंत चीन की कम्युनिस्ट लीडरशिप द्वारा त्यानमान स्क्वायर दमनकारी कार्रवाई के बाद हुआ था. सरकारी कार्रवाई में सैकड़ों छात्र मारे गए थे. हालांकि चीन हांगकांग में हो रहे विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए दमनकारी रवैया नहीं अपना रहा है जैसा कि उसने बीजिंग के त्यानमान स्क्वायर पर किया था. लेकिन राजनीतिक समीक्षक इस आशंका को नकार भी नहीं रहे हैं. जहां चीन बार–बार इस आंदोलन को ग़ैरक़ानूनी करार देते हुए आंदोलनकारियों को चेतावनी दे रहा है, वहीं चीन के सरकारी अख़बार इस आंदोलन को अराजकता बताते हुए इसके विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं. चीनी अख़बार द पीपुल्स डेली कहता है कि इस तरह के हालात पार्टी (कम्युनिस्ट पार्टी) के खिलाफ चुनौती है, इसलिए सरकार को इसके खिलाफ कठोर और निर्णायक कदम उठाने चाहिए. गौरतलब हो कि चीन में दबी आवाज में ही सही लेकिन सालों से लोकतंत्र की मांग उठ रही है. यदि हांगकांग में चीन झुकता है तो चीम में लोकतंत्र समर्थक प्रोत्साहित होंगे. चीन में लोकतंत्र की स्थापना की मांग एक बार फिर उट सकती है. फिलहाल चीन के लिए हांगकांग दोधारी तलवार बन गया है.

चीन के विदेश मंत्री ने अपने अमेरिका दौरे के दौरान यह कहा था कि यह चीन का अंदरूनी मामला है. लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी ने बीजिंग से अपील की थी कि वह संयम से काम ले. उन्होंने इससे यह जाहिर कर दिया था कि हांगकांग त्यानमान स्क्वायर नहीं है. 1989 के बाद दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है. हांगकांग के त्यानमान स्क्वायर बनने की संभावना बहुत कम है लेकिन चीन के खुद को एक परिपक्व वैश्विक लीडर बनाने की राह में यह अग्निपरीक्षा से कम नहीं है. ■

कतर फुटबाल विश्व कप

आयोजन की तैयारी में बंधुआ मजदूरी

अरुण तिवारी

साल 2010 में जब फीफा ने कतर को 2022 में होने वाले फुटबॉल विश्वकप की दावेदारी सौंपी थी उस समय उसके मन में यह आशंका नहीं आई होगी कि चार साल के अंदर–अंदर ही उसे कतर से यह दावेदारी वापस लेने के बारे में विचार करना पड़ेगा. दरअसल जब फीफा ने कतर को यह दावेदारी थी तब भी उसे यह मालूम था कि इस देश में गर्मी के महीने में तापमान काफी ज्यादा होगा और ठंढे यूरोपीय देशों से आए खिलाड़ियों को खेलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा. लेकिन इन सब के बावजूद भी कतर को दावेदारी दे दी गई. इसे लेकर फीफा घूस लेने का आरोप भी झेल रहा है. अगर गंभीरता से पड़ताल की जाए तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि सिर्फ गर्मी ही इसकी एक वजह नहीं है. आइए जानने कि कोशिश करते हैं कि गर्मी के अलावा ऐसे कौन से कारण थे जिसने फीफा को सोचने पर मजबूर कर दिया.

ज्यादा दिन नहीं बीते जब अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कतर में फीफा विश्व कप 2022 के लिए काम में लगे मजदूरों की अवस्था पर एक रिपोर्ट जारी की थी. अपनी रिपोर्ट 'द डार्क साइड ऑफ माइग्रेशन' में संस्था ने बताया कि देश में मजदूरों की एक बड़ी संख्या बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रही है. इन मजदूरों के साथ जानवरों जैस बर्ताव किया जाता है. चाहे कितनी ही गर्मी क्यों न हो हफ्ते में सातों दिन उनसे 12–12 घंटे काम कराया जाता है. बहुत से मजदूर इस दौरान न चोट लगने के कारण अपंग हो गए बल्कि कईयों की लाशें ही घर लौटीं.

दरअसल कतर को दावेदारी देने को लेकर कई मामलों में विवाद झेल रहा है. पहला तो फीफा के अधिकारियों पर इस बात के आरोप लगे कि कतर को यह दावेदारी देने के एवज में संस्था के भीतर ही काफी घूस चली. इसके पीछे पूर्व फीफा उपाध्यक्ष मोहम्मद बिन हम्माम का हाथ माना जा रहा है. उन पर ऐसा करने को लेकर आरोप भी लगे. फीफा में हो रहे इस भ्रष्टाचार को लेकर महान फुटबॉल खिलाड़ी डियागो माराडोना ने भी संस्था की खिंचाई और आलोचना की थी. दरअसल फीफा को उसके ही एक निरीक्षक दल ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि गर्मी के मौसम में कतर में खिलाडियों को खेलने में काफी दिक्कते आएंगी क्योंकि गर्मी में यहां का तापमान यूरोपीय देशों की तुलना में काफी ज्यादा होता है. इसके बावजूद भी अमेरिका, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे काबिल प्रतिद्वंद्वियों को किनारे कतर को दावेदारी सौंप दी गई. इसे लेकर तुरंत ही फीफा की आलोचना साबित हो गई थी. एक साक्षात्कार के दौरान फीफा अध्यक्ष योसेव ब्लाटर ने कहा था कि कतर को दावेदारी देने को लेकर फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों का तगडा राजनीतिक दबाव था. उनके मुताबिक इन दोनों देशों की कई बड़ी कंपनियां कतर में काम कर रही थीं, इसी वजह से इन दोनों देशों ने यह राजनीतिक दबाव बनाया था. उनकी बातों के मुताबिक कतर को दावेदारी दिए जाने को लेकर मोहम्मद बिन हम्माम ने इतना दबाव बनवा दिया था, जिसे तोडा जाना लगभग नामुमकिन सा था. ब्लाटर ने यह माना है कि कतर को विश्व कप की दावेदारी दिया जाना पूरी तरह से गलत था. यह एक भूल थी, जो फीफा से हो गई है.

ब्लाटर की इन बातों पर भरोसा किया जा सकता है लेकिन इस सब के बावजूद भी ये महा आयोजन कभी चर्चा का विषय नहीं बनता अगर वहां पर इतने सारे श्रामिकों की मौत नहीं हो रही होती. दरअसल विश्वकप की मेजबानी हथियाने के बाद कतर न सिर्फ आततायी हो गया बल्कि उसने दूसरे देशों के मजदूरों के साथ घृणित व्यवहार करना शुरू कर दिया. भारत भी उन देशों में शामिल है जिसके नागरिक कतर के अमानवीय तरीकों से काल के गाल में समाते जा रहे हैं. कतर में काम करने वाले कुल मजदूरों में 38 प्रतिशत जनसंख्या भारतीय मजदूरों की है.

इसी साल फरवरी में यूरोपीय संसद में भी कतर और फीफा की आलोचना की गई थी. आइटक की एक रिपोर्ट के मुताबिक कतर अंतरात्मा विहीन देश है. दीन हीन प्रवासी मजदूर हों, उच्च वेतनभोगी हों फिर या वहां रह रहे विदेशी, इन सभी के लिए मौलिक मानवाधिकारों का कोई मतलब ही नहीं है. इस देश में कफाला कानून लागू है जो विदेशी मजदूरों को जानवरों से भी बदतर सुलूक जैसी है. इसके अनुसार विदेश आने वाले मजदूरों के सारे अधिकार नियोक्ता के पास होते हैं. उसे यह अधिकार प्राप्त है कि मजदूरों को कैसा काम देगा, क्या काम देगा और कितने समय तक काम लेगा. अगर किसी के पास पहचान पत्र नहीं है. तो उसे जेल तक भेजा जा सकता है. आइटक ने यह अनुमान लगाया था कि अगर इसी तरह मजदूरों की मौतों का सिलसिला जारी रहा तो साल 2022 तक चार हजार से भी ज्यादा अप्रवासी मजदूरों की मौत हो चुकी होगी.

कतर में कुल चौदह लाख विदेश श्रमिक काम कर रहे हैं. इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया और फिलीपींस के लगभग 62 प्रतिशत मजदूर हैं. वहीं भारत और नेपाल के कुल मजदूर लगभग 38 प्रतिशत हैं. अगर आकंडों पर नजर दौडाएं तो हम यह पाएंगे कि वहां पर 2011 के बाद प्रत्येक साल लगभग 250 के आस–पास भारतीय मजदूरों की मौत हो रही है. इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी तक कतर में अभी तक लगभग एक हजार भारतीय मजदूरों की मौत हो चुकी है. इन सबके बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले को उठाने का श्रेय ब्रिटेन के द गार्जियन अखबार को जाता है. जबकि इस दौरान वे सभी देश जिनके नागरिक कतर के जुल्म का शिकार हो रहे थे, सिर्फ खामोश थे. आखिर ऐसा क्यों है कि ये देश अपने नागरिकों को मरने के लिए छोड देते हैं. आखिर अपने नागरिकों की रक्षा करना देश की सरकार का ही तो कर्तव्य है. इन मजदूरों की मौत और भी ज्यादा दुखदायी इस वजह से है क्योंकि ये सभी नागरिक काफी गरीब हैं. इनकी मौत के बाद पूरा परिवार सडक पर आ जाने के लिए मजबूर हो जाता है.

ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो फीफा पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप और भी गंभीर हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक ऐसे देश के हाथों में विश्व कप जैसे बेहतरीन आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी जो मजदूर की मौत का जिम्मेदार बनता जा रहा है. फीफा को इस पर संशय किए बिना ही कतर से मेजबानी छीन ली जानी चाहिए चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

> काफी सोचने के बाद उन्होंने पत्र को अष्टप्रधानों के सामने रखा. अष्टप्रधानों ने पत्र को पढ़ा. इसके बाद आपस में विचार–विमर्श किया और बोले, निजाम पर दया करना ठीक नहीं है. चाहे वह भूखे–प्यासे हों, उनका त्योहार हो, लेकिन हैं तो वे हमारे दुश्मन ही और उसको कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए. न ही उस पर दया करनी चाहिए.

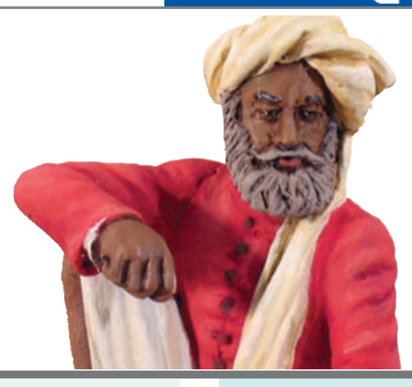

भवसागर से पार उतारेंगे साई

चौथी दुनिया ब्यूरो

साई बाबा समस्त यौगिक क्रियाओं में पारंगत थे.6 प्रकार की क्रियाओं के तो वे पूर्ण ज्ञाता थे.6 क्रियायें, जिनमें धोती (एक 3 फुट चौड़े व 22 फुट लम्बे कपड़े के भीगे हुए टुकड़े से पेट को स्वच्छ करना), खण्ड योग (अर्थात अपने शरीर के अवयवों को पृथक–पृथक कर उन्हें पुनः पूर्ववत जोड़ना) और समाधि आदि भी सम्मिलित हैं. यदि कहा जाए कि वे हिन्दू थे तो आकृति से वे मुसलमान प्रतीत होते थे. कोई भी यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता था कि वे हिन्दू थे या मुसलमान. वे हिन्दुओं का रामनवमी उत्सव यथाविधि मनाते थे और साथ ही मुसलमानों का चन्दनोत्सव भी. वे उत्सव में दंगलों को प्रोत्साहन तथा विजेताओं को पर्याप्त पुरस्कार देते थे. गोकुल अष्टमी को वे गोपाल–काला उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे. ईद के दिन वे मुसलमानों को मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित करते थे. एक समय मोहर्रम के अवसर पर मुसलमानों ने मस्जिद में ताजिए बनाने तथा कुछ दिन वहां रखकर फिर जुलूस बनाकर गांव से निकालने का कार्यक्रम किया. साईबाबा ने केवल चार दिन ताजियों को वहां रखने दिया. यदि कोई उन्हें हिन्दू घोषित करें तो वे सदा मस्जिद में निवास करते थे और यदि मुसलमान कहे तो वे सदा वहां धूनी प्रज्वलित रखते थे तथा अन्य कर्म, जो कि इस्लाम धर्म के विरुद्ध है, जैसे चक्की पीसना, शंख तथा घंटानाद, होम आदि कार्य करना, अन्नदान और अर्घ्य द्वारा पूजन आदि सदैव वहां चलते रहते थे.

यदि कोई कहे कि वे मुसलमान थे, तो कुलीन ब्राम्हण और अग्निहोत्री भी अपने नियमों का उल्लंघन कर सदा उनको साष्टांग नमस्कार किया करते थे. जो उनके स्वदेश का पता लगाने गए, उन्हें अपना प्रश्नत ही विस्मृत हो गया और वे उनके दर्शनमात्र से मोहित हो गया. इसका निर्णय कोई न कर सका कि यथार्थ में साई बाबा हिन्दू थे या मुसलमान. इसमें आश्चिर्य ही क्या है जो अहं व इन्द्रियजन्य सुखों को तिलांजलि देकर ईश्वर की शरण में आ जाता है तथा जब उसे ईश्वर के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है, तब उसकी कोई जाति–पाति नहीं रह जाती. इसी कोटि के साई बाबा थे, जो जातियों और प्राणियों में किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रखते थे. कुत्ते भी उनके भोजन–पात्र में मुंह डालकर स्वतंत्रतापूर्वक खाते थे, लेकिन उन्होंने कभी कोई भी आपत्ति नहीं की. ऐसा अपूर्व और अद्भुत साई बाबा का अवतार था. बाबा अखण्ड सच्चिदानन्द थे. उनकी महानता और अद्वितीय का बखान कौन कर सकता है. जिसने उनके चरण–कमलों की शरण ली, उसे साक्षात्कार की प्राप्ति हुई. अनेक सन्यासी, साधक और अन्य जन भी साईबाबा के पास आया करते थे. बाबा भी सदैव उनके साथ चलते–फिरते, उठते–बैठते, उनसे वार्तालाप कर उनका चित्तरंजन किया करते थे. अल्लाह मालिक सदैव उनके होठों पर था. वे कभी भी विवाद और मतभेद में नहीं पड़ते थे तथा सदा शान्त और स्थिर रहते थे, लेकिन कभी–कभी वे क्रोधित हो जाया करते थे. वे सदैव ही वेदान्त की शिक्षा देते थे. अमीर और गरीब दोनों उनके लिए एक समान थे. साई स्वयं ज्ञानावतार होकर भी वे सदैव अज्ञानता का प्रदर्शन करते थे. उन्हें आदरसत्कार से सदैव अरुचि थी. इस प्रकार साई बाबा का वैशिष्टय था. वे शरीरधारी, लेकिन कर्मों से उनकी ईश्वरीयता स्पष्ट झलकती थी. शिरडी के सकल नर–नारी उन्हें परमब्रह्मा ही मानते थे.

साई ने शिरडी में प्रायः समस्त मंदिरों का उन्होंने जीर्णोधार किया. तात्या पाटील के द्वारा शनि, गणपति, शंकर पार्वती, ग्राम्यदेवता और हनुमानजी आदि के मंदिर ठीक करवाए. उनका दान भी विलक्षण था. दक्षिणा के रुप में जो धन एकत्रित होता था, उसमें से वे किसी को बीस रुपये, किसी को पंद्रह रुपये या किसी को पचास रुपये, इसी प्रकार प्रतिदिन स्वेच्छापूर्वक वितरण कर देते थे. प्राप्तिकर्ता उसे शुद्ध दान समझता था. बाबा की भी सदैव यही इच्छा थी कि उसका उपयुक्त रीति से व्यय किया जाय.

बाबा के दर्शन से भक्तों को अनेक प्रकार का लाभ पहुंचता था. अनेकों निष्कपट और एकदम स्वस्थ बन गए, दुष्टात्मा लोग भी पुण्यात्मा में बदल गए. अनेकों कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और अनेकों को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो गई. बिना कोई रस या औषधि सेवन किए, बहुत से अंधों को पुनः दृष्टि प्राप्त हुई, पंगुओं की पंगुता नष्ट हो गई. कोई भी उनकी महानता का अन्त न पा सका. उनकी कीर्ति दूर–दूर तक फैलती गई और भिन्न–भिन्न स्थानों से यात्रियों के झुंड के झुंड शिरडी आने लगे. बाबा सदा धूनी के पास ही आसन जमाए रहते और वहीं विश्राम किया करते थे. वे कभी स्नान करते और कभी स्नान किए बिना ही समाधि में लीन रहते थे. वे सिर पर एक छोटी सी साफी, कमर में एक धोती और तन ढंकने के लिए एक अंगरखा धारण करते थे. प्रारम्भ से ही उनकी वेशभूषा इसी प्रकार थी. अपने जीवनकाल के पूर्व में वे गांव में चिकित्साकार्य भी किया करते थे. रोगियों का निदान कर उन्हें औषधि भी देते थे और उनके हाथ में अपरिमित यश था. इस कारण से वे अल्प काल में ही योग्य चिकित्सक विख्यात हो गए. यहां एक घटना का उल्लेख किया जाता है कि एक भक्त की आंखें बहुत लाल हो गई थी. उन पर सूजन भी आ गई थी. शिरडी सरीखे छोटे ग्राम में डॉक्टर कहां मिलता तब बाबा के भक्त रोगी को बाबा के पास लेकर आए. इस प्रकार की पीड़ा में डॉक्टर प्रायः लेप, मरहम, अंजन, गाय का दूध तथा कपूरयुक्त औषधियों को प्रयोग में लाते हैं, लेकिन बाबा की औषधि तो सर्वथा ही भिन्न थी. उन्होंने भिलावां पीस कर उसकी दो गोलियां बनाई और रोगी के नेत्रों में एक–एक गोली चिपका कर पट्टी से आंखें बांध दी. दूसरे दिन पट्टी हटाकर नेत्रों के ऊपर जल के छींटे छोड़े. सूजन कम हो गई और आंखे ठीक हो गईं. नेत्र शरीर का एक अति सुकोमल अंग है, लेकिन बाबा की औषधि से कोई हानि नहीं पहुंची, लेकिन आंखों की व्याधि दूर हो गई.

बाबा बाल्यकाल से ही यौगिक क्रियाएं किया करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी, उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था. चिकित्सा के नाम से उन्होंने कभी किसी से एक पैसा भी लेना स्वीकार नहीं करते थे. अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर–दूर तक फैल गई. उन्होंने अनेक निर्धनों और रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया. मसीहो के मसीहा साई ने कभी अपने स्वास्थ्य की चिंता न कर अनेक विघनों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाई. वे सदा कल्याणार्थ चिंतित रहते थे. साई हमेशा दयालु भाव से रहते थे सब पर एक समान कृपा दृष्टि बनाए रखते थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य–धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

बदला ले रही सरकार

पिछले 50 वर्षों में न तो कभी इतनी गर्मी पड़ी और न ही कभी लोगों को इतनी अधिक बिजली कटौती का सामना करना पड़ा. चुनाव के पहले तो 16–16 घंटे बिजली मिलती थी. अब 16 घंटे की कटौतीी हो रही है. ऐसा लगता है जैसे राज्य सरकार नागरिकों से लोकसभा चुनाव में हार का बदला ले रही है. अगर प्रदेश में बिजली की कमी थी, तो अन्य राज्यों से बिजली खरीद कर पूर्ति की जानी चाहिए थी. बिजली कटौती ने नागरिकों के दिन का चैन और रातों की नीद छीन ली है.

–राज किशोर पाण्डेय(प्रहरी), लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

सपा की जीत

कवर स्टोरी–उत्तर प्रदेश का उप चुनाव सपा अर्श पर भाजपा फर्श पर(29 सितंबर–05 अक्टूबर 2014)पढ़ा काफी तथ्यपरक है. प्रभातरंजन दीन का आलेख पढ़ा बिल्कुल सही है कि सपा अपने साम्प्रदायिक छवि से बाहर निकल गई और भाजपा उसी में फंसी रही. सपा ने लोकसभा चुनाव से संज्ञान लेते हुए अपने नेता आजम खान को उपचुनाव से दुर रखा कि उनके बयानों से साम्प्रदायिक ध्रुवी करण न हो. लेकिन भाजपा ने लव–जिहाद का मुद्दा झेड़कर उप चुनाव में ध्रुवीकरण की खूब कोशिश की, जिसका नतीजा रहा कि उसे 11 सीटों में से 8 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा. युवाओं को रोजगार चाहिए और जनता विकास, इसलिए अब वो ऐसे मुद्दो से नहीं बहकने वाली है. भाजपा के हारने का एक कारण पार्टी की अंर्तकलह भी है. इसका नतीजा है कि सपा के खिलाफ जना आक्रोश होने के बावजूद सपा ने 8 सीटों पर जीत हासिल की.

–मनोज यादव, रायबरेली, उत्तर प्रदेश.

सरकार पूरा करे वादे

आलेख–भाजपा के लिए सबक है चुनाव परिणाम (29 सितंबर–05 अक्टूबर 2014) पढ़ा काफी तथ्यपरक विचार है. कमल मोरारका का आलेख पढ़कर काफी अच्छा लगता है और उत्सुकता होती है कि उनके आने वाले लेख में और कुछ नया पढ़ने को मिलेगा. यह बिल्कुल सही है कि विधानसभा उपचुनाव परिणाम एक झटका देने और आश्चर्य वाला परिणाम था. इस परिणाम से खुद भाजपा को एक झटका लगा होगा और उसे आश्चर्य भी हुआ होगा. लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने वाली पार्टी उसके दो महीने बाद हुए उप चुनावों में हार गई. भाजपा और प्रधानमंत्री ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान बड़े–बड़े वादे किए थे, लेकिन उनमें से कोई वादा पूरा होता नजर नहीं आ रहा है. जनता ने उप चुनाव में भाजपा को जवाब दिया है, इसलिए उसे जनता से किए गए वादे को पूरा करना चाहिए.

–रामानुज पांडेय, झांसी, उत्तर प्रदेश.

भाजपा की अन्तर्कलह

आलेख–गुजरात–राजस्थान उप चुनाव परिणाम, भाजपा के लिए आत्मचिंतन का समय(29 सितंबर–05 अक्टूबर 2014) पढ़ा शशिशेखर इस अपने आलेख में गुजरात और राजस्थान के उपचुनाव परिणाम पर काफी विस्तार से लिखा है, जो तथ्यों पर आधारित है. भाजपा ने लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल की, जिससे भाजपा नेताओं का मनोबल इतना बढ़ गया कि अब उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता. जहां–जहां विधानसभा उपचुनाव हुए हैं लगभग उसे अधिकतर जगहों पर हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन बंगाल और असम में उसे जीत हासिल हुई है जो उसके लिए थोड़ी राहत है. उपचुनाव में हार या जीत का ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन जीतने वाली पार्टी का मनोबल बढ़ता है और हारने वाली पार्टी को अगले चुनाव के लिए अपने कमियों को दूर करने का मौला मिलता है. इस उप चुनाव से लोकसभा में शर्मनाक हार का सामना करने वाली कांग्रेस को जरूर राहत मिली है, जो उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह भरेगा. भजपा को अपनी गलतियों को सुधारना होगा और इस हार से उसे सबक लेने की भी जरूरत है.

–राकेश कुशवाहा, पटना, बिहार.

समय की मांग जनता परिवार

जब तोप मुकाबिल हो–जनता परिवार का एक होना जरूरी है (29 सितंबर–05 अक्टूबर 2014) पढ़ा काफी विचारोत्तेजक है. संतोष भारतीय ने सही कहा है कि जनता परिवार का एक होना जरूरी है, क्योंकि मोदी सरकार को चुनौती देने और एक सशक्त विपक्ष के लिए जनता परिवार को एक होना चाहिए. कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हार से इतना हताश है कि वह कोमा में चली गई है और लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही उसके बड़े नेता नजर नहीं आ रहे हैं. नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव से बिहार उप चुनाव में हाथ मिलाया जिसका परिणाम उनके गठबंधन के पक्ष में रहा, इसलिए पूरे जनता परिवार को एक साथ आना चाहिए, जो भाजपा को चुनौती दे सकता है. कांग्रेस एक सशक्त विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकती. एक सशक्त विपक्ष के लिए और राज्यों में भाजपा को कड़ी चुनौती देने लिए जनता परिवार में रही पार्टियों को साथ आना चाहिए.

–हरबंश सिंह, दरभंगा, बिहार.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :

चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर–11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन–201301

कहानी

भूखों की सेवा

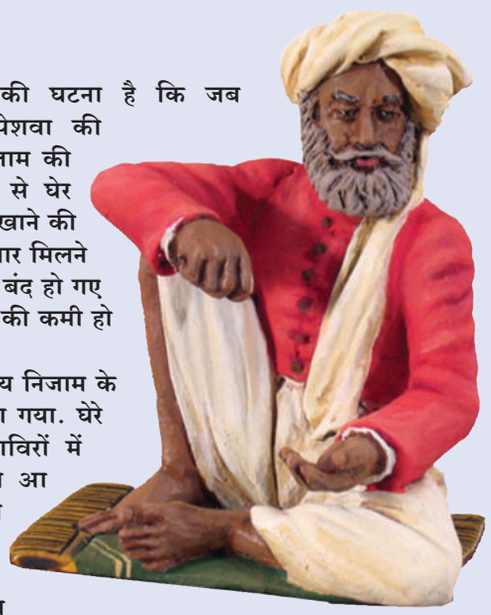

एक समय की घटना है कि जब बाजीराव पेशवा की सेना ने निजाम की फौज को चारों ओर से घेर लिया था. इससे उनकेखाने की सभी वस्तुएं और हथियार मिलने केजो रास्ते थे, वे सब बंद हो गए थे और सेना में भोजन की कमी हो गई थी.

संयोगवश उसी समय निजाम के सैनिकों का त्योहार आ गया. घेरे में पड़े निजाम के शिविरों में भूखों मरने की नौबत आ गई. कहीं से रसद–पानी न मिलते देख निजाम ने पेशवा को पत्र लिखा–क्या हमारे सिपाहियों को त्योहार के दिनों में भी भूखों मरना पड़ेगा?

यहां तो सभी धर्मों को बराबर महत्व दिया जाता है. हमने तो सुना था कि पेशवा बहादुर होने केसाथ–साथ रहमदिल भी हैं. वे भूखे लोगों को खाना खिलाते हैं और अपने भूखे दुश्मनों पर वार नहीं करते. पेशवा ने इस पत्र को कई बार पढ़ा.

काफी सोचने के बाद उन्होंने पत्र को अष्टप्रधानों के सामने रखा. अष्टप्रधानों ने पत्र को पढ़ा. इसके बाद आपस में विचार–विमर्श किया और बोले, निजाम पर दया करना ठीक नहीं है. चाहे वह भूखे–प्यासे हों, उनका त्योहार हो, लेकिन हैं तो वे हमारे दुश्मन ही और उसको कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए. न ही उस पर दया करनी चाहिए.

अष्टप्रधानों की बात सुनकर पेशवा बोले, मराठे वीर हैं, पर इसकेसाथ ही मनुष्य भी हैं. वीरता कहती है कि शत्रु को पराजित करना चाहिए, लेकिन मानवता का तकाजा ये है कि भूखे शत्रु को भोजन दिया जाए. यदि भोजन व पानी न मिलने से वह पहले ही कमजोर हो जाए तो उसे पराजित करना कोई बड़ी बात नहीं है. पेशवा की आज्ञा से निजाम के पास रसद और पानी की गाड़ियां भेज दी गईं. ■

शिक्षा–भुखे व्यक्ति को हमेशा भोजन देना चाहिए.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

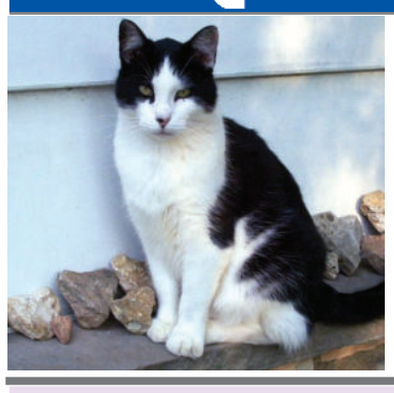

> रामू की बहू पर खून सवार हो गया. न रहे बांस, न बजे बांसुरी. रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली. रात भर उसे नींद न आई. किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि ज़िंदा न बचे, यही सोचती रही. सुबह वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है. रामू की बहू कुछ सोचकर मुस्कुराती हुई उठी. कबरी उसके उठते ही खिसक गई. रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे पर रखकर चली गई. हाथ में पाटा लेकर वह लौटी, तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है.

नायिकाओं से जगमग फिल्में

अनंत विजय

हिंदी साहित्य में जब नब्बे के दशक में स्त्री विमर्श की आंधी चल रही थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हिंदी फिल्मों में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसका असर देखने को मिलेगा. साहित्य में स्त्री विमर्श अभी तक अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाया है और लगातार अपने होने के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं हिंदी फिल्मों में स्त्री यानी नायिका पूरे तौर पर स्थापित हो चुकी है. कई बार रामधारी सिंह दिनकर की संस्कृति के चार अध्याय में लिखी हुई यह उक्ति याद आती है, जहां वह कहते हैं, विद्रोह, क्रांति या बगावत कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसका विस्फोट अचानक होता है. घाव भी फूटने के पहले लंबे समय तक पकता रहता है. दिनकर की इस उक्ति में हम यह जोड़ सकते हैं कि साहित्य एवं कला में भी किसी प्रवृत्ति के स्थापित होने में वक्त लगता है और उसकी स्वीकार्यता में और भी समय लगता है. साहित्य में यह समय फिल्मों से ज़्यादा लग रहा है. इन दिनों साहित्य में तो स्त्रियां केंद्र में हैं, बहुधा अपनी रचना की वजह से और कभी-कभार अपने बयानों की वजह से. साहित्य के स्त्री पात्र लगातार बोल्ड होते चले जा रहे हैं. घूंघट में रहने वाली स्त्रियां अब अपने बिंदासपन की वजह से पुरानी छवि को छिन्न-भिन्न कर आगे बढ़ चुकी है. इस वक्त हिंदी साहित्य में जो युवा पीढ़ी सक्रिय है, उसमें लेखिकाओं का पलड़ा भारी है और आलोचकों की आत्मा भी उनकी ओर झुकी हुई नज़र आती है. लेकिन, वहां अब भी लेखिकाओं को लेकर एक झिझक दिखाई देती है. यह एक अवांतर प्रसंग है, जिस पर फिर कभी विस्तार से चर्चा होगी.

हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों में नायिकाओं के बदलते किरदारों और उनके बढ़ते हुए दबदबे की. हिंदी फिल्मों के इतिहास पर नज़र डालें, तो फिल्में पुरुष प्रधान ही बना करती थीं और नायकों के होने या न होने से फिल्मों के चलने या फ्लॉप होने का अनुमान लगाया जाता था. चूंकि किसी भी कथानक में स्त्रियों की उपस्थिति अनिवार्य होती थी, लिहाजा फिल्मों में नायिकाओं को रखा जाता था. जैसे परिवार में पत्नी, बहू और बहन उसका अनिवार्य अंग होते हैं, उसी तरह से फिल्मों में नायिकाओं को रखा जाता था. नायिकाएं भी वैसी कि अपने पहनावे में बिल्कुल घरेलू, नख से शिख तक ढंकी हुईं. दिल के अरमानों को दिल में ही दफन करने को हरदम तैयार. जैसे-जैसे समय बदला, नायिकाओं के रंग-रूप में तो परिवर्तन हुआ, लेकिन फिल्मों में वे रहीं शोभा के तौर पर ही. फिल्मों के क्रमिक विकास के साथ-साथ नायिकाओं के कपड़े थोड़े कम होने लगे. फिल्म संगम में वैजयंती माला ने कपड़ों ने उस वक्त काफी धूम मचाई थी. तब यह तक लिखा गया था कि भारतीय फिल्मों की नायिकाएं बोल्ड होना शुरू हो गई हैं. पहनावे में बोल्डनेस के बावजूद हिंदी फिल्मों की नायिकाएं अपने नायकों के मुकाबले दोयम दर्जे पर ही रहीं.

बॉलीवुड में अगर हीरो को किसी एक फिल्म के लिए एक करोड़ रुपये मिलते थे, तो नायिकाओं को पच्चीस लाख रुपये पर ही संतोष करना पड़ता था. माना यह जाता था कि फिल्में तो हीरो के बल पर चलती हैं. साठ के दशक में एकाध प्रयोग हुए, जिनमें नायिकाओं के बूते पर फिल्म चलने की बात सामने आई. मीना कुमारी की फिल्म-मैं चुप रहूंगी की सफलता से इस बात की वकालत करने वालों को बल मिला. उस दौर में मीना कुमारी का जादू दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता था. किसी भी फिल्म में मीना कुमारी की मौजूदगी उसके हिट होने की गारंटी मानी जाती थी. आलम यह था कि एक ही साल मीना कुमारी की तीन फिल्में फिल्म फेयर अवॉर्ड के लिए नामांकित हुई थीं. यह फिल्म फेयर अवॉर्ड में एक रिकॉर्ड था कि एक ही साल में एक ही अभिनेत्री अलग-अलग

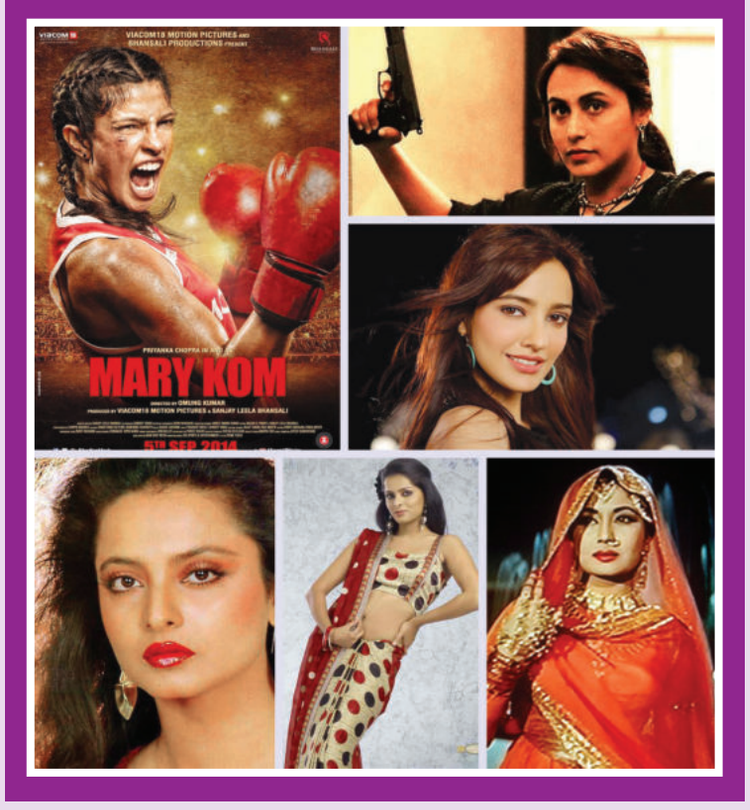

तीन फिल्मों से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नामांकित हुई थी. मीना कुमारी के बाद फिल्मी दुनिया में हेमा मालिनी के वक्त एक बार फिर से ऐसा मौक़ा आया, जब लगा कि नायिका भी अपने बूते पर फिल्म को सफल बना सकती है. सीता और गीता पूरे तौर पर हेमा मालिनी की फिल्म थी. आगे चलकर रेखा ने भी कुछ फिल्में अपने बूते पर सफल कराईं.

अब यहां एक बात ग़ौर करने लायक है. इस दौर में फिल्मों की नायिकाओं का जो संघर्ष था, वह अपने आपको बचाने, अपने वजूद को बचाने, अपने को साबित करने या फिर अपने परिवार को बचाने का संघर्ष था. फिल्मों की नायिकाएं वैसी सामाजिक संरचना का हिस्सा थीं, जहां एक महिला का जीवन संघर्ष केंद्र में था. इसी चरित्र के इर्द-गिर्द पूरी फिल्म घूमती थी. अब अगर हम ग़ौर से देखें, तो उस वक्त इस तरह की फिल्में इस वजह से हिट हो रही थीं कि समाज की महिलाओं का भी वही संघर्ष था. फिल्में देखकर महिलाएं कथानक के साथ अपने आपको भी आईडेंटिफाई कर रही थीं. इस बात पर भी शोध किया जाना चाहिए कि 1962 में मीना कुमारी की फिल्म-मैं चुप रहूंगी के सफल होने के बावजूद फिल्म निर्माताओं ने नायिका प्रधान फिल्मों पर दांव क्यों नहीं लगाया. मैं चुप रहूंगी के रिलीज होने के लगभग चालीस साल बाद अब हिंदी फिल्मों में एक ऐसा दौर आया है, जब लगातार एक के बाद एक नायिका प्रधान फिल्में आ रही हैं और हिट भी हो रही हैं. अभी-अभी रानी मुखर्जी अभिनीत फिल्म मर्दानी और प्रियंका चोपड़ा अभिनीत फिल्म मैरी कॉम आईं, जो काफी सफल रहीं. फिल्मों के जानकारों के मुताबिक, मैरी कॉम पर फिल्म निर्माता को क़रीब सौ फ़ीसद का मुनाफ़ा हुआ है.

ट्रेड पंडितों के मुताबिक, फिल्म मैरी कॉम के निर्माण पर कुल 18 करोड़ रुपये की लागत आई थी और अब तक उसकी कुल कमाई 35 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. इसी तरह रानी मुखर्जी अभिनीत फिल्म मर्दानी भी पचास फ़ीसद से ज़्यादा मुनाफा कमाने में कामयाब रही. मर्दानी की लागत 19 करोड़ रुपये के आसपास थी और रिलीज होने से लेकर अब तक फिल्म ने क़रीब 30 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है. इन दो फिल्मों के अलावा भी कई फिल्में आईं, जिनमें नायिकाओं ने अपने बूते पर फिल्म की लागत वसूल ली, बल्कि ठीकठाक मुनाफ़ा भी कमाया. इस साल रिलीज हुई हाईवे, रागिनी एमएमएस, बॉबी जासूस और गुलाब गैंग में से सिर्फ़ गुलाब गैंग ही अपनी लागत नहीं निकाल पाई. अब इन महिला प्रधान फिल्मों की सफलता के पीछे दो-तीन वजहें हैं. एक तो मल्टीप्लैक्सों की संख्या बढ़ने और लाइफ स्टाइल में बदलाव की वजह से महिला दर्शकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है. दूसरा, अब फिल्मों की नायिकाओं का चरित्र भी बदला है. पहले जहां फिल्मों की नायिकाएं अपने या परिवार के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करती थीं, वहीं अब जो फिल्में आ रही हैं, उनमें महिला समाज के लिए लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं. भारतीय फिल्मों में यह एक बड़ा बदलाव है, जिसे रेखांकित किया जाना आवश्यक है. जैसे मर्दानी और गुलाब गैंग में तो समाज के लिए संघर्ष ही फिल्म की केंद्रीय थीम है. उसी तरह मैरी कॉम में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और उसका संघर्ष ही नायिका के तौर पर प्रतिबिंबित होता है.

अब यह जो समाज के लिए कुछ करने का संघर्ष है, वह आज के मल्टीप्लैक्स में जाने वाली महिलाओं के मूड से मेल खाता है. इस तरह के चरित्र से आज मल्टीप्लैक्स की महिला दर्शक अपने आपको आईडेंटिफाई करती हैं. महिला दर्शकों की बढ़ती संख्या और फिर फिल्म के किरदार से एक तरह का उनका जुड़ाव नायिका प्रधान फिल्मों की सफलता के लिए आधार प्रधान कर रही है. लिहाजा फिल्में लोकप्रिय हो रही हैं. नायिकाओं को हीरो बनाती इस तरह की फिल्मों में निर्माताओं की भी रुचि काफी बढ़ी है. निर्माताओं की बढ़ती रुचि के पीछे आर्थिक कारण है. नायिकाओं को केंद्र में रखकर बनने वाली फिल्मों की लागत बहुत कम होती है. हीरो की तुलना में हिरोइन का मेहनताना कम होता है. अगर हम हाल में रिलीज हुई फिल्मों पर नज़र डालें, तो जय हो और सिंघम रिटर्न्स की लागत सौ करोड़ या उससे ज़्यादा रही है, जबकि नायिका प्रधान फिल्मों की औसत लागत 25 से 27 करोड़ रुपये रही है. अब अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें, तो नायिका प्रधान फिल्में कम बजट में तैयार हो जाती हैं और उनका औसत मुनाफ़ा भी ठीकठाक रहता है. ज़्यादा निवेश पर जोखिम ज़्यादा होता है और जो निर्माता ज़्यादा निवेश का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, वे कम लागत पर बनने वाली नायिका प्रधान फिल्में बना रहे हैं. वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि हिंदी सिनेमा में बदलाव का एक ऐसा दौर आया है, जहां अब हिरोइनों के बल पर लगातार एक के बाद एक फिल्म सफल हो रही है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कहानी

प्रायश्चित

***भगवती चरण वर्मा** उन साहित्यकारों में शुमार किए जाते हैं, जिन्होंने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के ख़िलाफ़ अपनी कलम चलाई और सच्चाई पर रोशनी डाली. प्रस्तुत कहानी में एक किशोरवय बहू घर में उत्पात मचाने वाली बिल्ली से आजिज आकर उस पर हमला कर बैठती है. चोट खाने के बाद भी बिल्ली कुछ देर के लिए वहीं सांस थामे पड़ी रहती है और घर में बिल्ली की हत्या को लेकर कोहराम मच जाता है.*

अगर कबरी बिल्ली घर-भर में किसी से प्रेम करती थी, तो रामू की बहू से और अगर रामू की बहू घर-भर में किसी से घृणा करती थी, तो कबरी बिल्ली से. रामू की बहू दो महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी. पति की प्यारी और सास की दुलारी, चौदह वर्ष की बालिका. भंडार-घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी, नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ. सास जी ने माला ली और पूजा-पाठ में मन लगाया. लेकिन, बहू ठहरी चौदह वर्ष की बालिका! कभी भंडार-घर खुला है, तो कभी भंडार-घर में बैठे-बैठे सो गई. कबरी बिल्ली को मौक़ा मिला, घी-दूध पर जुट गई. रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के-पंजे. रामू की बहू हांडी में घी रखते-रखते ऊंघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में. रामू की बहू दूध ढंककर मिसरानी को जिंस देने गई और दूध नदारद. अगर बात यहीं तक रह जाती, तो भी गलत न था. कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई कि उसके लिए खाना-पीना दुश्वार. रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची और रामू जब आए, तब तक कटोरी साफ़ चटी हुई.

रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वह घर में रहेगी या फिर कबरी. मोर्चाबंदी हो गई, दोनों सतर्क. बिल्ली फंसाने का कठघरा आया, उसमें दूध, मलाई, चूहे और दूसरे स्वादिष्ट व्यंजन रखे गए, लेकिन कबरी ने उधर निगाह तक न डाली. कबरी अभी तक तो रामू की बहू से डरती थी, पर अब साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उसे हाथ न लगा सके. कबरी का हौसला बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया. उसे मिलती थीं सास की मीठी झिड़कियां और पतिदेव को मिलता था रूखा-सूखा भोजन.

एक दिन रामू की बहू ने खीर बनाई. पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह-तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताख पर रखा गया, जहां बिल्ली न पहुंच सके. इसके बाद रामू की बहू पान लगाने में जुट गई. उधर बिल्ली कमरे में आई, ताख के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है. ताक की ऊंचाई अंदाजी. उधर रामू की बहू पान लगा रही है. पान लगाकर वह सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी, पंजा कटोरे में लगा और कटोरा झन्न की आवाज़ के साथ फर्श पर. आवाज़ सुनते ही रामू की बहू सास के सामने पान फेंककर दौड़ी, देखा कि फूल का कटोरा टुकड़े-टुकड़े, खीर फर्श पर और बिल्ली डटकर खीर उड़ा रही. रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत.

रामू की बहू पर खून सवार हो गया. न रहे बांस, न बजे बांसुरी. रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली. रात भर उसे नींद न आई. किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि ज़िंदा न बचे, यही सोचती रही. सुबह वह देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है. रामू की बहू कुछ सोचकर मुस्कुराती हुई उठी. कबरी उसके उठते ही खिसक गई. रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे पर रखकर चली गई. हाथ में पाटा लेकर वह लौटी, तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है. मौक़ा हाथ में आ गया, सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर दे मारा. कबरी न हिली, न डुली, न चीखी, न चिल्लाई. बस एकदम उलट गई. आवाज़ हुई, तो महरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर मौजूद. रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है.

> **एक दिन रामू की बहू ने खीर बनाई. पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह-तरह के मेवे दूध में औटाए गए, सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के एक ऐसे ऊंचे ताख पर रखा गया, जहां बिल्ली न पहुंच सके. इसके बाद रामू की बहू पान लगाने में जुट गई. उधर बिल्ली कमरे में आई, ताख के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर कटोरे की ओर देखा, सूंघा, माल अच्छा है.**

महरी बोली, अरे राम! बिल्ली तो मर गई. मां जी, बिल्ली की हत्या बहू से हो गई, यह तो बुरा हुआ. मिसरानी बोली, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है. हम तो रसोई न बनाएंगी, जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी. सास जी बोलीं, हां ठीक कहती हो. अब जब तक बहू के सिर से हत्या न उतर जाए, तब तक न कोई पानी पी सकता है, न खाना खा सकता है. बहू, यह क्या कर डाला? महरी ने कहा, कहो तो पंडित जी को बुलाय लाई. सास की जान में जान आई, हां, जल्दी पंडित जी को बुला लो. बिल्ली की हत्या की ख़बर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई. औरतों का रामू के घर तांता बंध गया. चारों तरफ़ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी.

पंडित परमसुख चौबे पूजा कर रहे थे. ख़बर पाते ही उठ पड़े. पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन न बनाना. लाला घासीराम की पतोह ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा. परमसुख छोटे और मोटे से आदमी थे. लंबाई चार फीट दस इंच और तोंद का घेरा अट्ठावन इंच. चेहरा गोल-मटोल, मूंछ बड़ी-बड़ी, रंग गोरा, चोटी कमर तक पहुंचती हुई. कहते हैं कि मथुरा में जब पंसेरी खुराक वाले पंडितों को ढूंढा जाता था, तो पंडित परमसुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता था. ■ ***क्रमशः***

feedback@chauthiduniya.com

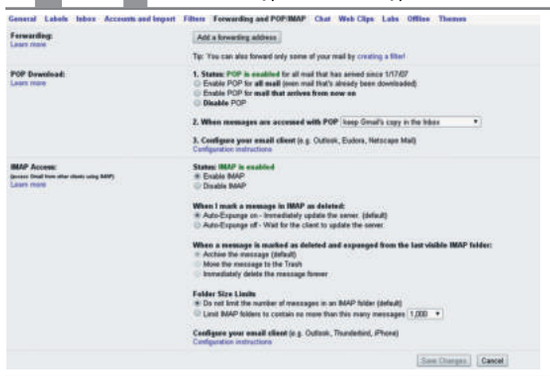

अगर आप चाहते हैं की आपके किसी मेल एड्रेस पर जो मेल आते हैं वो किसी और के पास या आपके किसी और ईमेल अकाउंट में खुद–ब–खुद चला जाए, तो ऐसा करने के लिए बस आप एक सेटिंग में बदलाव कीजिए और दूसरे एकाउंट में ईमेल पढ़िए इसके लिए(जीमेल में) सेटिंग्स में जाकर फॉरवार्डिंग एंड पॉप/आईमैप ऑप्शन में जाकर ऐड ए फॉरवार्डिंग एड्रेस बटन पर क्लिक करें.

ई-मेल एक, काम अनेक

श्याम सुन्दर प्रसाद

आज ईमेल एड्रेस तकरीबन हर व्यक्ति की प्रारंभिक जरुरतों में से एक हो गया है. ई मेल टेक्स्ट, ग्राफ़िक्स, ऑडियो, वीडियो, व अन्य प्रकार के डेटा को भेजने या पाने का मुख्य व आसान जरिया है. याहू, जीमेल, हॉटमेल और रेडिफ़ मेल या अन्य किसी डोमेन के मेल का हम सभी इस्तेमाल करते हैं. एक ईमेल आईडी डाटा के आदान प्रदान के अलावा बहुत से काम करता है जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है. आम तौर पर मेल भेजना, मेल रिसीव करना,किसी मेल को ड्राफ्ट में सुरक्षित रखना, डिलीट किये गए मेल को वापस इनबॉक्स में लाना जैसी सुविधाओं से आप भलीभांति परिचित होंगे. लेकिन ईमेल के अंदर बहुत से ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जिनका प्रयोग आमतौर पर यूजर्स नहीं करते हैं, वह इसलिए क्योंकि वो या तो इन सेवाओं से अनजान हैं या उन्हें इन फीचर्स का उपयोग करना नहीं आता है. उदाहरण के लिए अलग–अलग लोगों से मिलने वाले मेल यदि अलग अलग फोल्डर्स में खुद–ब–खुद चली जाएं, ठीक वैसे ही जैसे आपके मेल में स्पैम मेल खुद ही स्पैम फोल्डर में चली जाती है. आप कुछ खास टिप्स का उपयोग कर अपने एक ई मेल से अनेक काम कर सकते हैं. आइए आपके ईमेल के अंदर छुपी हुई सुविधाओं के बारे में जानते हैं.

फोल्डर या लेबल

क्या आपके मेल बॉक्स में सैकड़ो या हजारो मेल पड़ी हुयी हैं? तो क्यों न अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग सब्जेक्ट या अलग अलग श्रेणी के ई–मेल को अलग अलग फ़ोल्डरों में सेव किया जाए, ताकि जरुरत पड़ने पर हम अपने आसानी से मेल को ढूंढ सकें, साथ ही हमारा मेल बॉक्स भी साफ़ सुथरा बना रहे. अपने ई मेल पर अलग–अलग नाम या सोर्स के आधार पर मेलों को ऑर्गनाइज़ करने के लिए हम मेल में फोल्डर/लेबल नाम के लिंक पर क्लिक करके हम अपनी इच्छा के अनुसार फोल्डर का नाम रख सकते हैं. अब किसी भी मेल को किसी विशेष किसी फोल्डर में भेजने के लिए उस मेल पर राइट क्लिक करके मूव टू के ऑप्शन को चुनकर जिस फोल्डर में मेल को सेव करना चाहते हैं उस पर क्लिक करें. इस तरह आपका मेल बॉक्स ऑर्गनाइज हो जाता है, और आप आसानी से चाहे गए मेल तक आसानी से पहुंच सकते हैं.

मेल फिल्टर

आपकी मेल आई डी पर अलग–अलग विषयों से जुड़े बहुत से मेल आते हैं ऐसे में यदि आप एक ही विषय(सब्जेक्ट) के मेल को एक साथ देखना चाहते हैं तो ऐसा भी संभव है इसके लिए इसके लिए मेल के दाहिनी तरफ(जीमेल में) सेटिंग्स में जाएं फिर फ़िल्टर टैब पर क्लिक करें. क्लिक करने पर दो विकल्प दिखाई देंगे. पहला क्रिएट ए न्यू फिल्टर जिसमें की हम भेजने वाले के ईमेल नाम, सब्जेक्ट, अटैचमेंट या मेल साइज के आधार पर मेल को अलग कर सकते हैं. वहीं दूसरे ऑप्शन में इम्पोर्ट फिल्टर्स होता है जिसमें कि पहले से बनाए गए या अन्य जगह पर सेव किए हुए फिल्टर नियम को यहां सीधे प्रयोग में लाकर अपनी जरुरत के हिसाब से मेल को आसानी से खोज सकते हैं.

सभी मैसेज को दूसरे ईमेल पे फॉरवर्ड करना

अगर आप चाहते है की आपके किसी मेल एड्रेस पर जो मेल आते हैं वो किसी और के पास या आपके किसी और ईमेल अकाउंट में खुद–ब–खुद चला जाए. तो ऐसा करने के लिए बस आप एक सेटिंग में बदलाव कीजिए और दूसरे एकाउंट में ईमेल पढ़िए इसके लिए(जीमेल में) सेटिंग्स में जाकर फॉरवार्डिंग एंड पॉप/आईमैप ऑप्शन में जाकर ऐड ए फॉरवार्डिंग एड्रेस बटन पर क्लिक करें. फिर एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा जिसमे उस ईमेल का पता लिखें जिसपर मेल को फॉर्वर्ड करना है. इसके बाद नेक्सट बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आपसे कन्फर्म करने के लिए पूछा जाएगा कि अगर आप सहमत है तो प्रोसीड बटन पर क्लिक करें. आपके क्लिक करते ही दूसरे मेल पर एक वेरिफिकेशन मेल पहुंचेगा. इस लिंक पर क्लिक करते ही ये सेवा अपने आप शुरू हो जाएगी. यदि आप इसे बंद करना चाहते हैं तो वापस उसी लोकेशन पर जाकर डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें. ऐसा करते ही सेवा बंद हो जाएगी.

जोड़े अन्य ईमेल से और मेल करें एक से

यदि आप अपने जीमेल, याहू या हॉटमेल जैसे अलग अलग डॉमेन से या अपने प्राइवेट कंपनी के डोमेन के मेल भेजना चाहते हैं और बार–बार लॉगिन नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है. बहुत सारे ईमेल को एक ही मेल से जोड़ा जा सकता है और एक ही मेल पर लॉगइन करके मेल भेजे जा सकते हैं. वो भी अपनी पसंद के डॉमेन मेल से. आप अपने जीमेल अकाउंट से 5 ई–मेल अकाउंट को जोड़ सकते हैं. इसके लिए सेटिंग्स में जाकर एकाउंट्स एंड इम्पोर्ट टैब में क्लिक करें. इसके बाद सेंड मेल एज ऑप्शन में जाएं और ऐड एनअदर ईमेल एड्रेस योर ओन लिंक कर क्लिक करें. इसके बाद नियत जगह पर अपने ईमेल से संबंधित नाम और ई–मेल एड्रेस टाइप करें. यदि आपको जोड़े गए मेलों में से किसी मेल से संदेश भेजें जब आप किसी एक मेल पर जवाब चाहते हैं तो रिप्लाई टू एड्रेस भी जोड़ सकते हैं.

इसके लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें. उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन बटन कर क्लिक करें, वेरिफिकेशन पर क्लिक करते ही उससे संबंधित मेल पर एक ई–मेल चला जायेगा. अगर उसे आप एक्सेप्ट करते हैं. बस हो गया सेटिंग और आप अपने पहले वाले ई–मेल में जब नया मेल कंपोज करेंगे तो आप फ्रॉम वाले ऑप्शन के सामने एक ड्राप डाउन मेन्यू दिखेगा जिसमे सेट किये हुए ई–मेल को देखा जा सकता है. अब आप जिस मेल का प्रयोग करके मेल भेजना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके मेल सेंड कर सकते हैं.अगर इस सेवा को बंद करना हो तो एकाउन्टस एंड इम्पोर्ट टैब में जाकर जिस मेल को हटाना चाहते हैं उसके सामने के डिलीट बटन पर क्लिक करें.

इम्पोर्ट इमेल्स एंड कॉन्टेक्ट्स

यदि आप किसी पुराने ईमेल का बैकअप चाहते हैं या किसी अन्य ईमेल से अपने मेल्स और कॉन्टेक्ट्स को दूसरे मेल आईडी पर लाना चाहते हैं इसके लिए (जीमेल में) सेटिंग्स में जाकर एकाउंट्स एंड इम्पोर्ट सेक्शन में क्लिक करके इम्पोर्ट मेल एंड कॉन्टेक्ट्स ऑप्शन पर क्लिक करें. दूसरे ईमेल एड्रेस को फीड करें, इसके बाद आप कंटीन्यू बटन पर क्लिक करें. यदि आपका ईमेल एड्रेस सही रहा तो आपकेयूजरनेम और पासवर्ड का प्रयोग कर उस ईमेल में लॉगिन करना होगा अगर इसका ऑथेंटिकेशन हो गया तो आप उस मेल को यहां इम्पोर्ट कर सकते हैं.

कई भाषाओं में ईमेल लिख सकते हैं

अगर आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फ्रेंच जर्मन, चाइनीज या अन्य किसी भाषा मेंअपना संदेश लिखना चाहते हैं तो आप सेटिंग्स में जाकर जनरल टैब में लैंग्वेज सेक्शन में इनेबल लैंग्वेज टूल पर टिक करें. इसके एक्टिव होते ही आपको इनपुट टूल का ऑप्शन दिखने लगेगा. इसके बाद आप अपनी पसंद की भाषा में ई–मेल लिख सकते हैं.

किसी दूसरे ईमेल के मेल को अन्य मेल में कैसे प्राप्त करे

यदि आप किसी ई–मेल सर्विस प्रोवाइडर या प्राइवेट डोमेन के एक से अधिक ईमेल प्रयोग कर रहे हैं तो आप इससे अपने जीमेल पे सभी मेल्स को प्राप्त कर पाते हैं वो भी बिना किसी परेशानी और बिना किसी अन्य खर्चे के. इसके लिए (जीमेल) सेटिंग्स में जाकर एकाउंट्स एंड इम्पोर्ट टैब में क्लिक कर चेक मेल फ्रॉम अदर एकाउंट्स (यूजिंग पॉप 3) सेक्शन में जाकर–ऐड ए पॉप 3 मेल अकाउंट योर ओन लिंक कर पर क्लिक करें, इसके बाद सामने आये फॉर्म में ईमेल एड्रेस टाइप करें. जिसका मेल आप यहां चाहते हैं, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें. इसके बाद उपयुक्त जगह पर उस मेल का यूजर नाम, पासवर्ड, पॉप सर्वर का नाम (जैसे मेल डॉट जीमेल डॉट कॉम या मेल डॉट स्मार्टग्रुप्स डॉट इन या कुछ भी जो आपका सर्वर का नाम हो) और पोर्ट नंबर (जैसे 110 , 587, 465 , 995) भरे और ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर दें. अगर जानकारी सही है और सामने वाले सर्वर से मैच कर गई तो खुद ब खुद उस मेल पर के मेल इस मेल पर आने लगेंगे. यदि आप चाहें तो यहां पर मौजूद ऑप्शन क्लिक ऑन कॉपी ओन टू सर्वर ऑप्शन कर क्लिक कर सकते हैं जिससे की मेल की एक कॉपी पहले वाले मेल पर भी रहेगी. ■

smart7973@gmail.com

मर्सडीज की एसयूवी जीएलए क्लास

जर्मनी की लग्जरी कार बनाने मर्सडीज बेंज ने एसयूवी सेगमेंट का फायदा उठाने के लिए अपना जीएलए क्लास मॉडल लॉन्च की है. इसकी कीमत लगभग 32.75–36.9 लाख रुपये रखी है. जीएलए क्लास का मुकाबला बीएमडब्ल्यू 21, ऑडी क्यू 3, लैंड रोवर इवोक और वोल्वो वी40 से होगा. जीएलए क्लास पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन में मिलेगी. पेट्रोल ऑप्शन में 2 लीटर इंजन है और इसकी कीमत 36 लाख रुपये है, जबकि 2.2 लीटर इंजन केसाथ डीजल वर्जन की कीमत 32.75–36.9 लाख रुपये है. ■

जीएलए क्लास पेट्रोल और डीजल दोनों वर्जन में मिलेगी. पेट्रोल ऑप्शन में 2 लीटर इंजन है और इसकी कीमत 36 लाख रुपये है, जबकि 2.2 लीटर इंजन केसाथ डीजल वर्जन की कीमत 32.75–36.9 लाख रुपये है.

ब्लैकबेरी पासपोर्ट लान्च हुआ

स्मार्टफोन बाजार पर धमक जमाने के लिए ब्लैकबेरी ने अपना सबसे मंहगा स्मार्टफोन ब्लैकबेरी पासपोर्ट लॉन्च कर दिया है. कंपनी रारेप.ळप पर प्री–बुकिंग कराने वाले ग्राहकों को 5000 रुपये का गिफ्ट कार्ड देगी. चौकोर आकार होने की वजह से ब्लैकबेरी केइस फोन को पासपोर्ट का नाम दिया गया है. इस फोन की स्क्रीन 4.5 इंच का है जबकि स्क्रीन रेजोल्यूशन 1440 गुणा1440 पिक्सल है.

यह फोन ब्लैकबेरी के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम 10 ओएस पर आधारित है और यह 2.2 जीएचजेड क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर से लैस है. इसका रैम 3 जीबी है और इसमें 32 जीबी स्टोरेज है. इसमें 128 जीबी माइक्रो एसडी स्लॉट है.

इसमें 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस रियर कैमरा है और फ्रंट कैमरा 2 मेगापिक्सल का है. इसके रियर कैमरे में एलईडी फ्लैश है और यह 1080पी फ्रेम रेजोल्यूशन का वीडियो 60 फ्रेम प्रति सेकेंड की स्पीड से शूट कर सकता है. इसके फ्रंट कैमरे से भी 720 पिक्सल फ्रेम रेजोल्यूशन का वीडियो शूट हो सकता है.

इसके अन्य फीचर हैं, 4जी, 3जी, वाई–फाई, ब्लूटुथ, जीपीएस और एनएफसी. इसकेअलावा इसमें एक्सीलरोमीटर, जाइरो, एंबिएंट लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह फीचर हैं. इसके अलावा इसमें प्रॉक्सिमिटी और मैग्नेटिक सेंसर भी हैं. इस फोन की कीमत 49,990 रुपये है. ■

टीवीएस का दो नए रंगों में जुपिटर स्कूटर

टीवीएस ने स्कूटर सेगमेंट में अपना 110 सीसी जुपिटर मॉडल लॉन्च किया था. कंपनी ने अब जुपिटर को दो और नए रंगों में पेश किया है. जुपिटर टाइटेनियम ग्रे, मरक्यूरी व्हाइट, मिडनाइट ब्लैक और वोल्कैना रेड रंगों में पहले से उपलब्ध है. इसकी कीमत लगभग 44,200 रुपए है. टीवीएस जुपिटर 109.7सीसी, 4 स्ट्रोक, सिंगल सिलेंडर एयर–कूल्ड, ओएचसी इंजन पर दौड़ता है. जुपिटर का पावरट्रेन 5.88 केडब्ल्यू (8 बीएचपी) पावर देने में सक्षम है. कंपनी का दावा है कि जुपिटर 62 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है. ■

महिन्द्रा का गस्टो स्कूटर

महिन्द्रा ने 110 सीसी का एक गस्टो स्कूटर लॉन्च किया है. इसकी दिल्ली एक्सशोरूम की कीमत 43,000 रुपए है. महिन्द्रा की तरफ से लॉन्च किए गए इस टू व्हीलर को ग्लोबल स्कूटर कहा गया है. कंपनी के अनुसार, इसका डिजाइन इटली केहिसाब से किया गया है और साथ ही इसमें लगा एम–टेक इंजन इस स्कूटर को अन्य स्कूटर्स से अलग बनाता है. इसका इंजन 109.6सीसी का फोर–स्ट्रोक, एयर कूल्ड एम–टेक इंजन है, जो 8 बीएचपी की पावर और 9 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. यह स्कूटर दो वैरिएंट में उपलब्ध होगा, डीएक्स और वीएक्स. डीएक्स वैरिएंट की कीमत 43,000 रुपए है और वीएक्स वैरिएंट की कीमत 47,000 रुपए है. महिन्द्रा गस्टो की सीट पहले से चले आ रहे स्कूटर की तरह पीछे की तरफ से न खुलकर आगे से खुलती है. गस्टो की सीट सुविधा के हिसाब से एडजस्ट की जा सकती है. इसमें किक अन्य स्कूटर की अपेक्षा काफी आगे की तरफ दी गई है, ताकि बैठे–बैठे भी कोई व्यक्ति स्कूटर को आसानी से स्टार्ट कर सके. हालांकि, इसमें पुश स्टार्ट बटन भी दिया गया है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

17th Asian Games INCHEON 2014

मिशन रियो

कब होगा भारत से कांस्य युग का खात्मा

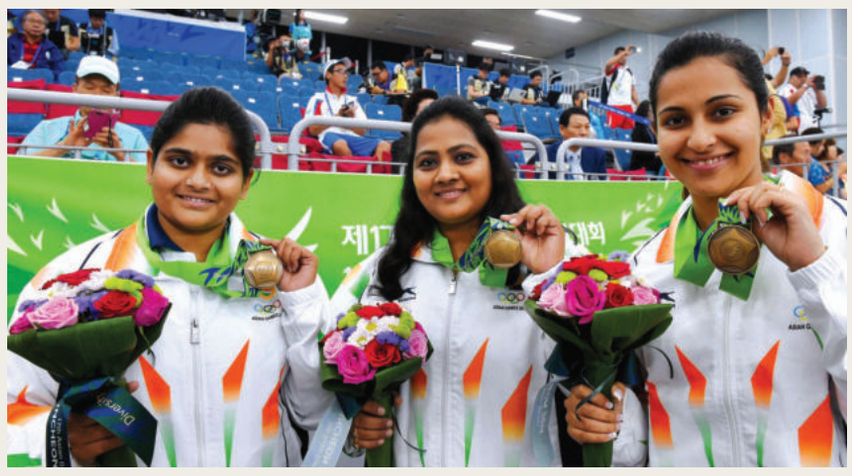

मोदी सरकार ने इस साल के केंद्रीय बजट में राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की तैयारी के लिए फंड स्वीकृत किया था. ताकि खिलाड़ी इन खेलों की तैयारी कर सकें साथ ही जरूरत होने पर विदेशों में जाकर ट्रेनिंग ले सकें. लेकिन सरकार ने खिलाड़ियों के लिए जो घोषणा की तब तक बहुत देर हो चुकी थी खिलाड़ी अंतिम दौर की तैयारी में जुटे थे. खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने के लिए ग्लासगो जाने की तैयारी कर रहे थे. ऐसे में खिलाड़ियों को न तो पैसे मिल पाए और न ही फंड का सही उपयोग हो पाया.

नवीन चौहान

भारत में खेलों में लंबे समय से चल रहा कांस्य युग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है. पिछले महीने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में सोने की थोड़ी चमक दिखाई पड़ी थी, लेकिन वह चमक दक्षिण कोरिया के इंचियोन में संपन्न हुए एशियाई खेलों बरकरार नहीं रही. भारत ने एशियाई खेलों में 11 स्वर्ण पदकों सहित कुल 57 पदक जीते और पदक तालिका में छठवें स्थान पर रहा. यहां पर भी भारतीय खिलाड़ियों का बड़ी संख्या में कांस्य पदक जीतने का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा. भारतीय खिलाड़ियों ने 37 कांस्य पदक जीते. ऐसे तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह का पदक जीतना एक बड़ी उपलब्धि होती है. यह खिलाड़ी की सालों की मेहनत का नतीजा होती है. लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक और एशियाई खेलों जैसे बड़े मंच पर छोटी–छोटी चूक कर बैठते हैं और उन्हें स्वर्ण की जगह रजत अथवा कांस्य पदक से संतोष करना पड़ता है. यही कहानी एक बार फिर 17 वें एशियाई खेलों दोहराई गई. हालांकि भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन भारत की झोली में सबसे ज्यादा कांस्य पदक ही आए. अभिनव बिंद्रा, मेरी कॉम, जीतू रॉय, सानिया मिर्ज़ा, सौरभ घोषाल, योगोश्वर दत्त जैसे खिलाड़ियों ने देश को स्वर्णिम सफलता दिलाई. यह बड़े खेद का विषय है कि आजादी के 66 साल बाद भी भारत खेलों की दुनिया में कुछ गिने चुने खेलों में ही अपनी पकड़ बना पया है. कुछ गिने चुने खेलों या स्पर्धाओं में ही निश्चित रुप से भारतीय खिलाड़ियों से पदक की आशा की जाती है उनमें टेनिस, कुश्ती, बॉक्सिंग, शूटिंग, कबड्डी और हॉकी आदि शामिल हैं. इन एशियाई खेलों इस सूची में स्क्वैश और डिस्कस थ्रो का नाम भी जुड़ गया है.

वर्ष 2010 में चीन के ग्वांगजू में हुए एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने 14 स्वर्ण, 17 रजत और 34 कांस्य पदक सहित कुल 64 पदक अपने नाम किए थे. भारतीय खिलाड़ियों ने जितने पदक जीते थे उनमें से आधे से ज्यादा कांस्य पदक थे. वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 6 पदक जीते थे. जिनमें दो रजत और चार कांस्य पदक थे. पिछले महीने ग्लास्गो में संपन्न हुए एशियाई खेलों में 15 स्वर्ण, 30 रजत और 19 कांस्य पदक जीते थे. तब इस ट्रेंड में बदलाव के संकेत दिखाई दिए थे लेकिन एशियाई खेलों में भारत एक बार फिर उसी ढर्रे पर वापस आ गया. एशियाई खेलों के दौरान स्वर्ण पदकों के लिए जूझते रहे. बीच–बीच में सोने–चांदी की चमक दिखाई पड़ती लेकिन कांसे के नीचे वो पदक दबे रहे. आखिरी दौर में आते आते टेनिस, हॉकी, कबड्डी और एथलेटिक्स में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और कुछ और स्वर्ण और रजत पदक भारत की झोली में डाल दिए.

ओलंपिक या एशियाई खेल जैसे किसी भी खेल आयोजन में एथलेटिक्स स्पर्धा में सबसे ज्यादा पदक दांव पर लगे होते हैं. इंचियोन एशियाई खेलों में 47 स्वर्ण पदक सहित कुल 141 पदकों को जीतने के लिए विभिन्न एशियाई देशों के खिलाड़ी एक दूसरे से भिड़े. लेकिन भारतीय खिलाड़ी मात्र 12 पदकों पर कब्जा कर सके जिनमें दो स्वर्ण, तीन रजत और सात कांस्य पदक शामिल हैं. एथलेटिक्स स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक सीमा पुनिया ने डिस्कस थ्रो में और 4 गुणा 400 रिले में महिलाओं ने दिलाया. एथलेटिक्स में महिलाएं पुरुषों से आगे रहीं और कुल आठ पदक जीते जिसमें एक स्वर्ण, दो रजत और पांच कांस्य पदक शामिल हैं. पुरुष खिलाड़ी एथलेटिक्स स्पर्धाओं केवल एक रजत और दो कांस्य सहित केवल तीन पदक जीत सके.

मोदी सरकार ने इस साल के केंद्रीय बजट में राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों की तैयारी के लिए फंड स्वीकृत किया था. ताकि खिलाड़ी इन खेलों की तैयारी कर सकें साथ ही जरूरत होने पर विदेशों में जाकर ट्रेनिंग ले सकें. लेकिन सरकार ने खिलाड़ियों के लिए जब घोषणा की तब तक बहुत देर हो चुकी थी. खिलाड़ी अंतिम दौर की तैयारी में जुटे हुए थे. खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने के लिए ग्लासगो जाने की तैयारी कर रहे थे. ऐसे में खिलाड़ियों को न तो पैसे मिल पाए और न ही फंड का सही उपयोग हो पाया. ऐसे में हम उनसे इन प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और स्वर्ण पदक की आशा कैसे करते हैं. फिलहाल जो भी खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं, यह उनकी अपनी मेहनत, समर्पण, प्रतिभा और त्याग का फल है. ये खिलाड़ी परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे हैं. यह बात जग जाहिर है कि भारतीय खिलाड़ियों के पास ट्रेनिंग की कमी है. खिलाड़ियों के पदक जीतने की राह में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की व्यवस्था न होना सबसे बड़ा रोड़ा है. दूसरे देशों में खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण दिया जाता है. और भारतीय खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव में खेलना होता है, ऐसे में देश की जनता उनसे विश्व स्तर पर श्रेष्ठ प्रदर्शन की उम्मीद लगाए रहती है. उस वक्त यह किसी को याद नहीं रहता कि बिना सुविधा के ये खिलाड़ी हर तरह से संपन्न देशों की टीमों से कैसे पार पाएंगे? और जब खिलाड़ी जूझते हुए परास्त होते हैं तो देश में हर जगह उनकी आलोचना शुरू हो जाती है. लेकिन कोई यह नहीं सोचता है कि आखिर ऐसी हालत क्यों है? यदि हमें कोई इमारत खड़ी करनी है तो इसके लिए सबसे पहले नींव मजबूत करनी होगी, यदि नींव ही कमजोर होगी तो निश्चित तौर इमारत कमजोर होगी.

यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत में खिलाड़ियों को वैसी सुविधाएं क्यों नहीं हासिल हैं जैसा कि विदेशों में है? ऐसा हमारे तरीकों में खामियों की वजह से ही होता है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पैसा खिलाड़ियों पर उनकी सफलता के बाद बरसाया जाता है, अगर उतना ही पैसा पहले ही खेलों के विकास पर लगाया जाए और खिलाड़ियों की सफलता के साथ–साथ कोचों और अकादमियों को भी पुरस्कृत किया जाए तो निश्चित तौर पर देश में खेलों की तस्वीर बदलेगी. देश में विकास का जो मॉडल पिछले दो–तीन दशकों में देश में गढ़ा गया है उनमें खेल को जगह नहीं मिली है. वहां खेलों को शामिल न करने का आधार पैसे की कमी को नहीं माना जा सकता, यदि यह तर्क दिया जाता है तो वह निराधार है. हमारे यहां प्राथमिक स्कूलों में खेलों को बढ़ावा नहीं मिलता,जबकि खेल की स्कूलों में ही होती है, देश में अगर खेल संस्कृति का विकास करना है तो सरकार को अपनी नीतियों में मूलभूत और प्रभावी बदलाव लाना होगा. सुशील कुमार, एम सी मेरीकॉम जैसे कुछ गिने चुने खिलाड़ियों को छोड़ दें तो भारतीय खेल इतिहास में बहुत कम ही ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने ओलंपिक या एशियाई खेल जैसे बड़े स्टेज पर अपने प्रदर्शन को दोहराया या उसमें सुधार किया है और न ही उसे अगली किसी पीढ़ी के लिए मानक बनाकर पेश करने की कोशिश की है. मिल्खा सिंह, पी.टी. ऊषा, कर्णम मल्लेश्वरी, राज्यवर्धन सिंह राठौर और अभिनव बिंद्रा ही क्यों न हों? कोई भी अपनी सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों को बरकरार नहीं रख पाया. केवल पहलवान सुशील कुमार ही ऐसा कर पाने में कामयाब हुए हैं बीजिंग ओलंपिक में कांस्य और लंदन ओलंपिक में कुश्ती का रजत पदक जीता था. इसी वजह से कुश्ती में खिलाड़ियों की नई खेप भी आ रही है. सुशील युवा खिलाड़ियों के लिए आदर्श बन गए हैं. भारत में हर पहलवान अब सुशील कुमार बनने का सपना देखता है. इसी वजह से देश में योगेशवर दत्त, और नरसिंह यादव जैसे नए पहलवान सामने आ रहे हैं. हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कुश्ती और बॉक्सिंग के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं. जिसका सीधा असर कुश्ती में भारत के प्रदर्शन में दिखाई दे रहा है. ऐसा अगर देश के हर राज्य में वहां की खेल प्रतिभाओं को देखकर होने लगे तो देश में खेलो की चाल, चरित्र और चेहरा पूरी तरह बदल जाएगा. ऐसा होने पर ही भारत खेलों के कांस्य युग का खात्मा हो पाएगा.■

navinonline2003@gmail.com

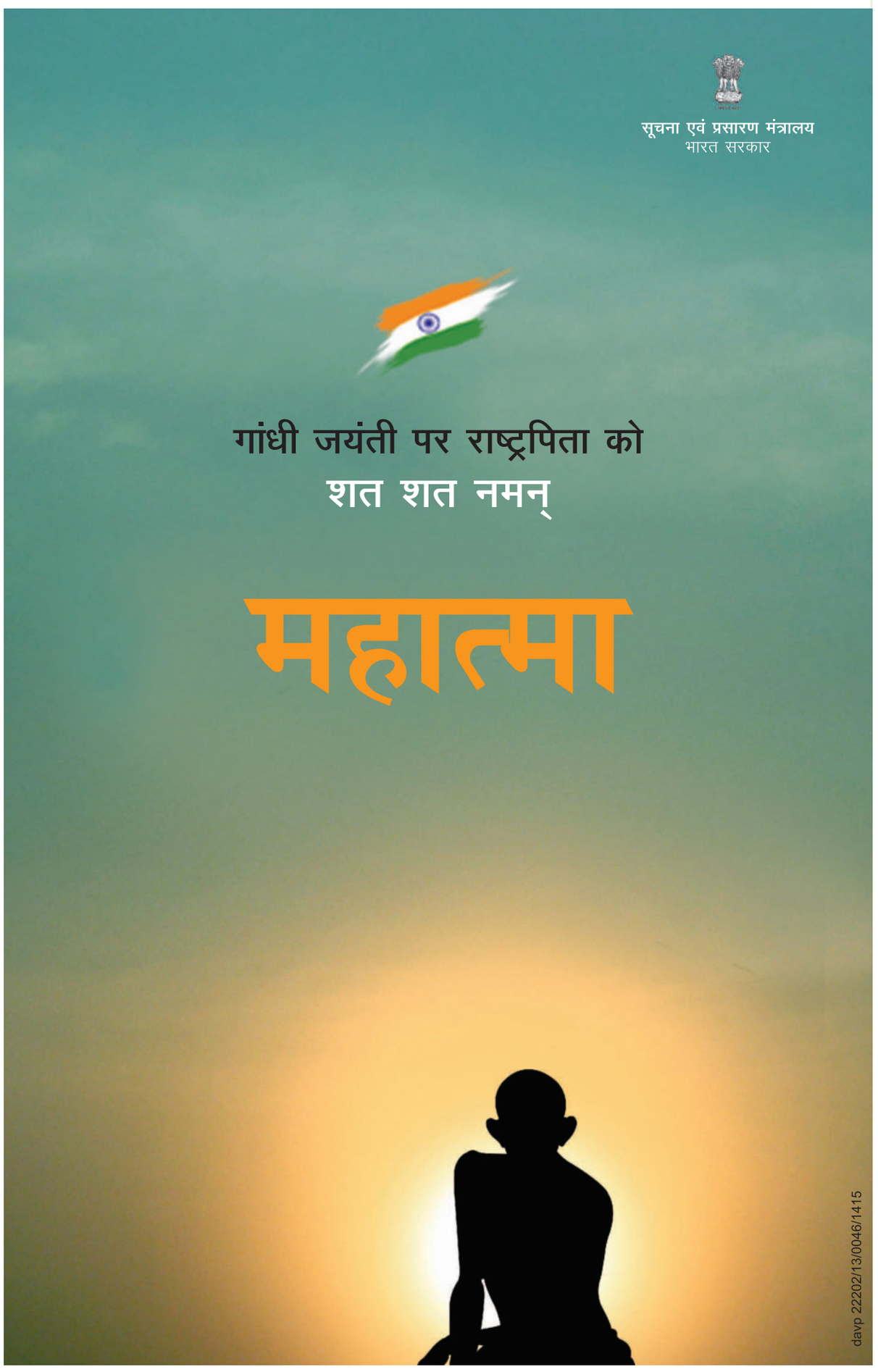

फीस बढ़ाकर फिल्में गवां रही हैं दीपिका

आज दीपिका बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्री हैं. एक फिल्म में काम करने के लिए दीपिका 10 करोड़ से भी ज्यादा फीस लेती हैं. उन्होंने इस रेस में कैटरीना कैफ, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसी लीडिंग एक्ट्रेसेस को भी पीछे छोड़ दिया है. उनकी इस डिमांड को देखते हुए छोटी बजट की फिल्मों के निर्माता निर्देशक उन्हें फिल्म ऑफर करने से कतरा रहे हैं.

डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की नंबर शीर्ष अभिनेत्री मानी जाती हैं. उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया है. पिछले साल बेस्ट एक्ट्रेस के अधिकांश अवार्डस उनकी झोली में आ गिरे. इसके बाद उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह सफलता की नई ऊंचाइयां छूने लगीं. इसके बाद उन्होंने अपना मेहनताना भी बढ़ा दिया. दीपिका सफलता के नए मुक़ाम की ओर बढ़ रही है, इसके साथ ही वह कई फिल्मों के प्रस्ताव ठुकरा भी रही हैं. कई निर्देशक तो उन्हें अपनी फिल्मों में लेने से झिझक रहे हैं. फिल्म किल दिल के लिए दीपिका को साइन किया गया था लेकिन कुछ समय बाद उनकी जगह परिणिति चोपड़ा को ले लिया गया. इसका कारण दीपिका की बढ़ी हुई फीस लग रही है. आज दीपिका बॉलीवुड की सबसे महंगी अभिनेत्री हैं. एक फिल्म में काम करने के लिए दीपिका 10 करोड़ से भी ज्यादा फीस लेती हैं. उन्होंने इस रेस में कैटरीना कैफ, करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा जैसी लीडिंग एक्ट्रेसेस को भी पीछे छोड़ दिया है. उनकी इस डिमांड को देखते हुए छोटी बजट की फिल्मों के निर्माता निर्देशक उन्हें फिल्म ऑफर करने से कतरा रहे हैं. करीना, कैटरीना और प्रियंका एक फिल्म के लिए औसतन 5 से 6 करोड़ रुपये लेती हैं. इस दौड़ में दीपिका इन सब से काफी आगे निकल गई हैं. फिल्म किल दिल में दीपिका के अपोजिट रणवीर सिंह को कास्ट किया गया था. इससे पहले दीपिका और रणवीर की जोड़ी गोलियों की रासलीला रामलीला में नज़र आई थी. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी. लेकिन दीपिका को रिजेक्ट कर उनकी जगह परिणिति चोपड़ा को दी गई है. वर्ष 2013 में दीपिका की फिल्में रेस-2, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस और रामलीला ने बॉक्स ऑफिस पर सौ करोड़ के क्लब में शामिल हुई थी. इन फिल्मों ने दीपिका को सफलता के शिखर पर पहुंचाया. जाने-माने निर्देशक संजय लीला भांसली ने अपनी आगामी फिल्म बाजीराव मस्तान के लिए भी दीपिका और रणबीर को चुना है लेकिन अभी तक शूटिंग की कोई तारीख तय नहीं हुई है. पहले संजय इस फिल्म के लिए सलमान खान और ऐश्वर्या रॉय को लेना चाहते थे. दीपिका आजकल अपनी आगामी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को लेकर खासा उत्साहित हैं. इसका निर्देशन फराह खान कर रही हैं. फिल्म में दीपिका के साथ शाहरुख खान हैं. लेकिन दीपिका के लिए महंगी अभिनेत्री का खिताब कहीं महंगा न पड़ जाए. ■

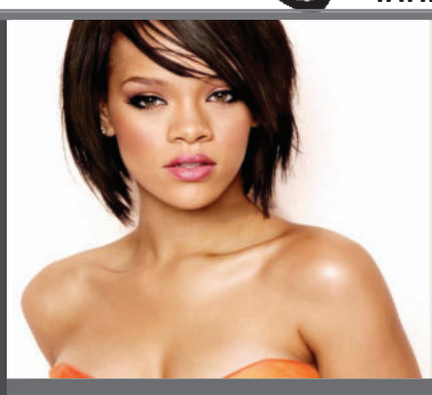

बॉन्ड फिल्म में नज़र आएंगी रिहाना

गायिका रिहाना, जेम्स बॉन्ड सीरीज की आने वाली नई फिल्म में अभिनय करने वाली हैं. बॉन्ड 24 नाम की यह फिल्म बॉन्ड सीरीज पर बनने वाली 24 वीं फिल्म है और इस फिल्म में रेहाना स्पेशल अपीयरेंस में होंगी. एक अंग्रेजी अखबार द डेली मिरर के मुताबिक इस फिल्म में एक्टिंग के लिए निर्माता ने 26 वर्षीय गायिका से संपर्क किया था. रेहाना बड़े पर्दे पर अपनी भूमिका को लेकर बेहद उत्साहित हैं. रिहाना खुद भी बॉन्ड फिल्मों की बहुत बड़ी प्रशंसक रही हैं और वह इसमें अभिनय करने के विचार को हमेशा से पसंद करती थीं. वह बॉन्ड 24 को लेकर बेहद उत्साहित है. इस फिल्म के निर्देशक सैम मेंडेस हैं और फिल्म की शूटिंग इस साल दिसंबर में शुरू हो सकती है. फिल्म के अगले साल नवंबर महीने में रिलीज होने की संभावना है.■

आत्मकथा लिख रही हैं आशा ताई

बॉलीवुड की जानी-मानी गायिका आशा भोसले आजकल अपनी आत्मकथा लिखने में व्यस्त हैं और वह अपनी आत्मकथा को लेकर बेहद उत्साहित हैं. आशा ताई को फिल्म इंडस्ट्री में काम करते छह दशक से ज्यादा का वक्त गुज़र चुका है. वह अपने छह दशक लंबे करियर के अनुभवों को किताब का रुप दे रही हैं. उनका कहना है कि यह किताब मेरे छह दशकों के सफर, जीवन के संघर्षों और दर्द की सच्ची दास्तान होगी. मैंने इसमें कुछ भी नहीं छिपाया है. पिछले एक साल से मैं इसे लिख रही हूं. यह किताब मूल रूप से हिंदी में होगी, इसका अनुवाद अंग्रेजी में भी प्रकाशित होगा. किताब अंतिम दौर में है जल्दी ही यह बाजार में उपलब्ध होगी.

रहमान के बेटे गाएंगे गाना

जाने माने संगीतकार ए आर रहमान के बेटे भी फिल्म जगत में कदम रखने जा रहे हैं. रहमान के बेटे बेटे अमीन फिल्मकार मणिरत्नकम की फिल्म में गाना गा सकते हैं. इससे पहले वे कपल्सा रीट्रीट में गीत गा चुके हैं. रहमान इससे खुश हैं लेकिन चाहते हैं कि उनका बेटा अभी पढ़ाई में ध्यान दे. इस वजह से रहमान थोड़ा परेशान हैं कि बेटे की पढ़ाई में कोई दिक्कत पैदा न हो. रहमान ने बताया कि उनके बेटे केलिए कई फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं लेकिन अभी वह अमीन को इससे दूर रखना चाहते हैं.

हॉलीवुड में कुछ खास नज़र नहीं आता : रितिक

बॉलीवुड स्टार रितिक रोशन का कहना है कि उन्हें हॉलीवुड में कुछ खास नज़र नहीं आता है. उन्हें हॉलीवुड से अब तक तकरीबन पांच-छह फिल्मों का ऑफर मिल चुका है लेकिन उन्हें स्क्रिप्ट ही पसंद नहीं आई. उन्हें फिल्मों की कहानी भी दमदार नजर नहीं आती है.

कपिल बिग-बॉस को होस्ट कर सकते हैं: सलमान

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का कहना है कि कपिल शर्मा बिग बॉस को होस्ट कर सकते हैं. सलमान का कहना है कि उनके मुकाबले एक बिग बॉस के होस्ट के रूप में स्टैंडअप कॉमेडियन ज्यादा अच्छा न्याय कर सकता है. फिलहाल सलमान खान बिगबॉस के आठवें सीजन को होस्ट कर रहे हैं. और वह कपिल को लेकर काफी गंभीर हैं. इसी वजह से उन्होंने बतौर होस्ट कपिल के नाम को आगे किया है. सलमान का कहना है कि बिग बॉस जिस तरह का शो है, उसके लिए एक स्टैंडअप कॉमेडियन की जरूरत है, हम चाहकर भी उस तरह की कॉमेडी नहीं कर सकते जैसे कॉमेडियन करते हैं. कुछ चीजें नेचुरल होती हैं, और कपिल में लोगों को हंसा सकने की नेचुरल क्षमता है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

वरूण और दीपिका एक साथ नज़र आएंगे

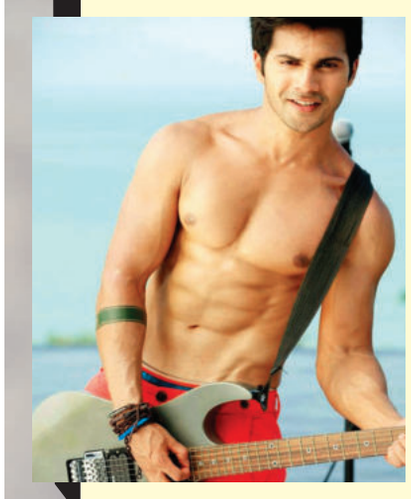

क्लीवेज विवाद के बाद दीपिका पादुकोण एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार उनके चर्चा में आने का कारण एक नई फिल्म है जिसमें वह वरुण धवन के साथ रोमांस करती नज़र आयेंगी. यह फिल्म हॉलीवुड फिल्म द फॉल्ट इन अवर स्टार्स की हिंदी रीमेक होगी. फिल्म का जो पहला पोज नजर आया है, उसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं. वरुण अभी बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं और दीपिका स्टार हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या दोनों एक साथ अपनी-अपनी भूमिकाओं से न्याय कर पाएंगे. इस फिल्म के निर्माता होमी अदजानिया हैं, जिन्होंने कॉकटेल और फाइंडिंग फेनी जैसी हिट फिल्मों का निर्माण किया है. इन दोनों फिल्मों में दीपिका काम कर चुकी हैं, दीपिका की अदजानिया के साथ यह तीसरी फिल्म होगी. अब देखना यह है वरुण और दीपिका की जोड़ी दर्शकों को कितनी पसंद आती है. फिल्म की शूटिंग 2015 में शुरू होगी.■

फिल्म को हिट करवाने के लिए मैं हूं ना

शाहरूख

बॉलीवुड के किंग शाहरूख खान आजकल फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को हिट कराने के लिए प्रमोशन में व्यस्त हैं. इस फिल्म का निर्देशन फराह खान ने किया है. फिल्म में शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण, बोमन ईरानी, विवान शाह और अभिषेक बच्चन मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म के गानों को दर्शक पसंद कर रहें है. फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफल बनाने के लिए शाहरुख कह रहे हैं मैं हूं ना. शाहरूख खान का कहना है कि लीक से हटकर बनाई गई फिल्में उनकी उपस्थिति से हिट हो जाती हैं. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा स्टार हूं. लोग मुझे पसंद करते है, इसलिए लीक से हटकर बनाई गई फिल्मों में भी वो मुझे देखना पसंद करते हैं. शाहरूख ने माया मेमसाब, ओह डार्लिंग, ये है इंडिया, डर, बाज़ीगर, स्वदेश, चक दे इंडिया जैसी लीक से हटकर बनाई गई कई फिल्मों में काम किया है. शाहरुख का कहना है कि जब भी मेरे सामने लीक से हटकर बनने वाली फिल्म का ऑफर आता है तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं. आम तौर पर दर्शक शाहरुख को रोमांटिक रोल में देखना पसंद करते हैं. दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे, कुछ-कुछ होता है, कभी खुशी, कभी गम जैसी फिल्मों में शाहरुख की भूमिका काफी पसंद आई थी. स्वदेश और चक दे इंडिया जैसी फिल्मों को दर्शकों और समीक्षकों दोनों ने सराहा था. इस पर शाहरुख का कहना है कि दर्शक मुझे इतना पसंद करते है वो मुझे सभी तरह की फिल्मों में देखना पसंद करते है. इसलिए लीक से हटकर फिल्म बनाने में भी मैं सहज महसूस करता हूं. फिल्म चक दे इंडिया की सफलता मेरे करियर की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है इसमें दर्शकों के रिस्पॉनसं को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था. ■

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

www.chauthiduniya.com

A RURAL REVOLUTION WITH A DURABLE COMPETITIVE EDGE Page 4

Secular Arithmetic Goes Against BJP
DECODING THE BY- ELECTIONS Page 6

Maneka Gandhi
SOYA MILK VERSUS COW'S MILK Page 11

CHAUTHI DUNIYA

POSTAL REGD. NO. UP/GBD-164/2013-15, RNI NO. UP ENG/2012/47802 India's Only Pro-People Weekly

Issue 12, Year-03 | 13 October - 19 October 2014 | Price : Rs. 5/-

WILL WE EVER GIVE Mary Kom A BHARAT RATNA? Page 15

OBAMA'S ISLAMIC STATE BLAME GAME Page 12

National Significance of Massive Rally in Haryana

WHY A UNITED JANATA PARIVAR MAKES SENSE

Photo : Prabhat Pandey

For success of a democracy, it is important that a strong and stable Government is there in the country. But more than that, it is important for a strong and trustworthy Opposition to be there. Today, a stable Government is present in the country, but where is the strong and trustworthy Opposition? The credentials of the Congress Party have been spoilt so much that it doesn't even have the required number of Lok Sabha MPs to become Leader of the Opposition. The people's trust in the Congress has been broken. The second problem is that the Congress Party is not doing anything either to win back the people's trust. After the elections, Rahul Gandhi and Sonia Gandhi have become passive. So the question arises: will an era of one party dominance -- which can prove to be dangerous for democracy -- return to the country once again? If the Congress becomes dormant, then it will be the responsibility of the regional parties to come forward and build a strong Opposition. A possible step in this direction was taken at Jind in Haryana recently: a rally of lakhs of people was held and Nitish Kumar fulfilled his duty by taking the initiative to unite the Janata Parivar, and thereby start a new turn in politics.

Manish Kumar

Jind, which is at the center of Haryana from a geographical point of view, became the center of politics in Haryana on September 25 this year. Since morning itself the flags of the Indian National Lok Dal (INLD) were flying on the streets of Haryana and supporters were in a rush to reach Jind. From Rohtak, about 60 kms from Jind, the roads were packed completely with vehicles. On the left and right sides of National Highway 41 and in the lanes at the side of the road caravans of INLD supporters were trying to move. There were jams everywhere and everywhere there was slogan shouting.

The condition on the roads was such that it was clear that many people among them would not be able to reach Jind or else will reach only after the rally is over. Those people who used their minds, got their vehicles off the highway and took side roads in between farms and reached the rally on time. It must be mentioned that the Jind rally was of lakhs of people, but there were no arrangements in place by the ruling Congress Government of Haryana. The INLD deserves congratulations that without the police and without official arrangements, it was successful in organising a rally of lakhs of people peacefully.

The rally took place outside Jind city near Safaido by-pass. Stretching as far as about 1 km, crowds of people was present. Most of the people who had come to participate in the rally were wearing traditional Haryanvi turbans and white clothes and holding green flags in their hands. Everywhere there were people and more people. Those people who thought that the late Chaudhary Devilal and the Chautala family have been forgotten by the people of Haryana or have been left behind were proved wrong by the numbers at the rally and all their arguments were silenced. The INLD's Jind rally proved to be a historic rally. Many people believe that in Haryana such a big rally has never been held before. In actual terms, people participated in this rally in lakhs. The number of people who were present under the canopy, much more than that were present outside the canopy. The canopy itself was so big that standing in its middle, it was difficult to tell who all were standing on the stage. This rally was organised by Om Prakash Chautala in honour of the great farmer leader and his father Chaudhary Devilal's 100th birth anniversary. However, it was completely a political rally. All the candidates of the INLD were present on the stage.

Addressing the sea of crowds, Chautala said that an INLD Government will be formed and he will take the oath of Chief Minister from jail itself. But to call this rally only a rally of Haryana elections would be wrong, because the seeds of a new chapter of Indian politics were sown at this rally. At this rally, a campaign to unite the Janata Parivar was begun. In the Jind rally, former Chief Minister H. D Deve Gowda, Chief Minister of Punjab Prakash Singh Badal, President of the Janata Dal United Sharad Yadav, former Chief Minister of Bihar Nitish Kumar and representative of the SP President Mulayam Singh Yadav, Shivpal Yadav, representative of the Samajwadi Janata Party and many well known people were present. All the leaders stressed one thing: that now everybody will have to unite. Nitish said that if members of the Janata Dal will be united, the beginning of new politics will be there. Sharad Yadav said that for making a new India there is a need for old partners to come together.

contd. on page-2

Politics Now Seems Driven By A Greed For Power

HAS THE ERA OF POLITICAL IDEOLOGY ENDED?

Santosh Bhartiya

It should finally be accepted that the era of ideology in politics has ended in the country, and finding any way, whatever, however it might be, to reach power has now become a new principle. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Jaiprakash Narayan, Ram Manohar Lohia, Deen Dayal Upadhyay – and if we take a name beyond them -- we can also include Guru Golwalkar and the principles proposed by him. All these people have become irrelevant in today's politics. That is why one should reach this conclusion that the era of ideology has taken farewell from the country.

The Shiv Sena and the Bharatiya Janata Party are of the same belief, be it belief in Hindutva, or be it belief with regard to Muslims, be it belief regarding the way of development. Both of them came together ideologically to do a different kind of politics. But the break between them didn't happen over ideology; instead it was over who will be in power and who can be removed from power completely and in that stead their own party can be established in power -- this has been the main reason for the breakup. On the other side, the Congress and the National Congress Party's principle were almost same, because of which they came together. In these principles there was secularism, including the poor in the race of development, and in these principles somewhere or the other farmers were there, even if they were big farmers. Between them too the break took place in Maharashtra because, instead of principles, more Ministers of whom should be there and who should become the Chief Minister and who could trip the other and establish complete control over power -- this selfishness became dominant.

Actually an illusion has been created. That illusion is that in the name of Narendra Modi, the Bharatiya Janata Party can win all the seats of the Legislative Assemblies. On the other side, after the Lok Sabha results, the by-elections in Bihar and Uttar Pradesh have given the indication that Narendra Modi's name will not work so much in the States. So the Shiv Sena here can win more seats.

contd. on page-2

Branding gave a farmers' cooperative a quasi-commercial strength, enabling it to adapt to competition.

Amul: Amazing Story Of India's Most Successful Brand

A RURAL REVOLUTION WITH A DURABLE COMPETITIVE EDGE

Creation of the Amul brand and its famous mascot gave a rural revolution a durable competitive edge… Amul is a brandname in its own right…Brand Amul is already present in over 50 countries. In India, it has 7,200 exclusive parlours…

Sohini Das

The tubby little moppet in the familiar polka-dotted dress is not just the Amul Butter mascot. The Amul Girl, who has entered urban lore with her regular appearance on billboards accompanied by clever catchphrases that comment on contemporary events, stands for the very fight its parent was born to counter.

The cooperative movement that began Gujarat back in 1946 was a movement against the atrocities of Polson Dairy, a locally-owned dairy in Anand, Gujarat, which allegedly procured milk from farmers at very low rates to sell to the Bombay (now Mumbai) Government.

Amul's architect in almost every way was the late Dr Verghese Kurien (who, ironically, died in the 50th year of the creation of the Amul girl). Arriving in Anand in 1949 as a Government employee to manage a dairy, he went from helping farmers repair their machinery to revolutionising the Indian dairy industry by scripting Operation Flood, a cooperative movement that turned India from a net importer of milk into one of the world's two largest producers today.

Not for nothing was Verghese Kurien called the Milkman of India, though his vision was a simple one of offering thousands of small dairy farmers centralised marketing and quality control facilities, the missing links in the dairy economy at the time. Thus, in 1973 the Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation was established to market milk and milk products manufactured by six district cooperative unions of Gujarat.

As R S Sodhi, GCMMF's managing director today, says, competition in the dairy sector 40 years ago was very different. "In the sixties and seventies, India was a milk-deficit country, not at all self-sufficient. "Milk powder was imported. From a per capita milk consumption of less than 110 grams per person to around 300 grams per person is a long way, and largely possible due to the cooperative movement." But branding also played a role, cleverly designed to add a tinge of nationalism to an essentially rural revolution. When experts asked Kurien to choose brandnames that would sound foreign, he wisely insisted on an Indian name. Thus, Amul (then short for Anand Milk Union Ltd) was born. Amul was not just a milk and butter brand, it became an umbrella for all the products that GCMMF marketed.

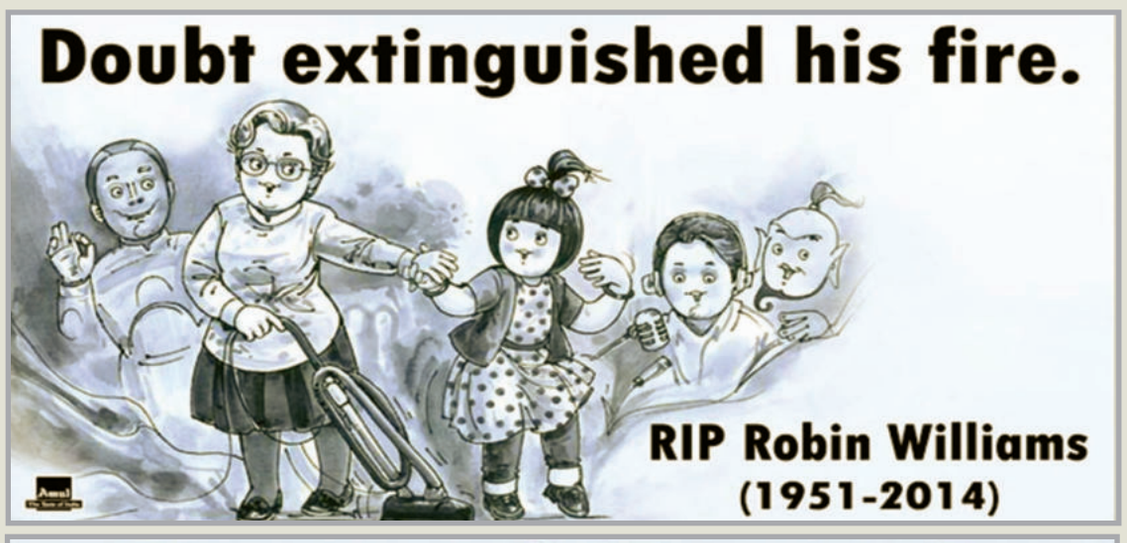

The (original) Amul Girl was created by Sylvester daCunha (daCunha Communications) to counter the Polson dairy girl. A seasoned marketer, Kurien gave DaCunha Communications immense creative freedom to release the Amul Girl ads without waiting to take permission from the company. The freedom is still maintained and is the the reason the Amul Girl is never late with her take on the world around, says the agency, led by Rahul daCunha, son of Sylvester. While the late Eustace Fernandes sketched the mascot, it was ad and theatre veteran Bharat Dabholkar who created some of the more popular ads. The first dairy, Kaira District Co-operative Milk Producers' Union, which created Amul in 1955, handed over the brand name to GCMMF in 1973.

By then, Amul had become a brandname in its own right. It is said that for Operation Flood, Kurien's idea of having farmers own the brand went a long way in creating a sense of ownership and, in turn, responsibility for the product's quality. This is the reason State federations now have their own brands -- Nandini in Karnataka, Verka in Punjab, Saras in Rajasthan and Mahananda in Maharashtra. Branding gave a farmers' cooperative a quasi-commercial strength, enabling it to adapt to competition.

Sodhi says GCMMF's professional management focused on fortifying its own distribution network by the eighties. In the nineties, it laid down the distribution of edible oil and frozen products and in 2000-2010, liquid milk outside of Gujarat. Since 2010, Amul's parent has been busy procuring milk from outside Gujarat. The supply chain spanning four distribution channels and pricing with attractive margins have ensured the federation can venture into new product categories and stay on top of competition.

"Even after the opening up of the sector in 1991, and the entry of several private dairies, there are few serious brands that have emerged in the domestic market," Sodhi says. Amul reaches one million retailers through a network of 10,000 dealers. Sodhi says since the mid-90s, Amul has been able to take the "range outside the security of our traditional products, milk powder and butter. "Since then, we have diversified to everything from ice-cream, curd to long-life flavoured milk." From being a local giant, GCMMF now wants to be a global company with a large domestic presence.

Brand Amul is already present in over 50 countries. In India, it has 7,200 exclusive parlours. But one of the challenges for Amul would be life after Kurien, whose iconic presence dominated the company long after his retirement. The ascension to being the chief of GCMMF has been a bone of contention with access to a huge vote bank of 3.3 million farmers. How GCMMF manages to rise above these controversies will shape its and Amul's future.■

-BS

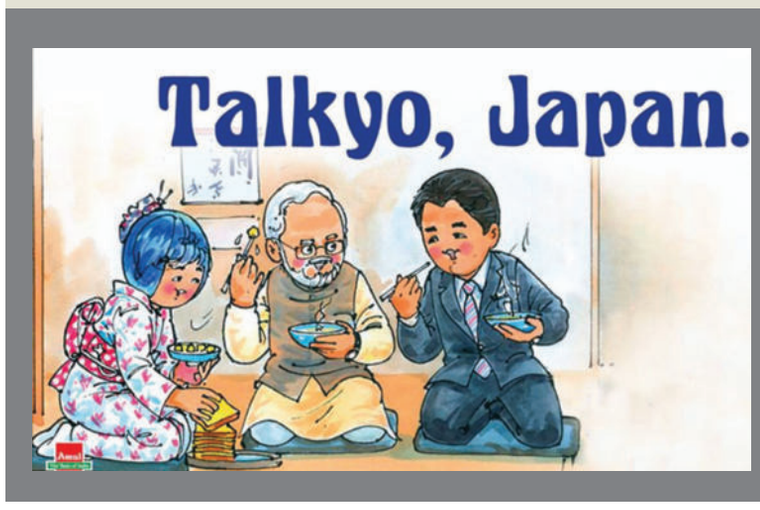

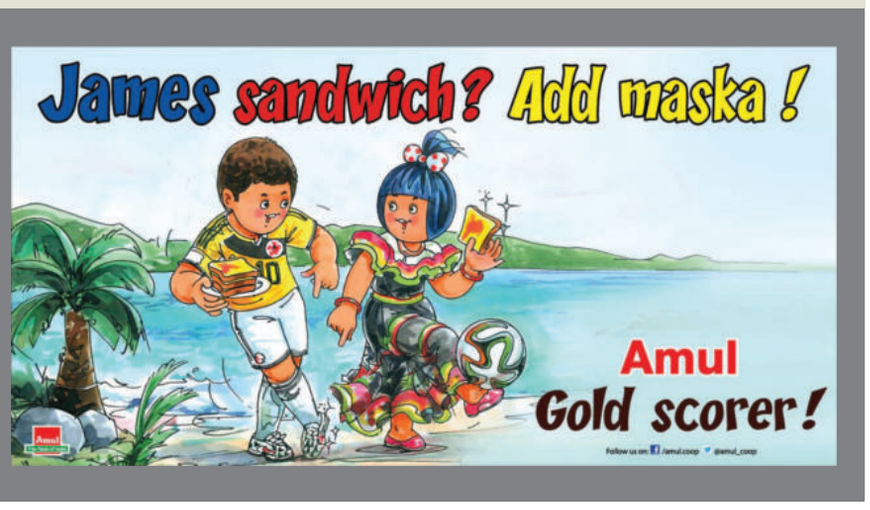

> Public Speaking 101 demands that you interact with the audience, and Mr. Modi has this down to a fine art.

7 HABITS OF MODI'S HIGHLY EFFECTIVE SPEECHES

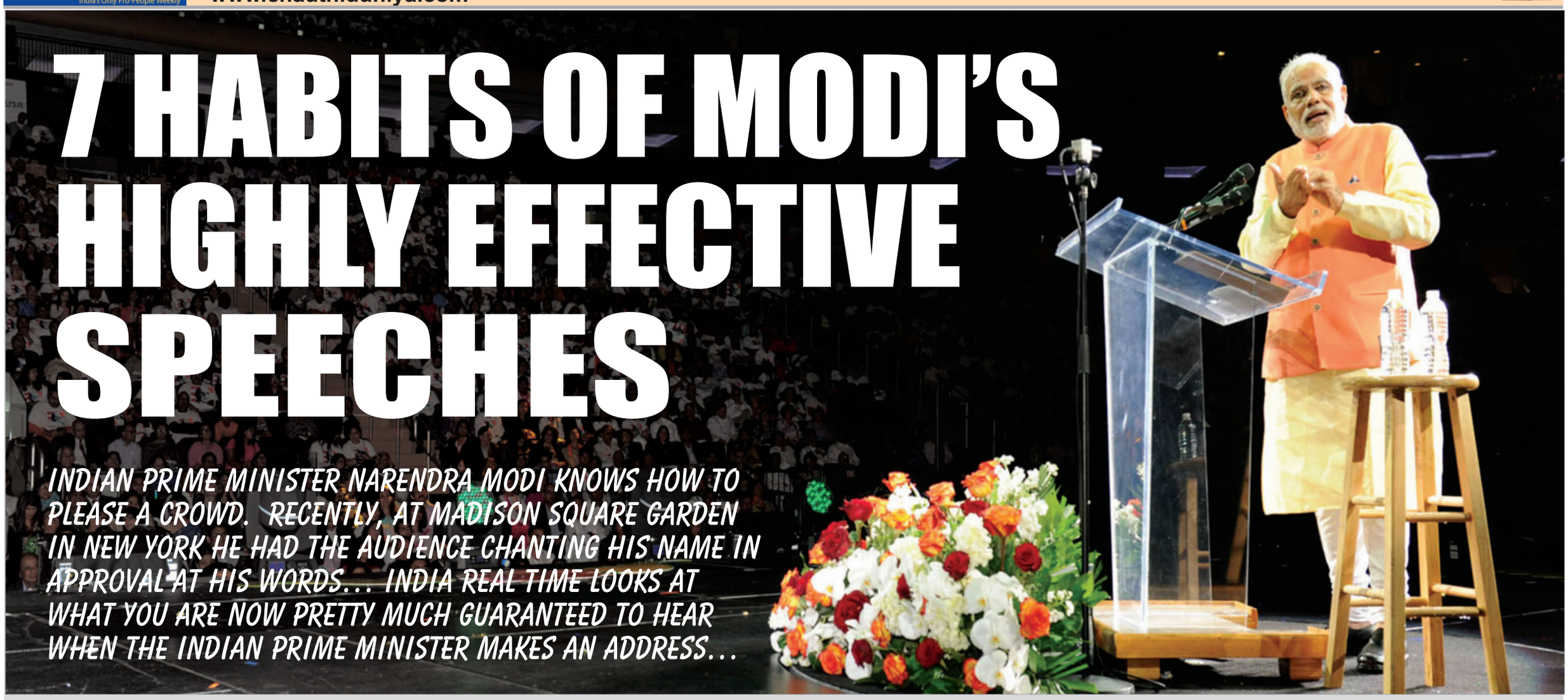

INDIAN PRIME MINISTER NARENDRA MODI KNOWS HOW TO PLEASE A CROWD. RECENTLY, AT MADISON SQUARE GARDEN IN NEW YORK HE HAD THE AUDIENCE CHANTING HIS NAME IN APPROVAL AT HIS WORDS... INDIA REAL TIME LOOKS AT WHAT YOU ARE NOW PRETTY MUCH GUARANTEED TO HEAR WHEN THE INDIAN PRIME MINISTER MAKES AN ADDRESS...

Shefali Anand

Mr. Modi tugged at the heartstrings of his Indian-American audience, appealing to their patriotism for mother India, throwing in some data to lend gravity to what he said, and then making them laugh. To some, including host Hari Sreenivasan, the whole thing started to sound a bit like a campaign rally. To others in the audience who hadn't heard him before it was electrifying, particularly compared to India's previous Prime Minister Manmohan Singh whose oratory would struggle to light up a torch bulb. But to those of us who have heard Mr. Modi address the public on other occasions, it sounded more like old wine in a very shiny new bottle.

We'd go as far as to say there is a formula to what makes a highly effective Modi Speech. India Real Time looks at what you are now pretty much guaranteed to hear when the Indian Prime Minister makes an address.

I Am a Small Man: Mr. Modi never fails to remind the public of his humble beginnings as a tea-seller. And why wouldn't he? There isn't a surer way for a leader to connect with the masses than to convince them that he is one of them. "I am a small man," Mr. Modi said on a Sunday night at Madison Square, adding that he wants to work for the small man by doing big things for him.

Cleanliness: Building toilets before temples, has long been a mantra of Mr. Modi, including when he was Chief Minister of Gujarat. He cleans up when he reminds the public about his cleanliness agenda. Sunday night, Mr. Modi spent several moments discussing the need to cleanse the River Ganges, India's most sacred waterway. He invoked Mahatma Gandhi's name (ticking the patriotism box), and said a clean India would be the best gift for Mr. Gandhi on the 150th anniversary of his birth in 2019.

Mr. Modi isn't the first person to talk about cleaning the holy river; former Indian Prime Minister Manmohan Singh identified it as national priority.

Aside from asking the audience to help with the cleanup, Mr. Modi hasn't yet come up with a convincing plan to complete the task. Earlier last month, when the Government presented a plan to India's Supreme Court to clean up the Ganges, the court said: "After seeing your action plan, it seems Ganga [the Ganges] will not be cleaned even after 200 years," according to NDTV news channel.

Involving the audience: Public Speaking 101 demands that you interact with the audience, and Mr. Modi has this down to a fine art. Take the clean up the Ganges example. He asked the audience: Should not the people of India help me in this initiative? Will you not help me in this initiative? "Yes!!!" shouted the crowd in response. Of course.

The funny anecdote: Mr. Modi's speeches can easily last an hour, but to keep the audience from getting too bored, he makes it a point to include a mix of one-liners to raise a laugh. On Sunday night, for instance, one of his anecdotes related to how India recently launched the cheapest mission to Mars in the world, at just $74 million. He said that in Ahmedabad, travel by an autorickshaw costs 10 rupees a kilometer. But India got to Mars for less than that: just seven rupees a km. Ha. Ha. Ha.

Snakes and Mice: This anecdote seems to be Mr. Modi's foreign crowd-pleaser. He pulled it out during a recent trip to Japan, and that wasn't its first airing. Basically, it involves the time he was asked during a visit to Taiwan whether India was a land of snake-charmers. Mr. Modi's response was to say that India was now a land of the mouse. The computer mouse. Get it? When Indians move the mouse it moves the entire world, the Prime Minister said, referring to India's large information-technology industry. This tickled the audience on Sunday, especially to people who probably left India before the country's tech industry was born.

Demographic dividend: In case you have missed the fact that India is a country of young people, Mr. Modi will happily remind you. Sixty five per cent of Indians are aged under 35, he said Sunday, repeating a line he used a lot in his campaign speeches.

Usually, this is followed by a spiel about how this large young population – known to economists as India's demographic dividend — will make the country grow rapidly in the future. He doesn't, however, add that millions of these young people and children are malnourished and don't know where their next meal will come from.

Finally, the Yojana: Mr. Modi typically likes to leave the crowd with what business folks call a takeaway. Typically, this is a program Mr. Modi plans to introduce. On Independence Day, Mr. Modi announced the Jan Dhan Yojana, an initiative to provide bank accounts for all. Sunday night, toward the end of his speech, he announced a plan to provide visa-on-arrival to Americans visiting India, and to merge some categories of visas for non-resident Indians. These were the only new pieces of information in his more than hour-long speech. Saving the best till last, perhaps, though the journalistic instinct in us can't help but point out: he buried the news.■

-WSJ

MODI IS A ROCK STAR, CHEERS MADISON SQUARE GARDEN

MODI MANIA

PRIME MINISTER NARENDRA MODI GETS A GRAND WELCOME AT MADISON SQUARE GARDEN IN NEW YORK, FIT FOR A ROCK STAR...

Lalit K Jha, Yoshita Singh

Indian-Americans from across the United States gave a "rock star" treatment to Prime Minister Narendra Modi at the prestigious Madison Square Garden in the Big Apple, where nearly 20,000 strong gathering of Indian Diaspora welcomed the Indian leader. Shouting slogans like 'Narendra Modi Zindabaad', 'Bharat Mata Ki Jai' and 'Welcome Modi', Indian-Americans started arriving at the venue since early in the morning. People were seen waiting in long queues. By 9 pm a large number of people were dressed in Modi T-shirt with portrait of Modi on it. Many were holding banners and slogans like 'America Loves Modi'.

Some 20,000 people packed the Madison Square Garden for the largest event of its kind for the Indian-American community organised by the recently formed Indian-American Community Foundation, and supported by more than 400 Indian-American organisers from across the country. "He is a rock star," said young college going Deepa Kaur. "We have a lot of expectations from him," she said. Never seen before, the organisers had lined up a number of cultural events including popular songs, folk dances. People were seen dancing to the tune of these cultural events. More than 200 media, a significantly large number of them from India, had registered for the event; which organisers said is unprecedented for an Indian American event.

"He is the first Prime Minister who is connected to the NRI (non-resident Indian community). That's why you see such a large number of people. We filled up the seats in just two weeks. It has never happened in the history of the Madison Square Garden that seats gets filled up some three weeks before the event," said Anil Sharma, one of the volunteers of the event. In fact, more than 2,000 volunteers worked day and night for the past three weeks to make he programme a success. "It's Modi mania," said Ankit Patel. "It's a lifetime event," he said.

In fact, the event attracted some three dozen Congressmen including several power lawmakers like Senator Robert Menendez, Chairman of the Senate Foreign Relations Committee; Congressman Ed Royce, Chairman of the House Foreign Relations Committee, and Congressman Ami Bera. South Carolina Governor Nikki Haley, Assistant Secretary of State for South and Central Asia Nisha Desai Biswal were also present. A huge contingent of Indian-American corporate leaders and IT professionals came in from the Silicon Valley for the mega event.

The New York Times in a headline 'Indian Leader Narendra Modi, Once Unwelcome in US gets a Rock Star Reception' story wrote Modi will receive a rally fit for a rock star. Modi's fans were seen carrying the Indian tricolour and wore traditional Indian garb with several groups of performers carrying drums and 'dhols' to give him a rousing welcome. There was also a group of Tibetan women carrying banners in support of Modi. Strict security arrangements are in place with police barricades at several locations. There was also a large group of anti-Modi protesters who had gathered outside the garden shouting slogans against the Prime Minister. They carrying banners reading "Modi -- visa still denied", "Wanted Narendra Modi for crimes against humanity", "India must end oppression of minorities", "Hindutva will destroy India" -- led by the Alliance for Justice and Accountability.

Robindra Deb, an anti-Modi protester said, "We have gathered outside Madison Square Garden to remind the people of what happened in 2002 (Gujarat riots) under Modi's governance. Modi needs to be held accountable. Not the entire Indian American community supports him". Besides the main venue, there were at least 50 other locations across the country where special arrangements had been made for the live telecast of the Prime Minister's speech and other events that include a nearly two-hour-long entertainment programme. At 16.4 per cent, Indian-Americans are the third largest Asian-American group in the US, numbering 2.8 million strong, which is almost 1 per cent of the US population.■

- PTI

US CONGRESSMEN CONNECT WITH MODI'S 'SMALL MAN SELLING TEA' SPIEL

Prime Minister Narendra Modi not only won the hearts of NRIs in the US, but also of nearly 40 top US lawmakers who described his words as "inspirational and visionary".

During his speech at the Madison Square Garden, attended by nearly 40 top lawmakers, the Congressmen immediately connected with Modi when he said he was a small man who reached here "selling tea" but intended to do "big things for small people". Many described him as "charismatic" figure, while others felt he was "destined to transform the nation". His views on minimum governance also went quite well with the lawmakers.

"I see now why the people of India elected him," said Congressman Henry C 'Hank' Johnson from Georgia said. "He has got a vision. He has a plan to make it happen. Prime Minister Modi just swarmed this place like a rockstar," said Congressman Pete Olson from Texas. Congressman Ami Bera, the only Indian-American lawmaker in the current House of Representatives, described Modi's speech as inspirational and visionary.■

Modi remains strong at the Centre and continues to accrue strength to himself. Shah's power was always derived directly from Modi.

When There Is A BJP PM In New Delhi, Party Is Run By Nobodies

GROUND REALITIES TELL THEIR OWN STORY

No BJP president is powerful when the party is in power. Amit Shah is completely dependent on Narendra Modi's clout. He has a protective political immunity and everyone knows its source, says Bharat Bhushan...

Altogether too much has been read into the reverses suffered by the Bharatiya Janata Party in the by-elections in the three crucial States of Uttar Pradesh, Rajasthan and Gujarat, where it lost 13 out of the 24 State assembly seats that it had held. Coming as they did after somewhat similar defeats in the assembly by-elections in Uttarakhand, Bihar, Karnataka and Madhya Pradesh, these electoral losses have been seen as an indication of voters turning away from the politics of communal polarisation, declining appeal of Narendra Modi and the weakening of his favoured apparatchik, party president Amit Shah. A detailed analysis suggests that this conclusion may be far-fetched.

In UP, the atmosphere was heated up through deliberate incidents of communal violence and by extremely provocative statements by Bharatiya Janata Party leaders like Adityanath. Improbable ideas of so-called "love jihad" were spun out, suggesting that Muslim youngsters were being incentivised to elope with Hindu girls. Even the normally sober Maneka Gandhi joined in by fanning emotions over beef exports, calling it "pink jihad".

These statements, however, contributed more to Muslim consolidation behind the Samajwadi Party, than of the Hindu vote with the BJP. Western UP, which saw more than 250 cases of communal violence in the first 71 days of the Modi Government, had the SP wresting the Thakurdwara seat from the BJP by fielding a Muslim candidate. This is the area in Moradabad where Hindus and Muslims had clashed over a loudspeaker in a temple. In Saharanpur Nagar constituency - with its 40 per cent Muslim electorate -- the communal polarisation helped both the BJP, which won, and the SP, which came a close second up from fourth position in the 2012 assembly election.

In the Terai region, which saw 29 communal clashes since Modi came to power, the SP wrested the two seats from the BJP. In Central UP, with 43 communal incidents, the BJP was able to retain the Lucknow East seat largely because the Shias supported veteran local BJP leader Lalji Tandon's son Ashutosh Tandon. In Bundelkhand, with six communal incidents and Eastern UP with 16 incidents in the same period, the SP wrested all four by-election seats from the BJP and its ally, the Apna Dal. The SP win in the Mainpuri Lok Sabha by-election was predictable since it is Mulayam Singh Yadav's family seat.

The absence of the Bahujan Samaj Party from the contest helped consolidate Muslims behind the SP and may have also possibly brought it some Dalit votes. However, with some of the most retrograde Muslim leaders in its ranks, the SP cannot be termed secular. It has been argued that had the BJP projected a development plank in UP rather than its communal face, its performance might have been better. But without a majority in the State assembly and a Government in Lucknow, its promises would not be credible. So, it chose communalisation instead.

In Rajasthan, the Congress victory in three out of four seats is explained by internal factionalism in the BJP. There are elements in the party who want to replace Chief Minister Vasundhara Raje with State party president Om Mathur. Having overseen two assembly elections as general secretary incharge of the BJP in Gujarat during Modi's tenure, Mathur is close to him. Today, Raje is not being allowed to expand her 11-member council of ministers, which is the smallest for any State and less than the constitutionally mandated strength despite a two-thirds majority in the State assembly. Nor has she been able to sack party MP Sanwar Lal Jat as her water resources minister. He had resigned from his Nasirabad assembly seat, is a Lok Sabha MP but is still a minister in Rajasthan. The Nasirabad seat went to the Congress in the by-poll.

Raje also refused to heed the advice of Jat, Santosh Ahlawat and Bahadur Singh Koli on their replacements, when they vacated the Nasirabad, Surajgarh and Weir assembly seats, respectively, to contest the national elections. It is believed that the local MPs actively worked against Raje's candidates. The only candidate of Raje who managed a win stood from Kota South, which is in her traditional area of influence. In Rajasthan, too, the Congress victory, therefore, was a circumstantial one and not a vote for secularism.

In Gujarat, the three seats that the Congress wrested from the BJP out of nine in the by-polls, is certainly a morale booster for the party. However, there is little to suggest that this represents disenchantment with Modi or the beginning of the BJP's decline in Gujarat. It may represent nothing more than its overconfidence and euphoria arising from the Lok Sabha sweep of all the 26 seats in the State.

It cannot be anybody's case that these by-election results presage what will happen in the 2019 general elections or in the impending State Assembly elections. Therefore, this is neither the beginning of the decline of Modi and Shah nor the dawning of a secular summer just yet. Modi remains strong at the Centre and continues to accrue strength to himself. There are no factions opposed to him either within the Cabinet or the party who stand to gain by blaming him for the by-election results.

Shah's power was always derived directly from Modi. Nobody is questioning him over the by-poll defeat nor is there any exercise to chastise him. The lowest point of Shah's presidency is yet to come. In any case, no BJP president is powerful when the party is in power. When there is a BJP Prime Minister in New Delhi, the party is either run by nobodies such as Jana Krishnamurthy, Bangaru Laxman and Venkaiah Naidu or by those who are reduced to insignificance like Kushabhau Thakre. Out on bail on three murder charges, Shah is completely dependent on Modi's clout. He has a protective political immunity and everyone knows its source. Ground realities, therefore, suggest that there is little reason to term the by-election results a victory for secularism and a defeat for hate-politics.■

-BS

Secular Arithmetic Goes Against BJP

DECODING THE BY-ELECTIONS

There are two major takeaways from the by-election results. One, a majority or Indians and Hindus have reasserted their secular credentials. The second, equally momentous, is the sure-footedness and quick response time of the Indian electorate, says Subir Roy...

The severe setback that the Bharatiya Janata Party has suffered in last month's by-elections to over half a dozen State assemblies (it made a single gain each in West Bengal and Assam) between three and five months after a dramatic victory in the general elections calls for intensive decoding. Done correctly, this can yield valuable insights into how the mind of the Indian electorate is working today. First, there has been no major setback for the BJP, now at the helm of national affairs, in the last few months. So the results cannot be a backlash against something that had taken place. On the contrary, Prime Minister Narendra Modi's connection with the electorate, apparent from the reception to his Independence Day and Teachers' Day speeches, seems to be quite intact. True, inflation, which always moves voters, is still running unconscionably high. But it is doubtful if people have formed a final verdict on the BJP Government's ability to tackle it in less than six months and are meting out punishment for it.

BJP leaders have sought to distance Modi from the defeats by pointing out that he did not personally campaign and asserted that his personal popularity remains intact. In fact, after the verdicts came, party men have themselves pointed to the poor state of the party in Bihar and Uttar Pradesh in particular, demotivated by infighting and disaffection over distribution of tickets. The point is that it cannot be a very good omen for the future of the party if it sinks without hand-holding from Modi, particularly when it has already pushed itself into the background while projecting him as the prime ministerial candidate.

So what went wrong for the BJP -- or what did the opposition get right? In Bihar and UP it is arithmetic. The BJP swept UP and Bihar in the parliamentary elections in good part because of multi-cornered contests splitting voters. Seeing this, sworn enemies Lalu Prasad and Nitish Kumar joined forces in Bihar, to the accompaniment of mild ridicule not just from the BJP but the media, too. Surely, the voter would see through this marriage of convenience. The voter saw it and loved it.

The popular vote of the Janata Dal (United)-Rashtriya Janata Dal-Congress combine ratcheted up 4.6 per cent and that of the BJP fell sharply by eight per cent! A similar phenomenon was seen in UP where Mayawati kept her Bahujan Samaj Party, which had secured 19.6 per cent of the popular vote in the Lok Sabha elections, out of the by-elections. Thus, a good part of the Dalit vote went by default to the Samajwadi Party. A similar polarisation and consolidation in favour of the Congress took place in Rajasthan and Gujarat.

There is an even greater and, in fact, historic significance in the UP vote. Modi's lieutenant, Amit Shah, had relocated to UP from before the parliamentary elections to oversee the tone, tenor and management of the elections there. For the assembly by-elections, the BJP ran a brazenly communal and divisive campaign, making an enormous issue of 'love jihad' and getting its member of Parliament Yogi Adityanath

to deliver a string of hate speeches. The aim was to unite the traditionally splintered Hindu vote in favour of the BJP. And the voter slapped it in the face and gave the Samajwadi Party, discredited for its incompetent rule of UP, a massive leg-up.

The three general elections -- 1998, 1999 and 2014 -- in which the BJP has emerged upfront have seen an accretion to its popular base beyond a core section of upper-caste Hindus. Atal Bihari Vajpayee made it a broad-based, centrist party that underplayed the Hindutva agenda. For the parliamentary elections, Modi concentrated on Congress misrule and promised development. Emboldened by the victory, Modi and the BJP went ahead flying the Hindutva jhanda high for the assembly by-elections. And we have seen how the electorate has responded to this.

There are two major takeaways from the by-election results. One, a majority or Indians and Hindus have reasserted their secular credentials. So Modi has had to shift course and certify the patriotism of Indian Muslims just before leaving for the United States, for the benefit of both the Indian and American audience. The second, equally momentous, is the sure-footedness and quick response time of the Indian electorate. Having sent one signal in April, it decided to send a fresh corrective signal in July to September. What is more -- and this is pure conjecture -- the electorate may have realised that the BJP had secured a massive mandate by default, courtesy vote-splitting. So in the by-elections it went ahead and undid a part of the mandate. If it is presumptuous to read the mind of the Indian voter beyond a point -- but even if we cannot -- then she at least gets credit for being highly inscrutable.■

-BS

> The condition of housing in most cities — be it slum or otherwise — has deteriorated. The reality is that housing in urban areas is not cheap and land is always in short supply.

Housing For All

AN UPHILL BATTLE

WHILE THE POPULATION HAS RISEN THROUGHOUT THE COUNTRY, IN URBAN AREAS, DRIVEN BY MIGRATION AND HIGHER FERTILITY, THE GROWTH HAS BEEN CLOSE TO DOUBLE THE OVERALL NATIONAL RATE. THIS HAS LED TO MORE PEOPLE ENDING UP HOMELESS IN URBAN INDIA...

Prachi Salve

Housing in India is a growing concern, not just for citizens but also for planners. Little wonder that Prime Minister Narendra Modi touched upon the subject in his very first address to the Lok Sabha after taking charge — he spoke about the need for all stakeholders to pitch in to ensure housing for all by 2022. While the population has risen throughout the country, in urban areas, driven by migration and higher fertility, the growth has been close to double the overall national rate. This has led to more people ending up homeless in urban India.

Again, even as the homeless population shot up 20.5 per cent in urban areas, the figure for the country as a whole and for rural areas dropped 8.8 per cent and 28 per cent, respectively. Population growth and homelessness have pushed up slum numbers in the country from 2001 to 2011. In 2011, of the total 4,041 statutory towns, 2,613 had slums — a 50 per cent surge over a decade. Simultaneously, the condition of housing in most cities — be it slum or otherwise — has deteriorated. The Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (MHUPA) released a report in March 2012 on housing poverty, highlighting the poor condition of India's overall housing stock. Housing poverty was defined as the total number of families residing in unacceptable (old and dilapidated) houses, families residing in unacceptable physical and social conditions, and families without homes. The total housing shortage in urban India, as of March 2012, is estimated at 1.87 crore, says the report.

Interestingly, more self-owned houses are in worse condition than rented ones. In other words, more families are living in non-serviceable and/or congested homes. The Government — through schemes started by the Ministry of Urban Development and the MHUPA — has continued efforts to provide better and affordable housing, especially to the urban poor. Let us look at the total budget for these Ministries and money allocated to housing.

There has been an increase in allocation to housing as a percentage of the total budget, with almost 19 per cent dedicated to housing, combining the two Ministries. Some of the schemes in place to address the issue of urban housing are:

BSUP: Basic Services for Urban Poor was planned to ensure provision of basic infrastructure services to the urban poor at affordable rates. The duration of the mission was seven years and it was launched in 2005 under JNNURM. The mission is being carried out in 65 selected cities. The central assistance has been given in the form of additional conditional assistance (ACA). Beneficiaries contribute 12 per cent for houses while for SC/ST/BC/OBC/PH and other weaker sections, the figure is 10 per cent. More than 10 lakh housing projects have been sanctioned under BSUP, out of which 3.6 lakh have been completed — a completion rate of only 36 per cent. There are 2.2 lakh dwelling projects under development. The highest number of projects have been allotted to West Bengal (1.6 lakh), followed by Maharashtra (1.5 lakh) and Andhra Pradesh (1.4 lakh). Fund allocation for BSUP is Rs 16,356 crore, out of which central assistance is Rs 14,805 crore. ACA of Rs 22,116.28 crore has been released, out of which Rs 11, 448 crore has been utilised. The best performers in terms of project completion are Tripura (100 per cent), Haryana (87.5 per cent) and Gujarat (72.5 per cent).

IHSDP: The Integrated Housing and Slum Development Programme was designed for slum improvement and rehabilitation for smaller towns/ cities under JNNURM. The central assistance, in general, is 80 per cent while for special category states it is 90 per cent. Beneficiaries contribute 12 per cent for houses while for SC/ST/BC/OBC/PH and other weaker sections, the figure is 10 per cent.The best performer in terms of project completion is Daman and Diu (87.5 per cent with 14 out 16 projects completed), followed by Karnataka (84 per cent).

The total fund allocated is Rs 6,828 crore. Of the Rs 4,320 crore releaswed as additional central assistance, Rs 1,225 crore has been utilised. The number of projects completed is 4.3 lakh units out of the total approved 5.7 lakh units — a completion rate of 75.6 per cent. Only 4 per cent of projects were completed under BSUP and 30 per cent under IHSDP. A key reason for the weak performance of both the programmes is land acquisition, especially in cities. Another issue is the difficulty in preparing detailed project reports and identification of beneficiaries. This leads to resistance from beneficiaries during project execution. Although BSUP and IHSDP stirred some interest, they could not facilitate the granting of legal property rights to the urban poor. Property or ownership rights, most economists and social scientists agree, are important steps in empowerment and urban poverty alleviation. A new programme — Rajiv Awas Yojana (RAY) — hoped to address this issue.

RAY provided credit to poor urban households to build their own home. In 2008, RAY was brought under Rajiv Rinn Yojana (RRY). The IHSDP was launched by the housing Ministry on 26 December 2008. An interest subsidy of 5 per cent per annum for the entire duration of the loan (15-20 years) is provided for loans up to Rs 1 lakh for EWS/LIG beneficiaries. The scheme is being implemented through banks and housing finance companies. After a lukewarm response, ISHDP was relaunched as RRY in September 2013.

A National Housing Bank report says an important reason why credit schemes have not worked well is the fundamental flaw in the assumption that the poor have access to land and need only financial support to build their homes. The reality is that housing in urban areas is not cheap and land is always in short supply. The report says that state-level housing boards must improve their capacity to fully utilise the available funds and deliver more houses.

The Modi Government had promised in its manifesto to tackle the problem of urban housing by creating 'smart cities'. In the 2014-15 Budget, Finance Minister Arun Jaitley set aside Rs 7,060 crore to develop 100 smart cities. So far, master planning of three new smart cities in the Chennai-Bengaluru Industrial Corridor region, namely, Ponneri in Tamil Nadu, Krishnapatnam in Andhra Pradesh and Tumkur in Karnataka, is to be completed on a pilot basis.

Most policies of the previous Government focused either on building houses for the poor or offering them credit to do so. Both failed on one crucial aspect — land. Any future policy needs to focus on land acquisition as this tends to be one of the major impediments to any housing or infrastructure project. There is also the need to keep in mind who the poor are and what their housing needs are. All the stakeholders need to be part of urban planning.■

- Business World